अपने दुश्मनों पर विजय पाने वाले की तुलना में मैं उसे शूरवीर मानता हूं, जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त की, क्योंकि सबसे कठिन जीत अपने आप पर विजय पाना है।

- अरस्तू

आतंक का साया

पंजाब में पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां जिस तरह से बढ़ रही हैं, वह बड़े खतरे की ओर इशारा करती हैं। बीते दस दिनों के भीतर राज्य में तीन बम धमाकों ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। अब तक की जांच-पड़ताल के निष्कर्षों की जो तस्वीर सामने आई है, उससे इस बात के साफ संकेत मिलते है कि उग्रवाद का कठिन दौर झेल चुके इस राज्य में खालिस्तान समर्थक आतंकी तंत्र फिर से सिर उठाने लगा है। जलंधर और अमृतसर में मंगलवार रात हुए दो सिलसिलेवार धमाकों ने राज्य की सुरक्षा एजंसियों की सतर्कता और खुफिया चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन विस्फोटों की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों जगह सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। आतंक के इस तंत्र को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि विभिन्न समूहों से जुड़े ज्यादातर आतंकी किसी आम नागरिक की तरह समाज में घुल-मिलकर रहते हैं, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल होता है। मौका मिलने पर वे अपने आकाओं के निर्देश पर हमला करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं।

गौरतलब है कि पंजाब के जलंधर में मंगलवार रात करीब आठ बजे सीमा सुरक्षा बल के पंजाब फ्रंटियर के मुख्यालय के बाहर विस्फोट हुआ। इसके बाद दूसरा धमाका रात करीब ग्यारह बजे अमृतसर में सैन्य छावनी के पास हुआ। जलंधर में हुए विस्फोट की जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है और पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है। इससे पहले पटियाला के शंभू इलाके में 27 अप्रैल को एक मालगाड़ी की पटरी पर विस्फोट हुआ था। पुलिस ने इस सिलसिले में खालिस्तान समर्थक एक आतंकी गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया था। ये घटनाएं खुफिया तंत्र की विफलता और सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामी की ओर इशारा करती है। राज्य पुलिस का मानना है कि इन आतंकी वारदातों के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजंसी आइएसआइ का हाथ है। सीमा पार से खालिस्तान समर्थक आतंकी समूहों को प्रशिक्षण, विस्फोटक सामग्री और हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। मगर सवाल है कि सुरक्षा एजंसियां इस तरह की गतिविधियों पर नियमित नजर रखने और किसी भी वारदात से पहले ही आतंकियों को धर-दबोचने में नाकाम क्यों हो रही हैं?

पुलिस के मुताबिक, अमृतसर में विस्फोट स्थल पर आइईडी के टुकड़े मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि यह या तो टाइम बम से किया गया विस्फोट था या फिर रिमोट कंट्रोल से धमाका किया गया। ऐसे में सुरक्षा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। अगर सुरक्षाबलों के परिसर में ही चौकसी के बंदोबस्त इतने कमजोर हैं कि कोई भी वहां विस्फोटक सामग्री रख सकता है, तो फिर अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था का स्तर कैसा होगा, इसका अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। पंजाब में आतंकी तंत्र के फैलते दायरे का अंदाजा इससे लगाया जा सकता कि पिछले वर्ष जुलाई में सुरक्षा एजंसियों ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल के तीन आतंकियों को गिरफ्तार किया था। इसके करीब तीन माह बाद ग्रेनेड हमले की साजिश में दस संदिग्धों को पकड़ा गया। इससे स्पष्ट है कि उग्रवाद के खात्मे के बाद शांति और समृद्धि की राह पर लौटे इस राज्य में आतंक का खतरा फिर से बढ़ता जा रहा है। अगर समय रहते स्थिति को नहीं संभाला गया, तो निस्संदेह राज्य में हालात फिर से बिगड़ सकते हैं।

लापरवाही का दायरा

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आस-पास के क्षेत्र में खुले नाले एवं पानी से भरे गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। हाल के दिनों में एक के बाद एक हादसों के बावजूद शासन-प्रशासन के स्तर पर एहतियाती उपायों को लेकर कोई गंभीर प्रयास होते नजर नहीं आ रहे हैं। इसी लापरवाही के कारण दिल्ली के मुकुंदपुर इलाके में पिछले दिनों खुले नाले में गिरने से एक मासूम बच्ची की जान चली गई। इस मामले में सरकार की ओर से सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग में अनुबंध पर कार्यरत एक कनिष्ठ अभियंता को नौकरी से निकाल दिया गया। मगर सवाल है कि क्या निचले स्तर के कर्मियों पर इस तरह की कार्रवाई से व्यवस्था में सुधार हो पाएगा? इसमें दोराय नहीं कि नागरिकों की सुरक्षा और खासकर बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। मगर कर्तव्य में लापरवाही बरते जाने के मामलों में क्या संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय नहीं की जानी चाहिए! जब उच्चाधिकारी ही जन समस्याओं के समाधान पर ध्यान नहीं देंगे, तो निचले कर्मियों से क्या उम्मीद की जा सकती है।

यह अक्सर देखने में आता है कि इस तरह के मामलों में या तो जिम्मेदारी ठेकेदारों पर डाल दी जाती है या फिर कार्रवाई के नाम पर निचले कर्मचारियों को निलंबित कर मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। मुकुंदपुर की घटना में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सवाल है कि इस क्षेत्र में खुले नाले को ऊपर से ढकने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ अनुबंध पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंता की ही थी, उच्च अधिकारियों का इससे कोई सरोकार नहीं था? सड़क पर खुदाई के बाद पानी से भरे गड्ढों और नालों को खुला छोड़ देने का जोखिम विभागीय अधिकारियों को नजर क्यों नहीं आता? दिल्ली सरकार का कहना है कि इस तरह की घटनाओं में लापरवाही बरतने पर अब जवाबदेही तय होगी, लेकिन इस बात पर भी गंभीरता से विचार करने की जरूरत है कि जब तक संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद धुंधली ही रहेगी। सरकार को चाहिए कि जलभराव वाली जगहों और खुले नालों की पहचान कर उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों की जान को किसी तरह का खतरा न हो।

श्रम की मांग और प्रवासन का संकट

प्रवासन आज केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक असमानता, बेरोजगारी और नीतिगत विफलताओं का संयुक्त परिणाम बन चुका है। इसके पीछे एक व्यक्ति एवं परिवार, अधूरे सपने और एक टूटती सामाजिक संरचना छिपी होती है।

देवेंद्रराज सुथार

संयुक्त राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन की एक रपट ने विश्व समुदाय का ध्यान एक ऐसे संकट की ओर आकर्षित किया है, जो अक्सर राजनीतिक बहसों और सीमा सुरक्षा की चर्चाओं के पीछे छिप जाता है। रपट के अनुसार, वर्ष 2025 में विश्व के विभिन्न प्रवासन मार्गों पर लगभग 7,900 लोगों की मृत्यु हुई या वे लापता हो गए। इसके साथ ही वर्ष 2014 से अब तक प्रवास के दौरान मारे गए या गायब हुए लोगों की कुल संख्या 80 हजार से अधिक हो चुकी है। यह संख्या केवल उन मामलों की है, जो दर्ज हो सके। वास्तविक स्थिति इससे कहीं अधिक गंभीर है। इन आंकड़ों का अर्थ यह है कि दुनिया भर में हजारों लोग बेहतर जीवन, सुरक्षा या रोजगार की तलाश में ऐसी यात्राएं कर रहे हैं, जिनका अंत अक्सर शोषण या गुमनामी में होता है।

प्रवासन आज केवल लोगों का स्थान परिवर्तन नहीं, बल्कि वैश्विक असमानता, युद्ध, जलवायु संकट, बेरोजगारी और नीतिगत विफलताओं का संयुक्त परिणाम बन चुका है। इसके पीछे एक व्यक्ति, एक परिवार, एक अधूरा सपना और एक टूटती सामाजिक संरचना छिपी होती है। इसलिए प्रवासन के सवाल को केवल कानूनी या अवैध प्रवेश के दायरे में सीमित करना सही नहीं है। इसे मानवीय गरिमा, श्रम अवसरों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक है। यही कारण है कि यह रपट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि विश्व व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है।

प्रवासन मानव सभ्यता के इतिहास जितना पुराना है। लोग सदियों से जल, भूमि, व्यापार, सुरक्षा और अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहे हैं। आधुनिक युग में प्रवासन के स्वरूप अधिक जटिल हो गए हैं। आज इसे व्यापक रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है-आंतरिक प्रवासन और अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। आंतरिक प्रवासन में लोग अपने ही देश के भीतर गांव से शहर, एक राज्य से दूसरे राज्य या पिछड़े क्षेत्र से विकसित क्षेत्र की ओर जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रवासन में लोग दूसरे देशों की सीमाएं पार करते हैं। आर्थिक प्रवासी वे लोग होते हैं, जो बेहतर रोजगार और आय के लिए जाते हैं, जबकि शरणार्थी वे हैं, जो युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़ते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापित होने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है।

आज प्रवासन संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि श्रम की वैश्विक मांग बढ़ी है, लेकिन सुरक्षित गतिशीलता के रास्ते सीमित हुए हैं। अनेक विकसित देशों को श्रमिकों की आवश्यकता है, फिर भी उनकी आव्रजन नीतियां कठोर होती जा रही हैं। वीजा नियमों की जटिलता, सीमित श्रम कोटा, लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव लाखों लोगों को अनियमित मार्गों की ओर धकेलते हैं। यही कारण है कि भूमध्य सागर, सहारा रेगिस्तान, अमेरिका-मेक्सिको सीमा, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जैसे मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में बदल चुके हैं। लोग छोटी और असुरक्षित नौकाओं में समुद्र पार करते हैं, रेगिस्तानों में बिना भोजन-पानी के चलते हैं, जंगलों से गुजरते हैं या मानव तस्करों पर निर्भर होते हैं। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित रहते हैं। यौन हिंसा, जबरन श्रम, फिरौती, अपहरण और मानव तस्करी जैसी घटनाएं लगातार सामने आती हैं। यह संकट केवल अपराधी गिरोहों का परिणाम नहीं, बल्कि उन नीतिगत व्यवस्थाओं का भी नतीजा है, जो सुरक्षित प्रवासन के अवसर उपलब्ध नहीं करातीं। प्रवासन मामले में जब कानूनी रास्ते बंद होते हैं, तो अवैध संजाल फलते-फूलते हैं।

प्रवासन का मानवीय प्रभाव सबसे गहरा और सबसे कम समझा गया आयाम है। किसी प्रवासी की मृत्यु केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती। वह पूरे परिवार की आर्थिक संरचना को तोड़ देती है। अनेक परिवार अपने सदस्य को विदेश भेजने के लिए ऋण लेते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं या जीवन भर की बचत लगा देते हैं। यदि वही व्यक्ति यात्रा में लापता हो जाए या उसकी मौत हो जाए, तो परिवार कर्ज और आर्थिक संकट में डूब जाता है। बच्चों की पढ़ाई छूट सकती है, बुजुर्गों की देखभाल रुक सकती है और परिवार की आय समाप्त हो सकती है। लापता होने की स्थिति और भी पीड़ादायक होती है, क्योंकि परिजन वर्षों तक प्रतीक्षा करते रहते हैं। महिलाओं पर इसका बोझ अधिक पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठानी पड़ती है।

> **आज प्रवासन के संकट की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि श्रम की वैश्विक मांग बढ़ी है, लेकिन सुरक्षित गतिशीलता के रास्ते सीमित हुए हैं। अनेक विकसित देशों को श्रमिकों की आवश्यकता है, फिर भी उनकी आव्रजन नीतियां कठोर होती जा रही हैं। वीजा नियमों की जटिलता, सीमित श्रम कोटा, लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया और राजनीतिक दबाव लाखों लोगों को अनियमित मार्गों की ओर धकेलते हैं। यही कारण है कि भूमध्य सागर, सहारा रेगिस्तान, अमेरिका-मेक्सिको सीमा, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर जैसे मार्ग दुनिया के सबसे खतरनाक रास्तों में बदल चुके हैं।**

प्रवासी महिलाओं की स्थिति और भी जटिल होती है। घरेलू काम, देखभाल सेवा या अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को कम वेतन, लंबा कार्य समय, यौन उत्पीड़न और कानूनी सुरक्षा की कमी का सामना करना पड़ता है। अकेले यात्रा करने वाले नाबालिगों की संख्या बढ़ रही है, जो शोषण और तस्करी के जोखिम में रहते हैं। गंतव्य देशों में भी प्रवासी समुदाय कई बार नस्लीय भेदभाव, सामाजिक अलगाव, भाषा बाधा और असुरक्षित रोजगार का सामना करते हैं। दूसरी ओर अचानक बड़ी संख्या में शरणार्थियों या प्रवासियों के आगमन से स्थानीय समाजों में संसाधनों पर दबाव, सांस्कृतिक तनाव और राजनीतिक प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हो सकती है।

भारत के लिए प्रवासन का विषय विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि यह एक साथ श्रम भेजने वाला, कुशल पेशेवर उपलब्ध कराने वाला और आंतरिक प्रवासन से प्रभावित देश है। विदेश में बसे भारतीयों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक मानी जाती है और वे हर वर्ष बड़ी राशि अपने देश भेजते हैं। यह धन ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च को बढ़ावा देता है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को सशक्त करता है। अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भारतीय पेशेवर विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा और उद्यमिता में योगदान दे रहे हैं। वहीं खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय श्रमिक निर्माण, परिवहन, घरेलू सेवा और श्रम-प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन श्रमिकों को कई बार पासपोर्ट जब्ती, वेतन बकाया, दुर्घटनाएं और कठिन कार्य परिस्थितियों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत सरकार ने ई-माइग्रेट पोर्टल, प्रवासी बीमा योजना, दूतावास सहायता तंत्र और कौशल प्रशिक्षण जैसे कदम उठाए हैं, पर इनकी पहुंच और प्रभावशीलता बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत के लिए प्रवासन केवल आर्थिक अवसर नहीं, बल्कि नागरिक संरक्षण और श्रम गरिमा का विषय भी है।

वैश्विक राजनीति में प्रवासन आज सबसे संवेदनशील मुद्दों में से एक है। अनेक देशों में चुनावी राजनीति प्रवासियों के प्रश्न पर केंद्रित होती जा रही है। कहीं इसे बेरोजगारी से जोड़ा जाता है, कहीं अपराध से, तो कहीं सांस्कृतिक पहचान के संकट के रूप में पेश किया जाता है। परिणामस्वरूप प्रवासी विरोधी भावनाएं, राष्ट्रवादी राजनीति और कठोर सीमा नीतियां मजबूत हुई हैं, परंतु वास्तविकता अधिक जटिल है। कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, बुजुर्गों की देखभाल और आतिथ्य क्षेत्रों में प्रवासी श्रमिकों पर निर्भर है। यदि श्रम प्रवाह रुक जाए, तो इन क्षेत्रों में गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। इस सबके बीच जलवायु परिवर्तन भविष्य में प्रवासन को और तीव्र करेगा। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि से तटीय आबादी विस्थापित होगी, सूखे से कृषि संकट गहराएगा, बाढ़ और चक्रवातों से आजीविका नष्ट होगी। छोटे द्वीपीय देशों, अफ्रीका के शुष्क क्षेत्रों और दक्षिण एशिया के तटीय इलाकों में यह चुनौती विशेष रूप से गंभीर है। आने वाले दशकों में प्रवासन को केवल सुरक्षा समस्या के रूप में ही देखा जाना सही नहीं होगा। इसके समाधान के लिए बहुस्तरीय दृष्टिकोण अपनाना होगा।

आत्मविश्वास के आयाम

ममता कुशवाहा

मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह अपने भीतर असीम संभावनाओं का भंडार होते हुए भी भय और संदेह के जाल में उलझकर स्वयं को सीमित कर लेता है। जबकि सत्य यह है कि सफलता किसी बाहरी चमत्कार का परिणाम नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर पलने वाले विचारों, भावनाओं और संकल्पों की स्वाभाविक परिणति है। जो व्यक्ति अपने भय से ऊपर उठकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का साहस जुटा लेता है, वही जीवन की ऊंचाइयों को छूने में समर्थ होता है।

भय मनुष्य का सबसे पुराना साथी है। यह कभी असफलता का भय बनकर सामने आता है, तो कभी समाज की आलोचना का। कभी यह भविष्य की अनिश्चितता का रूप ले लेता है, तो कभी अतीत की असफलताओं की छाया बनकर हमारे वर्तमान को जकड़ लेता है। भय का स्वभाव ही ऐसा है कि यह हमारे मन में संदेह को जन्म देता है और संदेह धीरे-धीरे आत्मविश्वास को क्षीण करता चला जाता है। जब मन में यह प्रश्न उठने लगता है कि क्या मैं यह कर पाऊंगा, तभी हमारी हार का आरंभ हो जाता है। मगर जीवन की दिशा वही व्यक्ति बदलता है, जो इस प्रश्न को चुनौती में बदल देता है। वह कहता है कि मैं अवश्य करूंगा। यही आत्मविश्वास का स्वर है, जो भीतर की सुप्त शक्तियों को जागृत करता है। आत्मविश्वास केवल एक भावना नहीं, बल्कि एक जीवंत ऊर्जा है, जो मनुष्य को उसके लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर करती है। जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है, तब वह परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता, बल्कि उन्हें अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है।

हमारा मन एक उर्वर भूमि के समान है, जिसमें हम जो भी बीज बोते हैं, वही फलित होता है। अगर हम इसमें भय, नकारात्मकता और संदेह के बीज बोते हैं, तो परिणामस्वरूप निराशा, असफलता और असंतोष की फसल उगती है। इसके विपरीत यदि हम अपने मन में साहस, आशा और श्रेष्ठ लक्ष्य के विचारों को स्थिर रखते हैं, तो यही विचार हमारे व्यक्तित्व को निखारते हैं और हमें सफलता के पथ पर अग्रसर करते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है, धीरे-धीरे वैसा ही बनता जाता है, यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का अटल सत्य है। हम अपने दैनिक जीवन में इस सत्य को सहज ही अनुभव कर सकते हैं। जब हम किसी कार्य को आरंभ करने से पहले ही यह मान लेते हैं कि यह कठिन है, यह मेरे बस का नहीं, तब हमारी ऊर्जा उसी क्षण क्षीण हो जाती है। इसके विपरीत जब हम सकारात्मक दृष्टि के साथ यह सोचते हैं कि 'यह संभव है, और मैं इसे कर सकता हूं,' तब हमारे भीतर एक नई शक्ति का संचार होता है। यही सकारात्मक दृष्टिकोण हमें कठिनाइयों में भी अवसर देखने की दृष्टि देता है। सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों को नकार दें या उनसे आंखें मूंद लें, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हम उन कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए भी अपने मन को आशा और साहस से भरा रखें।

जीवन में उतार-चढ़ाव तो आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संतुलित और दृढ़ बनाए रखता है, वही विजयी होता है। सकारात्मक सोच हमें यह सिखाती है कि हर अंधकार के बाद प्रकाश अवश्य आता है और हर संघर्ष के पीछे एक नई संभावना छिपी होती है। दृढ़ संकल्प इस पूरी प्रक्रिया का आधार है। केवल सकारात्मक सोच ही पर्याप्त नहीं होती, जब तक उसके साथ अटल संकल्प का संयोग न हो। संकल्प वह शक्ति है, जो हमें निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो। यह हमें गिरकर फिर उठने की प्रेरणा देता है और असफलताओं को सफलता की सीढ़ी में परिवर्तित कर देता है। जिस व्यक्ति के भीतर दृढ़ संकल्प होता है, वह बाधाओं को अपने मार्ग का अवरोध नहीं, बल्कि अपनी शक्ति की परीक्षा मानता है।

आंतरिक शक्ति का जागरण भी इसी प्रक्रिया का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जब हम अपने भीतर के भय और संदेह को त्यागकर आत्मविश्वास और सकारात्मकता को अपनाते हैं, तब हमारी आंतरिक शक्ति स्वतः जागृत होने लगती है। यह शक्ति हमें बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रखती है। यही आंतरिक शक्ति हमें विश्वास दिलाती है कि हम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं और हमारी दिशा अपने हाथों में है। आज के प्रतिस्पर्धात्मक और तनावपूर्ण जीवन में यह विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है। जब चारों ओर तुलना, आलोचना और अनिश्चितता का वातावरण हो, तब अपने भीतर विश्वास बनाए रखना चुनौती बन जाता है। मगर यही वह समय होता है, जब हमें अपने मन को सशक्त बनाना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि दूसरों की राय हमारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। हमारा आत्मविश्वास ही हमारी वास्तविक पहचान होती है।

इस बात की जरूरत है कि हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से पोषित करें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और संकल्प को दृढ़ बनाए रखें। भय और संदेह को अपने ऊपर हावी न होने दें, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बनाएं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हैं, तब कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वास्तव में सफलता उसी के कदम चूमती है, जो अपने मन की सीमाओं को तोड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जो अपने विचारों को सकारात्मकता से भरकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयत्नशील रहता है। जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारी सोच ही हमारा पथप्रदर्शक है। अगर यह सोच साहस, आशा और दृढ़ संकल्प से परिपूर्ण हो, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता।

दुनिया मेरे आगे

> **सकारात्मकता का अर्थ यह नहीं है कि हम जीवन की कठिनाइयों को नकार दें, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ यह है कि हम उन कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए अपने मन को आशा एवं साहस से भरा रखें। जीवन में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में खुद को संतुलित और दृढ़ बनाए रखता है, वही विजयी होता है।**

प्रकृति का दोहन

जल, जंगल और जमीन, प्रकृति के ये तीनों आधार स्तंभ समस्त जीव-जगत के जीवन की धुरी हैं। विडंबना यह है कि आधुनिक और शिक्षित मानव ने कथित विकास की अंधी दौड़ में इन्हीं आधारों का अंधाधुंध दोहन किया है। जंगलों को उजाड़ कर विकास की झूठी तस्वीर बनाई जा रही है। इसके दुष्परिणाम अब सामने आने लगे हैं। पूरी दुनिया भीषण तापमान वृद्धि का सामना कर रही है। चौंकाने वाला तथ्य यह है कि हर मिनट लगभग ग्यारह फुटबाल मैदान के बराबर जंगल नष्ट किए जा रहे हैं। यह आंकड़ा भले ही अविश्वसनीय लगे, लेकिन यही आज की कठोर सच्चाई है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक रपट के अनुसार, प्रतिवर्ष लगभग 43 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल समाप्त हो जाते हैं, जो कि डेनमार्क जैसे देश के बराबर क्षेत्रफल है। यह आंकड़ा न केवल चिंताजनक है, बल्कि पूरी मानवता के लिए चेतावनी भी है। वर्ष 2021 में आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलन में सौ से अधिक देशों ने वनों की कटाई पर रोक लगाने का संकल्प लिया था। दुर्भाग्यवश, इस संकल्प को गिने-चुने देशों ने ही गंभीरता से निभाया। नतीजा यह कि प्रकृति का संतुलन लगातार बिगड़ता जा रहा है।

- अरविंद रावल, झाबुआ

प्रशासनिक विफलता

'लापरवाही की कीमत' (संपादकीय, 2 मई) पढ़ा। मध्यप्रदेश के बरगी बांध में क्रूज नौका दुर्घटना केवल एक हादसा नहीं, बल्कि प्रशासनिक अव्यवस्था और लापरवाही का वह दस्तावेज है, जिसे हर बार जांच की फाइल में दफना दिया जाता है। यह दुर्घटना हमें बताती है कि हमारे यहां इस तरह के हादसे अचानक नहीं होते, वे धीरे-धीरे व्यवस्था की उदासीनता में पकते हैं और फिर किसी दिन जानलेवा रूप लेकर सामने आ जाते हैं। सबसे दुखद यह है कि ऐसे हादसों के बाद संवेदनाओं के स्वर तो बहुत निकलते हैं, पर जिम्मेदारी कहीं नहीं दिखती। सुरक्षा मानकों की अनदेखी, नावों पर क्षमता से अधिक सवारी, जीवनरक्षक जैकेट की अनुपलब्धता, मौसम की चेतावनी की उपेक्षा और नियमित निरीक्षण का अभाव, ये सभी प्रशासनिक विफलता हैं। सवाल यह नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह है कि इसे रोका क्यों नहीं गया? हमारा प्रशासन अक्सर तब जागता है, जब घटना हो चुकी होती है।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

अकेले पड़ते बुजुर्ग

'उपेक्षा का दंश झेलते बुजुर्ग' (आलेख, 4 मई) पढ़ा। यह एक गंभीर मुद्दा है। परिवार में आजकल जिस तरह बुजुर्गों की उपेक्षा होती है, वह वास्तव में दुखद है। जिन माता-पिता ने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए लगा दी, बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है या वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है। हमारे देश में ऐसे कई बुजुर्ग दंपति हैं, जिनके बेटे विदेश में हैं और वे फोन कर पूछते भी नहीं कि उनकी क्या हालत है। उन्हें पैसे की जरूरत तो नहीं। यह कोई एक घर की बात नहीं, बल्कि कई परिवारों में यह देखा जा रहा है। देश में बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उनकी मदद के लिए कानून बने हैं, लेकिन सिर्फ कागजों पर। उन्हें गंभीरता से लागू नहीं किया जाता। बुजुर्गों के लिए भरण-पोषण कानून है, लेकिन उस पर अमल कम ही होता है। सरकार को इस पर सख्ती करनी होगी और युवा पीढ़ी को भी यह बात समझनी होगी कि एक दिन वे भी बूढ़े होंगे। इसलिए बुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा जरूरी है।

- सोनिया कश्यप, जम्मू

व्यवस्था की संवेदनहीनता

ओडीशा में हाल ही में सामने आया मामला सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था और संवेदनहीनता पर सवाल है। एक व्यक्ति अपनी बहन के खाते से पैसे निकालने बैंक पहुंचता है, लेकिन जरूरी दस्तावेज न होने के कारण उसे पैसे नहीं मिलते। नियमों के जाल में उलझा यह व्यक्ति इतना मजबूर हो जाता है कि अपनी बहन के कंकाल को लेकर भटकता है। सवाल यह नहीं है कि नियम क्यों है? नियम जरूरी है, लेकिन क्या इसके साथ मानवीय संवेदनाएं नहीं होनी चाहिए? अगर बैंक कर्मचारी उस बुजुर्ग को यह समझा देते कि मृत्यु प्रमाणपत्र कैसे और कहां से बनेगा, किन कागजों की जरूरत होगी, तो शायद यह स्थिति पैदा ही नहीं होती। ग्रामीण और अशिक्षित लोगों के लिए सरकारी प्रक्रिया अक्सर जटिल होती है। ऐसे में जिम्मेदारी सिर्फ नागरिक की नहीं, बल्कि व्यवस्था की भी है कि वह उन्हें सही दिशा दिखाए।

- सावित्री शाह, सिंगरौली

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

ईरान की निंदा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ खड़े होते हुए ईरान द्वारा किए गए हमले की जो निंदा की है, वह अभूतपूर्व है। यह बहुत दुखद है कि ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात या यूएई के फुजैराह बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से हमला किया। ध्यान रहे, भारत इस युद्ध का पक्षधर नहीं है और वह जल्द से जल्द युद्ध-विराम के पक्ष में है। यूएई भी युद्ध नहीं चाहता है और भारत से उसकी मित्रता छिपी नहीं है। ईरान भी भारत का मित्र देश है, पर यूएई का भारत से तालमेल ज्यादा बेहतर है। बड़ी संख्या में भारतीय इस संपन्न, खूबसूरत, अपेक्षाकृत ज्यादा उदार व समावेशी देश में रहते हैं। कई भारतीयों के लिए यह दूसरे घर की तरह है। अतः भारत द्वारा यूएई पर हमले की निंदा स्वागत के योग्य है। अक्सर कहा जाता है कि भारत ऐसे मौकों पर ठोस फैसले नहीं ले पाता और चुप्पी साध लेता है। इस पृष्ठभूमि में भी भारत द्वारा की गई निंदा से पूरे पश्चिम एशिया में ऐसा सकारात्मक संदेश जाएगा, जो आज बहुत जरूरी है।

यह प्रशंसनीय है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने न सिर्फ यूएई के साथ एकजुटता दिखाई है, बल्कि होर्मुज समुद्री मार्ग में नौवहन की आजादी बहाल करने की भी अपील की है। यूएई की अमेरिका और इजरायल से मित्रता ईरान को नागवार गुजर रही है। ईरान पर अमेरिका-इजरायल ने मिलकर हमला किया है, लेकिन रणनीति के तहत ईरान आसपास के देशों को निशाना बना रहा है, ताकि अपने पक्ष में सामरिक दबाव बना सके। बेशक, ईरान एक बड़ी सैन्य ताकत है, लेकिन उसका अपने करीबी पड़ोसियों के प्रति ऐसा हिंसक व्यवहार बड़े अफसोस की बात है। ईरान के अपने पड़ोसियों के साथ रिश्ते अब पता नहीं कब सामान्य हो पाएंगे? ईरान द्वारा फुजैराह बंदरगाह पर किया गया हमला सुनियोजित था, क्योंकि यह बंदरगाह, खोर फक्कन बंदरगाह के अलावा, होर्मुज के बाहर और ओमान की खाड़ी में स्थित है। यह बंदरगाह भारत के लिए भी बहुत महत्व रखता है। अगर इस बंदरगाह से तेल-गैस के जहाजों का संचालन सहजता से होने लगे, तब होर्मुज से गुजरने की जरूरत नहीं रह जाएगी। यहां यह भी समझने की जरूरत है कि यूएई तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से बाहर निकल आया है। उसके बाहर निकल आने से भारत जैसे मित्र देशों को ज्यादा फायदा है। वैसे भी, भारत को तेल की आपूर्ति करने वाले पांच देशों में यूएई शामिल है। यूएई से ज्यादा से ज्यादा तेल-गैस लेना भारत के लिए मुफीद है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ यूएई के साथ एकजुटता दिखाई है, बल्कि होर्मुज समुद्री मार्ग में नौवहन की आजादी बहाल करने की भी अपील की है।

यहां ईरान की निंदा होनी ही चाहिए। वह युद्ध के समाधान तक या अपनी बात को माने जाने तक पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बनाए रखना चाहता है। यूएई पर उसका हमला इसी कोशिश का नतीजा है। ईरान नहीं चाहता कि तेल-गैस की आपूर्ति का कोई वैकल्पिक मार्ग सक्रिय हो। यह बहुत निंदनीय है कि ईरान द्वारा यूएई पर इजरायल से भी ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। एक पहलू यह भी है, जहां सऊदी अरब और कतर ने पाकिस्तान से रक्षा समझौते किए हैं, वहीं भारत सरकार यूएई के साथ रणनीतिक रक्षा साझेदारी स्थापित करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मई को नीदरलैंड जाते समय अबू धाबी भी जाएंगे, तब बड़े समझौतों की संभावना है। तमाम देशों की निगाहें इस ओर हैं। ऐसे में, भारत को मुखरता से सही को सही और गलत को गलत कहने का साहस संजोए रखना चाहिए। वक्त पर दोस्तों के साथ खड़ा होना हर लिहाज से जायज है। मित्र देश ईरान को भी युद्ध से निकालने और मुख्यधारा में लाने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 07 मई, 1951

चीन के विरुद्ध प्रतिबन्ध

कोरिया में पिछले दस महीनों से युद्ध जारी है और उसका कोई अन्त नजर नहीं आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से 14 राष्ट्रों की सेनाएं कोरिया में लड़ रही हैं, किन्तु युद्ध का मुख्य बोझ अमरीकी सेनाओं को सहन करना पड़ रहा है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेम्बली ने भारतीय प्रतिनिधि की तजवीज को मान लिया होता और संबंधित राष्ट्रों की कान्फ्रेंस बुलाने का आयोजन किया होता, तो न केवल कोरिया में युद्ध-विराम हो जाता, बल्कि दूर पूर्व की उन समस्याओं का हल भी निकल आता, जिनके कारण इस भाग की शांति खतरे में पड़ी हुई है और तनाव बढ़ता जा रहा है। किन्तु अमरीका भारतीय प्रतिनिधि की तजवीज से सहमत नहीं हो सका और उसने चीन की निन्दा करने वाला प्रस्ताव स्वीकार किये जाने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका को आज असाधारण प्रभाव प्राप्त है। भारत से राष्ट्र उसके कल को देखकर अपना मत स्थिर करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब कोरिया में युद्ध-विराम के प्रश्न पर विचार हो रहा था तो कई राष्ट्रों ने, जो भारत के दृष्टिकोण से सहमत थे, अन्तिम समय में अमरीका के रुख को देखकर ही अपना मत बदल लिया। फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ में भारतीय प्रतिनिधि की तजवीज ठुकरा दी गई और अमरीका की इच्छानुसार चीन की निन्दा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने से चीन का रुख और भी कड़ा हो गया और शांतिपूर्ण समाधान की जो भी संभावनाएं नजर आ रही थीं, वे दृष्टि से ओझल हो गईं। तब से कोरिया-युद्ध में गतिरोध सा चला आ रहा है। संयुक्त राष्ट्रीय सेनाएं कभी आगे बढ़ती हैं और कभी उन्हें पीछे हट जाना पड़ता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस प्रस्ताव में चीन की निन्दा की थी, उसी में चीन के साथ समझौते का प्रयत्न करने के लिए एक सद्भावना समिति भी नियुक्त की गई थी। इसके साथ ही एक और संयुक्त राष्ट्रीय कमेटी है, जिसका काम आक्रमणकारी के विरुद्ध प्रतिबन्धात्मक उपाय सुझाना है। इस कमेटी ने अपना काम अब तक स्थगित-सा किया हुआ था, कारण वह सद्भावना समिति के समझौते के प्रयत्नों में आड़े नहीं आना चाहती थी। किन्तु सद्भावना समिति को अपने प्रयत्नों में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है।

ऑपरेशन सिंदूर हमेशा याद किया जाएगा

आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छाशक्ति, दोनों है।

यहां स्कैन करें

सैयद अता हसनैन | राज्यपाल, बिहार

ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ केवल एक तारीख नहीं है, यह भारत की रणनीतिक सोच में निर्णायक बदलाव पर विचार करने का क्षण है। 7 मई, 2025 की घटनाएं एक सफल सैन्य अभियान से कहीं अधिक थीं। इन घटनाओं ने राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्य तैयारी, तकनीकी क्षमता और राष्ट्रीय संकल्प के समन्वय को देश-दुनिया के सामने रेखांकित किया। कई मायनों में ऑपरेशन सिंदूर को भविष्य के संघर्ष संचालन के एक सटीक प्रारूप के रूप में याद किया जाएगा।

दशकों तक सीमा-पार की उकसावे की घटनाओं पर भारत की प्रतिक्रिया अक्सर स्व-निर्धारित संयम में सीमित रहती थी। ऑपरेशन सिंदूर ने संयम त्यागने का नहीं, बल्कि इसके परिष्कार को रेखांकित किया। इसने भारत की संवेदनशीलता के साथ बल-प्रयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित किया। राजनीतिक नेतृत्व ने न केवल कार्रवाई का मजबूत इरादा दिखाया, बल्कि उद्देश्य की स्पष्टता गति, सटीकता और सामंजस्य में बदल गई। ये तीन विशेषताएं ही सफल आधुनिक सैन्य अभियानों को परिभाषित करती हैं।

आज के युद्ध केवल धरती, समुद्र और हवा तक सीमित नहीं रहे; ये साइबर, अंतरिक्ष और विद्युत चुंबकीय आयाम तक फैल गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने इन क्षेत्रों में भारत की बढ़ती दक्षता को प्रदर्शित किया। उन सटीक हमलों में साइबर संचालन ने महत्वपूर्ण पूरक भूमिका निभाई। इसने विरोधियों की संचार और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को बाधित किया। इस अभियान ने संयुक्त कार्यक्षमता में हमारी परिपक्वता दिखाई- समन्वय से आगे बढ़कर वास्तविक एकीकरण तक।

यहीं नागरिक-सेना एकीकरण की भूमिका पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह पूरे राष्ट्र का प्रयास था। खुफिया एजेंसियों, तकनीकी संस्थाओं और नागरिक नेतृत्व ने सशस्त्र बलों के साथ मिलकर काम किया। स्वदेशी तकनीक ने निगरानी प्रणाली से लेकर

सटीक हथियारों तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आत्मनिर्भर बनने के हमारे प्रयासों में सतत निवेश के लाभ को उजागर करती है। अभियान से पहले और उसके दौरान रणनीतिक दूरदर्शिता दिखी। कूटनीतिक संवादों ने सुनिश्चित किया कि भारत की कार्रवाई को वैश्विक स्तर पर सही संदर्भ में समझा जाए- सटीक, आवश्यक और समानुपाती।

दूसरी ओर, पाकिस्तान सैन्य दृष्टि से सुसंगत जवाब देने के लिए संघर्ष करता रहा, क्षमता की कमी और आश्चर्य के तत्व, दोनों ने उसकी जवाबी प्रतिक्रिया की सीमाएं उजागर कर दीं। कूटनीतिक रूप से उसने स्थिति को अंतरराष्ट्रीय रूप देने का प्रयास किया, पर उसे सीमित सफलता मिली। हालांकि, उसकी प्रतिक्रिया का सबसे स्पष्ट पहलू सूचना क्षेत्र में था। वास्तविक हालात को छिपाने के प्रयास में गलत जानकारियों की चालाकी से बौछार की गई, पर वास्तविक समय पर जानकारी व वैश्विक निगरानी के युग में ऐसी कहानियां जल्द ही बेनकाब हो जाती हैं।

इस झूठे प्रचार का स्पष्टता व आत्मविश्वास के साथ खंडन करना आवश्यक है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी आक्रामकता नहीं थी, बल्कि यह पाकिस्तानी उकसावे पर संतुलित प्रतिक्रिया थी। इसके उद्देश्यों में सटीकता थी, इसके लक्ष्य वैध थे, और इसका क्रियान्वयन अनुशासित था। भारत की कार्रवाई ने आनुपातिकता और आवश्यकता के सिद्धांतों का पालन किया, जो संयम के विशेष लक्षण हैं। भारत ने पूरी प्रक्रिया में सूचना की सत्यनिष्ठा बनाए रखी। पूरी पारदर्शिता बनाए रखकर भारत ने आख्यान को तोड़ने-मरोड़ने के पाकिस्तानी प्रयासों को नाकाम कर दिया।

ऑपरेशन सिंदूर से कई सबक मिले, जो भविष्य के लिए मूल्यवान मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। सबसे पहले, राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। रणनीतिक अस्पष्टता विरोधियों का हौसला बढ़ाती है, स्पष्टता उन्हें हतोत्साहित करती है। दूसरा, बहु-क्षेत्रीय एकीकरण का विकास लगातार जारी रहना चाहिए। बढ़त बनाए रखने के लिए साइबर, अंतरिक्ष व कृत्रिम बुद्धिमत्ता में निवेश महत्वपूर्ण है। तीसरा, नागरिक-सैन्य समन्वय को और अधिक संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए, ताकि राष्ट्र-शक्ति का समन्वित तरीके से उपयोग सुनिश्चित हो सके।

एक अन्य महत्वपूर्ण सबक सूचना-युद्ध के लिए है। धारणा की लड़ाई सतत और सीमाहीन होती है। भारत को गलत जानकारी का पता लगाने, उसका मुकाबला करने और पूर्व-कार्रवाई की अपनी क्षमताओं को मजबूत करना चाहिए। त्वरित व विश्वसनीय संचार में तकनीकी उपकरण ही नहीं, बल्कि संस्थागत तंत्र को शामिल करना अहम है। आख्यान को जीतना रणनीतिक सफलता को बनाए रखने के लिए जरूरी है।

ऑपरेशन सिंदूर ने रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता के महत्व को भी रेखांकित किया। स्वदेशी रक्षा प्रणालियों ने अपनी योग्यता साबित की, जिससे बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम हुई और संचालन से जुड़ी स्वायत्तता बढ़ी। अनुसंधान, विकास और नवाचार में निरंतर निवेश के जरिये इस गति को बनाए रखा जाना चाहिए। इस प्रयास में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल महत्वपूर्ण होगा।

आज जब देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है, तो यह संदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की निर्णायक क्षमता और इच्छाशक्ति, दोनों है। इसने यह दर्शाया कि संयम अपनाना एक विकल्प है, अनिवार्यता नहीं। आने वाले वर्षों में, ऑपरेशन सिंदूर का अध्ययन बहुक्षेत्रीय प्रभावी अभियानों के उदाहरण के रूप में किया जाएगा। इसने अपेक्षाओं को फिर से परिभाषित किया है- भारत के भीतर भी और देश के बाहर भी। इसने इस सरल, लेकिन शक्तिशाली सिद्धांत को सुदृढ़ किया है कि जब राष्ट्रीय संकल्प का क्षमता के साथ संयोजन होता है, तो परिणाम निर्णायक होते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर की विरासत इसकी तात्कालिक सफलता तक सीमित नहीं है, यह उस आत्मविश्वास में निहित है, जो इसने पैदा किया है। यह उन सबमें निहित है, जो इसने आत्मसात किए हैं और उस मार्ग में निहित है, जो इसने भारत के सामरिक भविष्य के लिए निर्धारित किया है। अनसुलझे संघर्ष भारत की परीक्षा लेते रहेंगे- विभिन्न क्षेत्रों में और विकसित होते प्रारूपों में भी। फिर भी, जब तक राष्ट्र के राजनीतिक, सैन्य और संस्थागत प्रभाग एक साथ कार्य करेंगे, स्पष्टता और उद्देश्य के साथ अपनी क्षमताओं को एकीकृत करेंगे, प्रभाव का संतुलन हमेशा भारत के पक्ष में रहेगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

क्या कम हो रही मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी

यहां स्कैन करें

सुहेल वहीद | वरिष्ठ पत्रकार

पांच राज्यों के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से अभी हम गुजरे हैं। निस्संदेह, वहां सरकारों के गठन की कवायद तेज हो गई है, पर यह जानना सचमुच दिलचस्प होगा कि मुसलमानों की हिस्सेदारी के लिहाज से ये विधानसभाएं कैसी हैं और मुस्लिम मतों का क्या ट्रेंड दिख रहा है?

शुरुआत असम से। कश्मीर और लक्षद्वीप के बाद सबसे अधिक 34 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले इस राज्य में जनसंख्या के लिहाज से लगभग 55 मुस्लिम विधायक होने चाहिए थे। किंतु यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चर्चित परिसीमन के बाद 126 सीटों वाली असम विधानसभा में मुस्लिम बहुल सीटों की संख्या 32 से घटकर 22 रह गई हैं। दस वर्ष से असम की राज्य सरकार में कोई मुस्लिम मंत्री नहीं है और न अब होने की उम्मीद है। असम के 14 सांसदों में से दो मुस्लिम हैं।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया में समाज शास्त्र के प्रोफेसर नाजिमुद्दीन सिद्दीकी का पिछले वर्ष प्रकाशित एक अध्ययन बताता है कि असम की जेलों में बंद कुल विचाराधीन कैदियों में 52.54 फीसदी व कुल सजायाफ्ता कैदियों में 55.6 प्रतिशत संख्या मुस्लिमों की है। इस सूबे में एक भी डीएम या एसपी मुस्लिम नहीं है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय में भी 23 न्यायाधीशों में सिर्फ एक मुसलमान हैं। असम में बांग्लाभाषी हिंदुओं में निर्धनता दर जहां 12 फीसदी है, वहीं बांग्ला बोलने वाले मुसलमानों में यह दर 39 फीसदी है। गौरतलब है, असम में गरीबी दर तेजी से घटने के लिए नीति आयोग उसकी प्रशंसा कर चुका है। इस सूरतेहाल में मुसलमानों के खिलाफ चुनावी प्रचार करके मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अगर बड़ी फतह हासिल करते हैं, तो यह सियासी से ज्यादा सामाजिक सफलता मानी जानी चाहिए।

इन विधानसभा चुनावों के बाद मुसलमानों की सरकारों में नुमाइंदगी और घट जाएगी, क्योंकि ममता सरकार में सात मुस्लिम मंत्री थे।

ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल का है। यहां मुस्लिम आबादी 30 फीसदी से ज्यादा है और असम की तरह यह सूबा भी गरीब मुसलमानों का एक बड़ा आश्रय स्थल है। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की संस्था 'प्रतीची' के अनुसार, बंगाल की उच्च शिक्षा में मुस्लिम प्रतिनिधित्व 12 फीसदी है। यहां मुसलमानों की साक्षरता दर 57.47 फीसदी है, जो राज्य की औसत दर से दस फीसदी कम है। यह हाल तब है, जब बंगाल में करीब 46 वर्षों से वाम मोर्चे व तृणमूल कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों की सरकार रही है।

पश्चिम बंगाल में भी निर्धनता दर 27 फीसदी से घटकर अब 20 फीसदी रह गई है, लेकिन करीब 80 प्रतिशत मुस्लिम ग्रामीण परिवारों की मासिक आय आज भी 5,000 रुपये या उससे कम है। तीन चौथाई से अधिक मुस्लिम भूमिहीन हैं। आधे से अधिक के पास बीपीएल या मनरेगा कार्ड नहीं है। सिर्फ 36.6 प्रतिशत मुस्लिम आबादी पक्के घरों में रहती है। साफ है, यहां भी हालात ज्यादा नहीं बदल सके हैं।

केरलम में मुस्लिम आबादी 27 फीसदी से ज्यादा है। यह एक संपन्न और साक्षर राज्य है, जिसकी जीडीपी का बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से आने वाली कमाई है। यहां की छह लाख से अधिक नर्सें खाड़ी और अन्य देशों में नौकरी पर हैं। इनमें लगभग 40 फीसदी मुसलमान हैं। केरलम प्रवासन सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, यहां के प्रवासियों में मुस्लिम हिस्सेदारी सबसे अधिक 42 फीसदी है। लगभग 2.17 लाख करोड़ वार्षिक विदेशी धन में मुस्लिमों का हिस्सा 40 प्रतिशत है। हालांकि, असम व बंगाल की तरह यहां मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं होता।

सियासत का यह सामाजिक पहलू है, लेकिन इसका एक तकनीकी पक्ष भी है, वह है मुस्लिम प्रतिनिधित्व। इन चुनावों के बाद मुसलमानों की सरकारों में नुमाइंदगी और घट जाएगी, क्योंकि ममता सरकार में सात मुस्लिम मंत्री थे। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना में एक-एक और कर्नाटक में दो मुस्लिम मंत्री हैं। केरलम में दो-तीन बन सकते हैं।

केंद्र सरकार बिना मुस्लिम चेहरे के चल रही है। देश की करीब 20.05 करोड़ मुस्लिम आबादी बिना अपनी नुमाइंदगी के खुश रहने पर मजबूर है। कहा जा रहा है, सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग की परीक्षाओं समेत विकास योजनाओं के लाभार्थियों में वे बढ़ रहे हैं, पर यह स्वस्थ लोकतंत्र की खुशफहमी भरी चूक है। सबका साथ, सबका विकास यदि सरकार करे, तो कई अन्य रास्ते खुलेंगे। हिस्सेदारी ही जिम्मेदारी बढ़ाती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

शिक्षा का उद्देश्य साफ हो

मनुष्य ने मन में यह कल्पना पाल रखी है कि ईश्वर उसी की शक्ल के हैं। इसीलिए उसको इतना घमंड है। दूसरे जीवों की तुलना में अधिक क्षमता रखने के कारण उसने अपने को भगवान मान रखा है। केवल अपनी भलाई के बारे में सोचते हुए उसने उन सभी को इस जगत से दूर करने का निश्चय कर लिया, जो उसके अनुकूल न हो। ऐसी सोच फैलाने के लिए बनी है आज की शिक्षा पद्धति।

एक वैज्ञानिक ने अपने शोध आलेख के पन्नों को जोड़ने के लिए एक पेपर क्लिप की तलाश की। मेज पर रखी क्लिप टेढ़ी थी। उसे सीधा करने के लिए उन्हें एक औजार की जरूरत पड़ी। सभी चीजों को उलट-पुलटकर ढूंढ़ते हुए उन्हें जंप-क्लिप का बॉक्स मिल गया। वैज्ञानिक ने उसमें से एक नई क्लिप हाथ में ले ली। इस सही क्लिप की मदद से वह टेढी क्लिप को सीधा करने में जुट गए। यह देखकर उनका सहायक चौंक उठा। उसके संकेत करने के बाद वैज्ञानिक को अपनी मूर्खता का पता चला। पता है, वह वैज्ञानिक कौन थे? स्वयं आइंस्टीन! इसीलिए कह रहा हूं, सीखना अलग चीज है और जागरूकता के साथ काम करना अलग बात।

हमारे देश में पहले पारंपरिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। अकेले किसी व्यक्ति के निर्माण तक वह नहीं रुकी थी। उसके साथ जुड़े लोगों को भी उन्नत बनाने की शिक्षा के रूप में वह बनाई गई थी। वह दूसरों को अपने समान देखने की स्वस्थ दृष्टि प्रदान करती थी, लेकिन जब शिक्षा ब्रिटिश हुकूमत के अधीन हुई, उसने हम सबको भुलाकर केवल 'मैं' के बारे में सोचने की प्रेरणा दी। मैं, मेरा के बारे में देखने वाली शिक्षा समाज या परिवार के लिए कभी उचित नहीं है।

जो शिक्षा अपने ही घर, परिवार और देश को हेय दृष्टि से देखने की प्रेरणा देकर स्वयं को अपने ही देश में पराये की तरह अनुभव कराती है, ऐसी शिक्षा कदापि अच्छी नहीं है। शिक्षा वही उत्तम है, जो केवल जीविका तलाशने तक न रुके और सीखने वाले के दृष्टिकोण को स्वस्थ बनाए। जो हमारी संस्कृति की जड़ों को मजबूत करे। देश के नागरिकों को बंधनमुक्त, निर्भीक और पक्षपात रहित जीवन की ओर आगे बढ़ाए। अपनी उस संस्कृति से वह पुनः हमारी मुलाकात कराए, हमें जोड़े, जो स्वतंत्र वातावरण व दूसरों को अपने समान मानने की मनोवृत्ति को बढ़ावा देती थी।

जो शिक्षा अपने ही घर, परिवार और देश को हेय दृष्टि से देखने की प्रेरणा देकर स्वयं को अपने ही देश में पराये की तरह अनुभव कराती है, ऐसी शिक्षा कदापि अच्छी नहीं है।

राजनीति और धर्मों ने शिक्षा को अपने नियंत्रण में लेकर जनता के साथ ठगी करते हुए उन्हें निकम्मा बना दिया है। यदि योजनाबद्ध रूप से किसी चीज को ध्वस्त किया जा सकता है, तो हम योजनाबद्ध से किसी चीज का निर्माण क्यों नहीं कर सकते? शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है, यह हथियार सबको मिलना चाहिए, ताकि वह अपनी सुरक्षा कर सके।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

धर्मेंद्र प्रधान | केंद्रीय शिक्षा मंत्री

अंग की समृद्ध परंपरा, बंग की प्रखर बुद्धिमत्ता और कलिंग की अटूट कर्मशक्ति, ये तीनों मिलकर विकसित भारत के भव्य भविष्य की मजबूत नींव रख रहे हैं। संस्कृति, ज्ञान और परिश्रम का यह अद्भुत संगम भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

यह सीधा-सीधा जनादेश का अपमान

पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी का अपने पद से इस्तीफा न देने संबंधी रुख निहायत बचकाना है। ऐसी बेतुकी बात उनके जैसी उच्च शिक्षित महिला को शोभा नहीं देती। चुनाव संपन्न कराने में सिर्फ एक व्यक्ति नहीं काम करता, बल्कि इसे एक विशाल तंत्र मिलकर अंजाम देता है, जैसे चुनाव आयोग, स्थानीय प्रशासन, पुलिस आदि। ऐसे में, चुनाव हारने के बाद पद न छोड़ना जनादेश का अपमान है। ममता बनर्जी को खुले दिल से जनता का मत स्वीकार करना चाहिए और मुख्यमंत्री पद छोड़कर अपनी हार की समीक्षा करनी चाहिए। उनके जैसी शिक्षित व लोकतंत्र में आस्था रखने वाली नेता से परिपक्वता की उम्मीद की जाती है।

शैलबाला कुमारी, गृहिणी

पश्चिम बंगाल की जनता ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में डेढ़ दशक से राज्य की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की सरकार को नकारते हुए भारतीय जनता पार्टी को पहली बार स्पष्ट बहुमत दिया है। यह जनादेश केवल सत्ता-परिवर्तन का संकेत नहीं है, बल्कि तृणमूल की शासन शैली के प्रति जनता की स्पष्ट प्रतिक्रिया भी है। इस परिदृश्य में यदि कोई राजनीतिक दल या नेता जनादेश को स्वीकार करने के बजाय उस पर प्रश्नचिह्न लगाने का प्रयास करता है, तो इसे लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध माना जाएगा। चुनाव परिणामों के बाद आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति, विशेषकर बिना ठोस प्रमाण के, लोकतंत्र की गरिमा को आहत करती है। सर्वविदित है कि लोकतंत्र में जनता का निर्णय सर्वोपरि होता है। मतदाता अपने विवेक से सरकार चुनते हैं और उसी अधिकार से उसे बदलने का भी सामर्थ्य रखते हैं। अतः चुनाव परिणामों को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना प्रत्येक जन-प्रतिनिधि का नैतिक दायित्व है। पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में तेज ध्रुवीकरण देखने को मिला है। ऐसे में, यह अपेक्षा और भी बढ़ जाती है कि सभी पक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए संयम और परिपक्वता का परिचय दें। सत्ता परिवर्तन की स्थिति में शांतिपूर्ण हस्तांतरण ही लोकतंत्र की वास्तविक कसौटी है। जनादेश को नकारने या उस पर संदेह प्रकट करने से न केवल मतदाताओं की भावना आहत होती है, बल्कि देश की सांविधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं। यह स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। अतः सभी राजनीतिक दलों के नेतागण और खुद ममता बनर्जी जनादेश का सम्मान करें और जनता के विश्वास को सर्वोपरि मानते हुए आगे की राजनीति को सकारात्मक दिशा दें।

अरविंद रावल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

ममता बनर्जी

ममता को भला क्यों पद छोड़ना चाहिए

पांचों राज्यों में सबसे चौंकाने वाला नतीजा पश्चिम बंगाल का रहा है, क्योंकि भले ही यहां एनडीए को भारी बहुमत मिला हो, लेकिन जिस तरह से चुनाव-प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की खबरें आईं, उनसे यही संकेत निकलता है कि इसमें एक तरफ केंद्र की सरकार और उसका पूरा तंत्र लगा था, तो दूसरी तरफ राज्य की तृणमूल सरकार। जाहिर है, जब एक पार्टी विशेष के समर्थन में पूरा तंत्र झोंक दिया जाएगा, तो जीत को असल जनादेश मानना गलत होगा। इन सबकी शुरुआत एसआईआर से हुई थी, जो तृणमूल की कमर तोड़ने वाली प्रक्रिया साबित हुई। पूर्व में भी देश में मतदाताओं का गहन पुनरीक्षण होता रहा है, लेकिन हालिया एसआईआर जैसा विवादास्पद कभी नहीं रहा। इसका उद्देश्य केवल नाम घटाना नहीं, बल्कि जोड़ना भी होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में 91 लाख मतदाताओं के नाम, मनमाने ढंग से हटा दिए गए, जिसे शायद ही न्यायोचित कहा जाएगा। इतना ही नहीं, करीब 27 लाख मतदाता अयोग्य बताकर वोट देने से रोक दिए गए, क्योंकि उनके दस्तावेजों की जांच नहीं हो सकी थी। इसका अर्थ है कि इस बार लाखों मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि यह अधिकार उनको संविधान से हासिल है। ऐसे में, न्याय और लोकतंत्र की बात ही बेमानी है। शायद ही अब ऐसी कोई व्यवस्था बची है, जहां ममता बनर्जी जा सकें। ऐसे में, यदि उन्होंने मुख्यमंत्री पद न छोड़ने का एलान किया है, उसके निहितार्थ समझे जा सकते हैं।

जंग बहादुर सिंह, टिप्पणीकार

यह सही है कि लोकतंत्र में जीत और हार एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव कराए गए हैं, उनको देखते हुए ममता बनर्जी का कदम गलत नहीं लगता। जब 27 लाख मतदाताओं को मताधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, तो चुनाव परिणाम को 'वास्तविक जनादेश' कैसे मान सकते हैं? अच्छा तो यही होता कि कुछ दिन ठहरकर चुनाव कराए जाते, पर चुनाव आयोग को न जाने क्यों मतदान कराने की जल्दबाजी थी। 'जल्दबाजी' उसे क्यों थी, यह तो वही बता सकता है, लेकिन इस तरह के नतीजों की अपेक्षा विजेता दल को भी शायद ही थी। यह बात सही है कि ममता बनर्जी के इस 'अड़ियल रुख' का बहुत असर नहीं पड़ेगा और उन्हें आज नहीं तो कल, पद छोड़ना ही होगा। किंतु वह चाहें, तो अदालत में इस मामले को उठा सकती हैं। इसके अलावा, उन्हें जनता के बीच भी इस मुद्दे को ले जाना चाहिए। ममता बनर्जी का जनांदोलन करना भाजपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

दीपक कुमार, टिप्पणीकार

जब चुन-चुनकर भारत ने साधा निशाना

ठीक एक साल पहले ऑपरेशन सिंदूर से लिखी गई थी एक शौर्य गाथा, जिसे हम कभी भूल नहीं पाएंगे। कश्मीर के पहलगाम में हुए निर्मम आतंकी वारदात का मुकम्मल जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने एक बहुत संतुलित और आधुनिक सैन्य अभियान छेड़ा था। कुछ जोखिम उठाकर आतंकियों और उनके ठिकानों को ऐसे नुकसान पहुंचाया गया था कि महज चार दिन में पाकिस्तान संघर्ष विराम की गुहार लगाने लगा था। पेश हैं उस सिंदूरी शौर्य गाथा के कुछ पहलू...

100 से ज्यादा ड्रोन का सफल प्रयोग भारत ने किया और पाकिस्तान की ओर से आए 600 से ज्यादा ड्रोन मार गिराए गए।

आतंकियों को घर में घुसकर जवाब : ऑपरेशन सिंदूर के चार दिन

22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने 7 मई को सुबह होने से पहले ही रात 1:05 बजे पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। आतंकियों पर चुन-चुनकर निशाना साधा गया। जवाबी हमले भी हुए। यह अध्ययन का विषय है कि हमने कहां-कहां हमले किए और जवाबी हमले कहां-कहां हुए? पेश है राघव बिखचंदानी की ग्राफिक्स आधारित रिपोर्ट :

पहला दिन
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में नौ स्थानों पर आतंकी बुनियादी ढांचे पर सटीक हमले किए। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भारी गोलाबारी की, जिसमें कम से कम 13 लोगों की जान गई।

दूसरा दिन
भारत ने जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान के कई हमलों को विफल कर दिया। जवाब में भारत ने लाहौर के साथ-साथ कराची, रावलपिंडी और गुजरांवाला में हवाई रक्षा प्रणालियों पर हमले किए।

तीसरा दिन
इस्लामाबाद ने शत्रुता और बढ़ा दी। जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात में ड्रोन से हमले किए, जिनमें अधिकांश को भारत ने नाकाम कर दिया। पंजाब के फिरोजपुर शहर में एक ड्रोन हमले में तीन नागरिक घायल हो गए। भारत ने इसके उचित जवाबी उपाय किए।

चौथा दिन
पाकिस्तान द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में हमले तेज करने के बाद भारतीय वायुसेना ने सियालकोट, चकलाला और मुरीद सहित पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू किए। शाम पांच बजे से संघर्ष विराम लागू हुआ, लेकिन सीमा पर गोलाबारी के साथ पाकिस्तान द्वारा इसके कई उल्लंघनों की खबरें मिलीं।

सिंदूर से मिले सबक
- आतंकवाद का सुनियोजित जमीनी जवाब आक्रामकता के साथ देना चाहिए।
- तकनीकी कौशल और आत्मनिर्भर होना जंग के मैदान में भी काम आता है।
- भारत ने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया था कि उसकी लड़ाई आतंकियों से है।
- भारत का यह रुख बहुत प्रशंसनीय रहा कि उसका निशाना नागरिक नहीं हैं।
- किसी भी लड़ाई को जरूरत से ज्यादा नहीं खींचना चाहिए। संदेश जरूरी है।
- सैन्य अभियान के सटीक नामकरण का भी कारगर असर दुनिया में हुआ।

सुजान चिनॉय
डायरेक्टर जनरल, मनोहर पर्रिकर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस

कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के नौ ठिकानों पर अभूतपूर्व और आधुनिक सैन्य अभियान चलाते हुए वार किया था। भारत पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख पाकिस्तानी आतंकी ढांचों को तबाह कर दिया गया।

ऑपरेशन सिंदूर का एक अच्छा पहलू यह रहा कि भारत ने पाकिस्तान के आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने से परहेज किया, जबकि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हालात को ज्यादा बिगाड़ दिया। पाकिस्तान की ओर से किए गए जवाबी हमले बहुत हद तक नाकाम कर दिए गए। जवाब में भारत ने भी अभियान को आगे बढ़ाया। आतंकी नेटवर्क का समर्थन करने वाले प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर भी जवाबी हमले का सिलसिला चला दिया।

अब यह इतिहास में दर्ज है कि चार दिन के भीतर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद, भारत ने स्थापित सैन्य चैनलों के माध्यम से पाकिस्तान की युद्धविराम की अपील स्वीकार कर ली। किसी भी प्रकार की गलत सूचना या बाद में उसे छिपाने की कोशिश इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत सैन्य रूप से विजय प्राप्त की। साथ ही, एक नियंत्रित युद्ध का ऐसा ऊंचा स्तर दिखाया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था।

दुनिया का इतिहास ऐसे लंबे युद्धों के उदाहरणों से अटा पड़ा है, जिनको आसानी से या जल्दी विराम नहीं मिला है। ऐसे युद्धों में रूस-यूक्रेन युद्ध अब अपने पांचवें वर्ष में चल रहा है। वियतनाम और अफगानिस्तान में लंबे चले युद्ध भी इसमें शामिल हैं, जिनमें वर्षों तक लड़ाई, क्षेत्रीय अस्थिरता और आर्थिक बाधाएं देखी गईं। अभी पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की भारी कीमत न सिर्फ युद्धरत देश, बल्कि पूरा विश्व समुदाय चुका रहा है। इसके विपरीत, भारतीय नेतृत्व के दृढ़ संकल्प और सैन्य कौशल की बदौलत ऑपरेशन सिंदूर एक अंतहीन युद्ध बनने से बच गया।

भारत का निर्णायक फैसला

कोई दोराय नहीं, पहलगाम हमले के बाद की गई जवाबी कार्रवाई निर्णायक साबित हुई। भारत ने समन्वित अभियान के तहत पाकिस्तानी क्षेत्र में घुसकर पाकिस्तान और उसके अधिकृत जम्मू-कश्मीर में फैले नौ महत्वपूर्ण आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाया। लश्कर-ए-तइबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकानों को तबाह कर दिया। पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर से लेकर पाकिस्तानी पंजाब के सियालकोट और बहावलपुर जैसे स्थानों तक, इन हमलों ने अपनी पहुंच और सटीकता का प्रदर्शन किया। पाकिस्तान में नूर खान और सरगोधा हवाई अड्डों सहित अनेक महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया, जिससे यह साफ संदेश गया कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकी ठिकाना भारत की पहुंच से बाहर नहीं है। इन हमलों का पैमाना बड़ा था और सटीकता भी अभूतपूर्व थी। पाकिस्तान में यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ और मुदस्सिर अहमद सहित 100 से अधिक आतंकी मारे गए। पाकिस्तान अपनी कमियों को छिपा नहीं पाया।

ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के परमाणु खतरे को भी उजागर कर दिया था। यूक्रेन या गाजा जैसे संघर्षों के विपरीत, जहां व्यापक नुकसान होता है, इस अभियान ने पाकिस्तान में आतंकवाद और सैन्य बुनियादी ढांचे को तो भारी नुकसान पहुंचाया, पर वहां के नागरिक प्रतिष्ठानों को छोड़ दिया। दूसरी ओर, पाकिस्तानी द्वारा किए गए हमलों से भारतीय पक्ष पर प्रभाव नगण्य रहा। अगर संघर्ष विराम न होता, तो पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

पूरी दुनिया की निगाह के सामने भारत की एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली कारगर साबित हुई। विशेष रूप से स्वदेशी आकाशतीर रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की ओर से आ रहे ड्रोन और मिसाइलों का कामयाबी से मुकाबला करते हुए अपने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा की।

लागत और नुकसान

ऑपरेशन सिंदूर में भारत के सामने आर्थिक बाधाएं भी न्यूनतम आईं। पाकिस्तान पर संघर्ष की लागत भारी पड़ी। उसे जान-माल का ज्यादा नुकसान हुआ। भारत की सुविचारित योजना, प्रौद्योगिकी और क्रियान्वयन की सफलता सबके सामने आई। भारतीय वायु सेना ने राफेल जेट, स्कैल्प मिसाइलों व हैमर बमों का उपयोग करते हुए पाकिस्तानी वायु रक्षा प्रणालियों को चकमा दिया, उन्हें जाम कर दिया और 23 मिनट में मिशन पूरा कर दिखाया।

10 मई 2025 को, भारत ने पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाते हुए और महत्वपूर्ण क्षमताओं को निष्क्रिय करते हुए, कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया था। परमाणु हथियार संपन्न देश होने के बावजूद, भारत ने एक ही ऑपरेशन में पाकिस्तान के 11 सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया और कथित तौर पर पाकिस्तान की वायु सेना की 20 प्रतिशत संपत्तियों को नष्ट कर दिया।

रक्षा में आत्मनिर्भरता की ओर

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य एकजुटता, आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण का अच्छा प्रदर्शन किया। नौसेना ने समुद्री दबाव बनाए रखा, जबकि थल सेना व वायु सेना ने आतंकवाद और आतंकी-सैन्य बुनियादी ढांचे पर समन्वित हमले किए। इस ऑपरेशन में अनेक लंबित सुधारों को मान्यता मिली और सुधार के कार्य आगे बढ़े। जैसे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कार्यालय का सृजन हुआ और देश स्वदेशी रक्षा उत्पादन की ओर बढ़ा। रक्षा क्षेत्र में उत्पादन 2014-15 में 46,429 करोड़ रुपये से बढ़कर 2024-25 में 1,54,000 करोड़ रुपये हो गया, जिसमें से 65 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन देश में ही हो रहा है। ड्रोन आयात प्रतिबंध और पीएलआई योजना जैसी नीतियों ने घरेलू अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया है। आज 75 प्रतिशत रक्षा खरीद घरेलू स्तर पर होती है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास का 25 प्रतिशत निजी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। लगभग 90 प्रतिशत गोला-बारूद का स्वदेशीकरण हो चुका है और 2027-28 तक पूर्ण स्वदेशीकरण की उम्मीद है। ब्रह्मोस, आकाश, आकाशतीर, तेजस और ड्रोन-रोधी प्लेटफार्मों जैसी प्रणालियों ने बहु-क्षेत्रीय क्षमता को बढ़ाया है।

चार दिन के भीतर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद भारत ने पाकिस्तान की युद्ध-विराम की अपील स्वीकार कर ली। किसी भी प्रकार की गलत सूचना या बाद में उसे छिपाने की कोशिश इस तथ्य को नहीं बदल सकती कि भारत ने सैन्य रूप से विजय प्राप्त की।

सिंदूर ने ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित प्रणालियों की भूमिका को साबित कर दिया। पिछले दशक के व्यापक सुधार, जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उदारीकरण और रक्षा गलियारे का निर्माण शामिल हैं, ये सब प्रबंध भारत की दीर्घकालिक रणनीतिक स्वायत्तता के अनुकूल हैं।

सैन्य सफलता के लिए राजनीतिक दिशा-निर्देश केंद्रीय महत्व रखते हैं। सैनिकों का शौर्य महत्वपूर्ण है, लेकिन नेतृत्व की दूरदर्शिता परिणाम तय करती है। पिछले एक दशक में भारत आतंकवाद के जवाब में सैन्य विकल्पों का उपयोग करने की ओर संयम के साथ आगे बढ़ा है।

भारतीय नेतृत्व की दूरदर्शिता

भारतीय नेतृत्व ने संयमित जोखिम लेने की क्षमता का प्रदर्शन किया है और यह नेतृत्व सार्वजनिक रूप से आतंकियों को उनकी अपनी जमीन पर ही निशाना बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सशस्त्र बलों को पूरी आजादी दी गई है, हालांकि, जान के नुकसान से बचने के निर्देश के साथ। ध्यान रखने की बात है, शत्रु के क्षेत्र में भी नागरिक जीवन का सम्मान करने का यह सभ्यतागत लोकाचार पाकिस्तान के लिए अनजाना है, लेकिन भारत अपनी इस नीति पर बखूबी चला है। पाकिस्तान की नीति तो स्पष्ट है, वह भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ने के लिए आतंकवाद का सक्रिय रूप से उपयोग करता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सिंधु जल संधि को निलंबित करने से लेकर सुनियोजित जवाबी हमलों तक, सभी निर्णय सैन्य नेतृत्व के साथ सोच-समझकर और समन्वयपूर्वक लिए गए हैं। उनका मूलमंत्र स्पष्ट और सटीक रहा है : आतंकियों और उनके समर्थकों को, चाहे वे कहीं भी हों, निशाना बनाना।

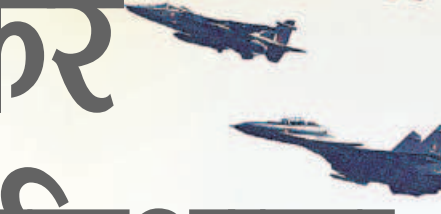

आक्रामकता रही असरदार

पाकिस्तान के साथ भारत के अनुभवों से यह पता चलता है कि बल प्रयोग द्वारा प्रतिरोध करना राजनयिक विरोध और दस्तावेज तैयार करने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होता है, जैसा 2008 में मुंबई में हुए भयावह आतंकवादी हमलों के बाद देखा गया था। स्पष्ट रूप से, ऑपरेशन सिंदूर ने इस संबंध में एक नया मानक स्थापित किया है। साथ ही, यह साफ संकेत भी दिया है कि भारतीय हमले जम्मू-कश्मीर से आगे बढ़कर पाकिस्तान के भीतरी इलाकों तक जा सकते हैं।

ऑपरेशन सिंदूर ने एक राष्ट्रव्यापी दृष्टिकोण को सामने रखा, जिसमें सशस्त्र बलों, सरकार और निजी उद्योग को एकीकृत किया गया। नागरिक-सैन्य समन्वय के लिए नए मानक स्थापित किए गए। विशेष रूप से, स्टार्टअप और निजी कंपनियों ने आईडेक्स ढांचे के समर्थन से ड्रोन और काउंटर-यूएएस प्रणालियों में योगदान दिया है। आने वाले वर्षों में इन रक्षा प्रणालियों की भूमिका बढ़ने की संभावना है। सिंदूर अभियान से सीखे गए सबक में एक यह भी था कि विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय में सुधार हुआ है। इसरो ने उपग्रह आधारित निगरानी प्रदान की, जबकि गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और सार्वजनिक संचार को प्रबंधित करने के सफल प्रयास किए गए।

सैन्य संचालन सुधार को बल

भारतीय सेना के एकीकृत रक्षा स्टाफ ने संयुक्त खरीद और संचालन सुनिश्चित किया। तीनों सैन्य सेवाओं को साझा खुफिया जानकारी पर कार्य करने में सक्षम बनाया गया। नागरिक प्रशासन को सैन्य योजना के साथ जोड़ा गया, जिसमें रक्षा तैयारी के उपाय और सार्वजनिक संचार शामिल थे।

ध्यान देने की बात है, भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने के लिए विश्व भर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजकर विपक्षी दलों से भी संपर्क साधा, जिससे राष्ट्र के समक्ष मौजूद व्यापक चुनौतियों के समाधान में राजनीतिक एकता के महत्व का पता चलता है। समग्रता में अगर देखें, तो ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों को कभी भूलना नहीं चाहिए।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan Times

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

मेष : मन अशांत रहेगा। संयत रहें। नौकरी में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। परिश्रम अधिक रहेगा। खर्च में बढ़ोतरी होगी।

वृष : आत्मसयंत रहें। व्यर्थ के क्रोध से बचें। बातचीत में भी संतुलित रहें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु कार्यक्षेत्र में बदलाव के साथ स्थान परिवर्तन होगा।

मिथुन : पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। शैक्षिक और बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।

कर्क : मन परेशान रहेगा। धैर्य रखें। संयत रहें। सेहत के प्रति सचेत रहें। कारोबार में वृद्धि होगी। शासन-सत्ता का सहयोग भी मिल सकता है। लाभ में वृद्धि होगी।

सिंह : आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे, परंतु मन परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। पिता का साथ मिलेगा। शैक्षिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी।

कन्या : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। मन परेशान भी रहेगा। धैर्यशीलता बनाए रखें। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। कारोबार में लाभ के अवसर मिलेंगे।

तुला : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। धार्मिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन अव्यवस्थित हो सकता है।

वृश्चिक : आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु धैर्यशीलता में कमी रहेगी। कारोबार में बदलाव की संभावना बन रही है। परिवार एवं मित्र जनों का साथ मिलेगा।

धनु : मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, परंतु आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। नौकरी में अफसरों से सहभाव बनाकर रखें। तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी।

मकर : मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। रहन-सहन कष्टमय हो सकता है। कारोबार में भी बदलाव की संभावना बन रही है।

कुंभ : आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के योग बन रहे हैं। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख में वृद्धि भी हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मीन : आत्मसंयत रहें। व्यर्थ के क्रोध एवं विवाद से बचें। खर्चों की अधिकता रहेगी। नौकरी में तरक्की के मार्ग प्रशस्त हो सकते हैं। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें।

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

07 मई, गुरुवार, **शक संवत्:** 17 वैशाख, (सौर) 1948 **पंजाब पंचांग:** 24, वैशाख मास प्रविष्टे 2083 **इस्लाम:** 19, जिल्काद, 1447, **विक्रमी संवत:** प्रथम (शुद्ध) ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तिथि प्रातः 10.15 मिनट तक पश्चात षष्ठी तिथि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सायं 06.46 मिनट तक पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, साध्य योग रात्रि 02 बजे तक। चन्द्रमा धनु राशि में रात्रि 01.27 मिनट तक उपरांत मकर राशि। **सूर्य उत्तरायण।** वसंत ऋतु। दोपहर 01.30 मिनट से अपराह्न 03 बजे तक राहुकालम्। श्री टैगोर जयंती।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

कई लोगों का कहना है कि मेरा घर वास्तु के अनुसार ठीक है। फिर भी मुझे लगता है कि घर में वो बात नहीं है, जो होनी चाहिए। – आर्यन कुलश्रेष्ठ, आगरा

- आपका घर वास्तु के अनुसार लगभग ठीक है, किंतु रंगों के चयन में बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है। घर में इतने सारे रंग करवाने के कारण दोष बन गया है। हर कमरे में लॉबी में अलग-अलग रंग हैं। उन्ही रंगों से मिलते हुए रंग हर जगह की छत पर हैं। इस कारण घर का आकाश तत्व खराब हो गया है। सीलिंग में हमेशा सफेद रंग अच्छा होता है, जिससे हम शांति का अनुभव करते हैं। नया सृजन कर पाते हैं, वरना आपकी सोच संकुचित हो जाती है। आप कम से कम छतों का रंग बदलवा दें।

वर्ग पहेली : 8321

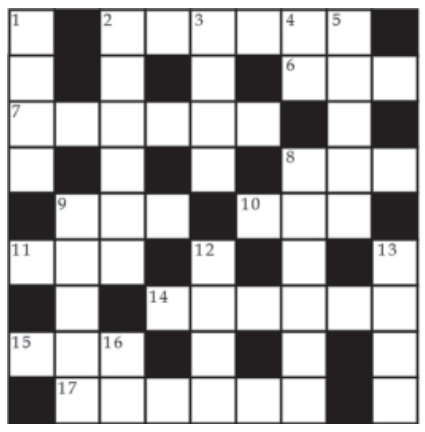

बाएं से दाएं
2. इज्जत करना; आदर करना; मान देना (3,3)
6. जलनिधि; रत्नाकर; समुद्र; सिंधु (3)
7. यज्ञ करना; होम करना (3,3)
8. कृत्रिम; बनावटी; झूठा; जाली (3)
9. धारण करने वाला; पात्र; कलश; घड़ा (3)
10. अनुरूपता; तुल्यता; बराबरी; समकक्षता; निष्पक्षता (3)
11. मतवाला; पागल; विक्षिप्त (3)
14. खत्म करना; निपटाना; संपन्न करना (3,3)
15. अंतर मिटना; साथ लगना; सम्मिलित होना; मिल जाना; भेंट होना (3)
17. अप्रसन्न करना; रुष्ट करना (3,3)

ऊपर से नीचे
1. प्रशंसा; तारीफ (4)
2. झेलना; बर्दाश्त करना; सहना (3,3)
3. अस्वीकृत करना; मना करना; रद्द करना (4)
4. पृथ्वी; जीभ; तरकारी का तरल अंश; शोरबा (2)
5. नागरिक अधिकारों से युक्त होने की अवस्था; निवासी होने का अधिकार (5)
8. झुकना; प्रणाम करना; माथा नवाना (3,3)
9. चढ़ाई करना; आक्रमण करना (2,3)
12. समाज का; समाज से संबंधित (4)
13. अप्रतिष्ठा; अपमान; तिरस्कार; आदर का अभाव (4)
16. हड़ताल में लगाया जाने वाला शब्द घोष; उद्घोष (2)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8320

■	1 प	2 रा	ज	3 य	■	4 प	त	5 न
6 ख	■	ज	■	7 था	म	ना	■	ह
8 ब	ल	प	ड़	ना	■	ह	■	ले
र	■	त्रि	■	म	■	■	9 पा	प
दा	■	10 त	थ्य	■	11 का	12 ल	■	र
13 रे	क्त	■	■	14 का	■	ह	■	द
क	■	15 ऊ	■	16 ला	प	र	वा	ह
र	■	17 स	मी	प	■	दा	■	ला
18 ना	ह	र	■	19 न	व	र	स	■

सुडोकू : 8303

* आसान

8		5			1	7	2	
					3			
			8	7				1
5	6		9					2
	4			5			9	
9					6		1	3
3				8	9			
			7					
	7	2	4			6		9

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8302

1	9	5	4	2	3	8	7	6
3	4	7	6	9	8	2	5	1
6	8	2	7	1	5	3	9	4
8	7	1	5	6	4	9	3	2
5	2	9	3	8	1	4	6	7
4	6	3	2	7	9	1	8	5
9	5	8	1	4	6	7	2	3
2	3	4	9	5	7	6	1	8
7	1	6	8	3	2	5	4	9

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 ● आगरा

सत्ता का मोह एक ऐसा जाल है, जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव है। -फ्रांज काफ्का

यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि 2011 में वामपंथी शासन के खिलाफ परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई ममता अब लोकतंत्र की उसी प्रक्रिया को स्वीकारने को तैयार नहीं दिख रहीं, जिसने उन्हें तीन बार मुख्यमंत्री बनाया। यह रवैया उनकी छवि को धूमिल करने के साथ बंगाल को भी अस्थिरता की ओर ले जा सकता है।

जनादेश, जिद और अराजकता

विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इन्कार करना लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध तो है ही, यह राज्य में नतीजों की घोषणा के बाद से फैली अराजकता को और भी भड़का सकता है। यह इसलिए भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि देश में शायद यह पहला ही ऐसा मामला होगा, जब विधानसभा चुनाव में किसी मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी की हार के बाद पद से इस्तीफा देने से इन्कार किया हो। ममता निर्वाचन आयोग और एसआईआर प्रक्रिया को अपनी हार के लिए जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन इस मामले में वह चयनात्मक नहीं हो सकतीं। आखिर इसी निर्वाचन आयोग ने केरल और तमिलनाडु में भी तो चुनाव कराए। इन दोनों ही राज्यों में सत्ताधारी दल को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वहां के मुख्यमंत्रियों ने तो सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। नतीजे बताते हैं कि कुल 293 सीटों में से सिर्फ 49 सीटों पर जीत का अंतर उन मतदाताओं की संख्या से कम था, जिन्हें एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाया गया था। इन सीटों पर भी आधी भाजपा ने, तो लगभग इतनी ही तृणमूल ने जीतीं। लोकतंत्र में कोई भी हार या जीत अंतिम नहीं होती, पर केवल संदेह और जिद के आधार पर जनादेश की अवहेलना करना ठीक नहीं। हार के बाद चुनाव आयोग या प्रशासनिक प्रक्रिया पर कोई भी सवाल उठा सकता है। यह उसका अधिकार है। ममता बनर्जी चाहें तो चुनाव परिणाम को अदालत में चुनौती दे सकती हैं, व्यवस्था के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ सकती हैं या फिर कोई राजनीतिक आंदोलन भी खड़ा कर सकती हैं। लेकिन फिलहाल वह जो कर रही हैं, वह सत्ता में बने रहने का हठ ही अधिक लगता है। ममता बनर्जी निस्संदेह बड़ी राजनेता हैं और जिस जुझारूपन से उन्होंने कभी सीपीएम का मुकाबला किया था, वह उन्हें देश के राजनीतिक इतिहास में एक अहम स्थान देता है। लेकिन उन्हें यह समझना चाहिए कि राजनीति में एक नेता की भूमिका सत्ता तक पहुंचने से पहले, सत्ता मिलने के बाद

और सत्ता से बाहर होने के बाद बदलती रहती है और यह अस्वाभाविक नहीं कि उनके कद के राजनेता से इसे सहजता से लेने की उम्मीद रखी जाए। यह दुखद ही है कि 2011 में वामपंथी शासन के खिलाफ परिवर्तन का नारा देकर सत्ता में आई ममता अब लोकतंत्र की उसी प्रक्रिया को स्वीकारने को तैयार नहीं दिख रहीं, जिसने उन्हें तीन बार मुख्यमंत्री बनाया। ममता को चाहिए कि वह जनादेश को स्वीकार करें, विपक्ष की भूमिका निभाएं और उचित मार्ग से अपनी शिकायतों का समाधान ढूंढें। अड़ियल रवैया न केवल उनकी छवि को धूमिल करेगा, बल्कि बंगाल को भी अस्थिरता की ओर ले जा सकता है।

सांविधानिक मर्यादा और सत्ता का मोह

ब्रिटेन के राजा जेम्स-II के लिए जब परिस्थितियां प्रतिकूल हुईं, तो उन्होंने यह सोचकर राजमुद्रा को टेम्स नदी में फेंक दिया कि उसके अभाव में लोगों को पुन: उनकी ओर ही लौटना पड़ेगा, पर ऐसा तो हुआ नहीं। यदि ममता भी कुछ ऐसा ही सोच रही हैं, तो उन्हें समझना होगा कि लोकतंत्र में कभी कोई व्यक्ति अपरिहार्य नहीं होता।

ममता बनर्जी ने चुनाव में हारने के बावजूद मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने से इन्कार कर दिया है। इससे मिलता-जुलता प्रकरण ब्रिटेन में भी हो चुका है। वर्ष 1688 में ग्लोरियस रिवोल्यूशन के समय जब ब्रिटेन के राजा जेम्स द्वितीय के लिए परिस्थितियां प्रतिकूल हुईं, तो लंदन से भागते समय उन्होंने अपनी राजमुद्रा को टेम्स नदी में फेंक दिया था। उनका विचार था कि राजमुद्रा के अभाव में शासन की वैधानिक प्रक्रिया रुक जाएगी और अंततः व्यवस्था को पुनः उन्हीं की ओर लौटना पड़ेगा। पर, ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सांविधानिक व्यवस्था व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि संस्थाओं और परंपराओं पर आधारित थी। राजमुद्रा के अभाव ने शासन को नहीं रोका, बल्कि नई व्यवस्था बनी, संसद ने अपनी भूमिका निभाई और अंततः जेम्स द्वितीय को सत्ता से बाहर होना पड़ा। इतिहास ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोकतंत्र अथवा सांविधानिक शासन किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होता।

हरवंश दीक्षित
विधि विशेषज्ञ

लोकतांत्रिक संस्थाओं का आधार निस्संदेह संख्याबल होता है, किंतु उनका पुष्पन-पल्लवन जिम्मेदार लोगों के परिपक्व आचरण से होता है। वह परंपराओं, सांविधानिक मर्यादाओं और नैतिक उत्तरदायित्वों की नींव से सुदृढ़ होता है। संविधान किसी राष्ट्र का लिखित ग्रंथ अवश्य होता है, पर लोकतंत्र की वास्तविक आत्मा उन अलिखित परंपराओं में निहित रहती है, जो सत्ता को संयमित करती हैं और शासक को उत्तरदायी बनाती हैं। जब कोई निर्वाचित शासक या सरकार जनभावनाओं अथवा नैतिक उत्तरदायित्व की उपेक्षा कर केवल पद से चिपके रहने का संकेत देती है, तब प्रश्न केवल राजनीतिक नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति और सांविधानिक परिपक्वता का बन जाता है।

भारतीय संविधान की मूल भावना भी यही है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का

प्रमुख होता है। यद्यपि मुख्यमंत्री का पद तकनीकी रूप से राज्यपाल के प्रसाद आधारित माना गया है, परंतु संसदीय लोकतंत्र की परंपरा यह स्थापित करती है कि सरकार को सदन का विश्वास तथा नैतिक वैधता, दोनों प्राप्त होने चाहिए। डॉ. भीमराव आंबेडकर ने भी संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि संविधान कितना भी उत्तम क्यों न हो, यदि उसे चलाने वाले लोग उचित सांविधानिक आचरण न करें, तो उसकी आत्मा क्षीण हो जाती है।

भारत की संसदीय परंपरा में 'सांविधानिक नैतिकता' का विचार अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने अनेक निर्णयों में इस सिद्धांत को लोकतंत्र का मूलाधार बताया है। वर्ष 1994 के एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ के ऐतिहासिक निर्णय में शीर्ष न्यायालय ने स्पष्ट किया कि लोकतंत्र केवल संख्या का प्रश्न नहीं, बल्कि सांविधानिक मूल्यों और उत्तरदायित्व का भी विषय है। इसी प्रकार वर्ष 2016 के नाबम रेबिया प्रकरण में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सांविधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को अपने अधिकारों का प्रयोग संविधान की आत्मा के अनुरूप ही करना चाहिए, न कि राजनीतिक सुविधा के अनुसार।

भारतीय राजनीति में त्यागपत्र केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि नैतिक उत्तरदायित्व का प्रतीक भी रहा है। बात अगस्त 1956 की है, जब आंध्र प्रदेश के महबूबनगर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ, जिसमें 112 लोगों की जान चली गई। इस हादसे की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, तत्कालीन रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पंडित नेहरू को अपना इस्तीफा सौंप दिया, लेकिन उन्होंने शास्त्री जी को इस्तीफा वापस लेने के लिए राजी कर लिया। कुछ महीनों बाद, नवंबर 1956 में, तमिलनाडु के अरियालुर में एक और रेल हादसा हुआ। इस घटना में 144 लोगों की मौत हो गई। शास्त्री जी ने तुरंत प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंप दिया और उनसे इसे जल्द से जल्द स्वीकार करने का आग्रह किया। स्वतंत्र भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति में यह उदाहरण आज भी राजनीतिक मर्यादा के आदर्श के रूप में स्मरण किया जाता है। इसके विपरीत, जब कोई शासक यह संदेश देने का प्रयास करता है कि उसके बिना शासन या व्यवस्था चल ही नहीं सकती, तब वह अनजाने में लोकतंत्र की मूल भावना का ही अपमान करता है।

यदि किसी राज्य में मुख्यमंत्री त्यागपत्र देने से इन्कार करते हैं अथवा यह संकेत देते हैं कि उनके पद पर बने रहने से ही व्यवस्था चल सकती है, तो यह लोकतांत्रिक संस्थाओं की शक्ति को कम करके आंकने जैसा है। भारतीय संविधान ने सत्ता के हस्तांतरण की स्पष्ट व्यवस्था दी है। संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के अंतर्गत राज्यपाल नई सरकार के गठन की प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है, किसी एक व्यक्ति के प्रति नहीं। लोकतंत्र की यही शक्ति है कि व्यक्ति बदल जाते हैं, परंतु संस्थाएं अपनी व्यवस्था से चलती रहती हैं।

इतिहास और संविधान, दोनों हमें सिखाते हैं कि सत्ता का वास्तविक सौंदर्य त्याग और उत्तरदायित्व में है, न कि पद से चिपके रहने में। राजा जेम्स द्वितीय की राजमुद्रा टेम्स नदी में डूब गई, पर ब्रिटिश शासन नहीं रुका। उसी प्रकार, किसी भी लोकतंत्र में कोई व्यक्ति इतना अपरिहार्य नहीं होता कि उसके बिना सांविधानिक व्यवस्था ठहर जाए। लोकतंत्र व्यक्तियों की नहीं, संस्थाओं की विजय का नाम है।

आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक नेतृत्व केवल कानूनी अधिकारों की नहीं, बल्कि सांविधानिक मर्यादाओं और नैतिक उत्तरदायित्वों की भी रक्षा करे। लोकतंत्र की स्थिरता संविधान की धाराओं से उतनी सुरक्षित नहीं होती, जितनी शासकों के आत्मसंयम, परिपक्वता और संस्थाओं के प्रति सम्मान से होती है। जब सत्ता का मोह सांविधानिक शिष्टाचार पर भारी पड़ने लगे, तब इतिहास चेतावनी देता है कि ऐसे क्षण केवल राजनीतिक संकट नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति की परीक्षा भी बन जाते हैं।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

रवींद्रनाथ टैगोर

जब हमारे शब्द, हाव-भाव, विचार और कर्म आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं, तब हमारे आचरण में एक ऐसी मधुरता प्रकट होती है, जो दूसरों के हृदय को स्पर्श करती है। इस प्रकार की विनम्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता।

विनम्रता ही चरित्र को आकार देती है

सभ्यता केवल औपचारिक शिष्टाचार या बाहरी विनम्रता का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यवहार की वास्तविक सुंदरता का प्रतीक है। सच्ची सभ्यता तब विकसित होती है, जब मनुष्य के भीतर धैर्य, आत्मसंयम और एक शांत व संतुलित मन का निर्माण होता है। यह कोई बनावटी गुण नहीं, बल्कि एक सृजनात्मक कला है, जैसे संगीत, चित्रकला या काव्य। जब हमारे शब्द, हाव-भाव, विचार और कर्म आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं, तब हमारे आचरण में एक ऐसी मधुरता और गरिमा प्रकट होती है, जो दूसरों के हृदय को स्पर्श करती है। इस प्रकार की विनम्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता और हमारे व्यक्तित्व की सच्ची अभिव्यक्ति होती है। यही गुण मनुष्य को केवल सामाजिक प्राणी नहीं, बल्कि संवेदनशील और सजग व्यक्तित्व बनाता है। यह हमारे संबंधों में विश्वास और सम्मान की नींव को भी मजबूत करता है।

दरअसल, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में इतना व्यस्त हो गया है कि वह इस आंतरिक सौंदर्य को धीरे-धीरे भूलता जा रहा है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में हम अक्सर जल्दबाजी में रहते हैं। वे हमें अधीर, असंवेदनशील और कभी-कभी कठोर बना देती हैं। हम केवल अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इस प्रक्रिया में हमारे व्यवहार की कोमलता और शिष्टता कहीं खो जाती है। मनुष्य केवल आवश्यकताओं का दास नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक उच्च आदर्श और गहरी चेतना विद्यमान है, जो उसे पूर्णता और एकता की ओर प्रेरित करती है। बस उसे इसे पहचानने की जरूरत होती है।

जब हमारे विचार, भावनाएं और कर्म एक दूसरे के साथ संतुलन में होते हैं, तब हम सच्चे आनंद का अनुभव करते हैं। जब यह सामंजस्य भंग होता है, तब हमें दुख, तनाव और अशांति महसूस होती है। इस प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी हमें यह सिखाती हैं कि सच्चा सुख हमारे भीतर ही निहित है। जब हम प्रेम, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, तब हमारा जीवन अधिक व्यापक और अर्थपूर्ण बन जाता है। इसके विपरीत, जब हम अपने आप को दूसरों से अलग कर लेते हैं, तब हमारे भीतर नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो हमें संकीर्ण और सीमित कर देती हैं। संसार की सच्चाई वस्तुओं की अधिकता या उनके आकार में नहीं, बल्कि उनके आपसी संबंधों और सामंजस्य में निहित होती है। यही संबंध जीवन को सुंदर और सार्थक बनाते हैं। प्रकृति का प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक परिवर्तन और प्रत्येक गति हमें इसी एकता और संतुलन का संदेश देता है। जब हम इस सत्य को समझते हैं और अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमारा जीवन केवल आवश्यकताओं की पूर्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह एक उच्च, सुंदर और आनंदमय अनुभव में परिवर्तित हो जाता है।

- 'पर्सनैलिटी' के अनूदित अंश

विचारों को सुंदर बनाएं

सूत्र

मनुष्य की वास्तविक सुंदरता उसके बाहरी वैभव में नहीं, बल्कि उसके शांत, संतुलित और संवेदनशील विचारों में छिपी होती है। जब हमारे विचार, शब्द और कर्म आपस में सामंजस्य स्थापित करते हैं, तभी जीवन में सच्चा आनंद और गरिमा जन्म लेते हैं। प्रकृति भी हर क्षण यही सिखाती है कि संतुलन और संबंध ही जीवन के आधार हैं।

दूसरा पहलू

साल 1924 में न्यूयॉर्क सिटी के सिविक क्लब में आयोजित एक डिनर पार्टी ने अमेरिकी सांस्कृतिक इतिहास की दिशा बदल दी।

1924 की वह डिनर पार्टी जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी

साल 1924 में न्यूयॉर्क सिटी के सिविक क्लब में आयोजित एक डिनर पार्टी ने अमेरिकी सांस्कृतिक इतिहास की दिशा बदल दी। यह आयोजन औपचारिक रूप से लेखिका और संपादक जेसी रेडमोन फॉसेट के पहले उपन्यास *देयर इज कन्फ्यूजन* के सम्मान में रखा गया था, पर नेशनल ज्योग्राफिक हिस्ट्री से जुड़ीं इतिहासकार और लेखिका पैट्रिशिया डेनियल्स के अनुसार, इसका वास्तविक उद्देश्य इससे कहीं बड़ा था।

इसी शाम को हार्लेम रेनैसांस की शुरुआत माना गया, जिसने अफ्रीकी-अमेरिकी पहचान को नई आवाज दी और अमेरिकी साहित्य, संगीत तथा कला को स्थायी रूप से बदल दिया। हार्लेम रेनैसांस 1920 और 1930 के दशक में उभरा वह आंदोलन था, जिसका केंद्र न्यूयॉर्क का हार्लेम इलाका बना। रेनैसांस का अर्थ पुनर्जागरण है। इस ऐतिहासिक डिनर के आयोजक समाजशास्त्री चार्ल्स एस जॉनसन और दार्शनिक एलेन लॉक थे। दोनों का उद्देश्य अश्वेत व श्वेत, दोनों समुदायों के प्रभावशाली लेखकों और बुद्धिजीवियों को एक मंच पर लाना था, ताकि उभरती हुई अश्वेत रचनात्मक पीढ़ी को राष्ट्रीय पहचान मिल सके। इस डिनर में ग्वेंडोलिन बेनेट, काउंटी कुलन, लैंग्स्टन ह्यूज और जोरा नील हर्स्टन जैसे युवा लेखक मौजूद थे, जो 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य के बड़े नाम बने। फॉसेट खुद इस आंदोलन की केंद्रीय शख्सियत थीं। वह *द क्राइसिस पत्रिका* की संपादक थीं और युवा लेखकों को अवसर देने में उनकी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने अश्वेत मध्यवर्गीय जीवन को साहित्य में स्थान दिया, जो उस समय दुर्लभ था। 1925 में, जॉनसन ने एक और बड़ा पुरस्कार समारोह आयोजित किया, जिसमें ह्यूज और हर्स्टन सहित कई युवा रचनाकार फिर एक साथ आए। उसी वर्ष हर्स्टन का नाटक कलर स्ट्रक प्रकाशित हुआ और 1926 में लैंग्स्टन ह्यूज का पहला कविता संग्रह सामने आया। धीरे-धीरे यही युवा लेखक अमेरिकी साहित्य की नई आवाज बन गए।

यह आयोजन लेखिका और संपादक जेसी रेडमोन फॉसेट के पहले उपन्यास *देयर इज कन्फ्यूजन* के सम्मान में रखा गया था।

आज, जब नस्लीय पहचान, प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक समानता पर दुनिया भर में नई बहसें चल रही हैं, 1924 की वह डिनर पार्टी फिर याद की जा रही है, जिसने अफ्रीकी-अमेरिकी पहचान को नई आवाज दी।

आज, जब नस्लीय पहचान, प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक समानता पर दुनिया भर में नई बहसें चल रही हैं, 1924 की वह डिनर पार्टी फिर याद की जा रही है। एक साधारण-सी दिखने वाली डिनर टेबल से उठी यह आवाज आगे चलकर अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली सांस्कृतिक आंदोलनों में बदल गई।

-अमर उजाला नेटवर्क

आंकड़े

देश में पीएनजी

भारत तेजी से पाइपलाइन के जरिये प्राकृतिक गैस (पीएनजी) अपनाने की ओर बढ़ रहा है। मार्च से अब तक 5.01 लाख से अधिक नए कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

महाराष्ट्र	43.4
गुजरात	37.8
उत्तर प्रदेश	21.2
दिल्ली	18.7
कर्नाटक	5.6

आंकड़े विभिन्न राज्यों में कुल पीएनजी कनेक्शन के, लाख में। | स्रोत : पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ

भोलेनाथ ने ब्राह्मण भक्त की परीक्षा लेने के लिए उसके मार्ग में स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली रख दी, पर उसने उसे स्पर्श तक नहीं किया।

भक्ति की परीक्षा

पौराणिक कथाओं के अनुसार, एक ब्राह्मण भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन-दौलत नहीं थी, किंतु उसके हृदय में श्रद्धा और संतोष का भाव था। वह जो भी थोड़ा-बहुत अन्न पाता, उसी में संतुष्ट रहता और सदा शिव नाम जपता रहता।

एक दिन उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव ने एक धनी व्यापारी का रूप धारण किया। उन्होंने उस ब्राह्मण के मार्ग में स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली रख दी। ब्राह्मण जब वहां पहुंचा, तो उसकी दृष्टि उस थैली पर पड़ी। क्षणभर के लिए उसका मन विचलित हुआ, परंतु अगले ही क्षण उसने स्वयं को संभाल लिया। वह मन ही मन बोला, 'यह धन मेरे लिए नहीं, यह मेरे तप और भक्ति को विचलित करने वाली माया है।' उसने उस थैली को स्पर्श तक नहीं किया।

अंतर्यात्रा
संकलित

उसकी निःस्वार्थ भक्ति और वैराग्य से प्रसन्न होकर भोलेनाथ अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, 'वत्स, तुमने धन के प्रलोभन पर विजय पाई है, यही सच्ची भक्ति है।' भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उस दिन से ब्राह्मण का जीवन पूरी तरह बदल गया।

अमर उजाला
पुराने पन्नों से — 7 मई, 1958

दहेज विरोधी विधेयक शीघ्र पेश किया जाएगा

संसद में दहेज विरोधी विधेयक शीघ्र पेश किया जायगा
कानूनमन्त्री श्री अशोकसेन ने महिला प्रतिनिधि मंडल को आश्वासन दिया

कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने कहा कि सरकार शीघ्र ही संसद में दहेज विरोधी विधेयक को पेश करेगी। दहेज एक गंभीर सामाजिक समस्या है तथा इसका उन्मूलन केवल कानूनी उपायों से नहीं, बल्कि लोगों के सहयोग से ही संभव है।

पुस्तक से पुस्तक के जन्म की कहानी पुरानी है

बिहारी लाल हरित ने *रामचरितमानस* की तर्ज पर *भीमायण* महाकाव्य की रचना की थी। ऐसे काव्य प्रयास पहले भी होते रहे हैं और आज भी जारी हैं।

श्यौराज सिंह 'बेचैन'

मुद्दा

पुस्तकें हमेशा नई पुस्तकों को जन्म देती आई हैं, और यह परंपरा बेहद पुरानी है। ताजा खबर के मुताबिक, '*रामचरितमानस* की तर्ज पर गाया भी जाएगा संविधान।' कई देशों के 142 रचनाकारों ने संविधान को दोहा, रोला और छंदों में सजाया है। ऐसे काव्य प्रयास पहले भी होते रहे हैं। 1950-73 में बिहारी लाल हरित ने *रामचरितमानस* की तर्ज पर *भीमायण* महाकाव्य की रचना की थी, तो आरडी निमेश ने *भीम कथामृतम* में संविधान को काव्य रूप देने का प्रयास किया।

हाल के दिनों में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी सुनील कुमार गौतम ने अनुच्छेदों को पद्य रूप में प्रस्तुत कर *संविधान काव्य* शीर्षक से एक खंडकाव्य प्रकाशित कराया। इसकी बानगी देखिए-'*प्रजातंत्र का मुख्य तंत्र है निर्वाचन आयोग।/इसकी मदद से सरकारों को चुनते हैं लोग।/चुनाव आयोगों को देता है संविधान सुरक्षा।/स्वतंत्र चुनावों से होती है, प्रजातंत्र की रक्षा।*' ऐसे में, हमें पुस्तक-संग्रह की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। पाठकीय रुचियों में विविधता होना अच्छी बात है।

बेशक इस 'डिजिटल युग' में विश्व साहित्य की बड़ी से बड़ी लाइब्रेरी मोबाइल इंटरनेट द्वारा मौजूदा पीढ़ी की मुट्ठी में आ गई है। कृत्रिम मेधा ने पुस्तकों के अध्ययन और लेखन मार्ग में बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है, पर मुद्रित पुस्तकें केवल सूचनाएं भर नहीं देतीं, अपितु मानवीय संवेदनाएं साझा करने का मौका देती हैं। ऐसे में किताबें पढ़ने और लिखने की स्पर्धा बच्चों में छिड़नी चाहिए। बच्चों से बच्चे अधिक सीखते हैं। बड़ों से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है। मसलन पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, 'किताब के पन्नों में ही समाधान है।' 12 वर्ष की अभिजिता की चार किताबें प्रकाशित होने जैसी खबरें हमें बाल लेखकों के प्रति आश्वस्त करती हैं। आठवीं कक्षा के छात्र आयुष सिंह ने 12-13 साल की उम्र में दो दर्जन बाल सुलभ कहानियों का संग्रह वरिष्ठ बाल लेखक प्रयाग शुक्ल को समर्पित किया है। इसलिए, हमें बच्चों के विषय और रुचियों के अनुरूप अपने आसपास पुस्तक-प्रेम का माहौल सृजित करना चाहिए। बच्चों की सयानी बातें बड़ों की बचकानी बातों से ज्यादा वजनी हो जाती हैं।

किताबें बचपन को संयम, सपने और सहृदयता देती हैं। वे निर्धनतम बच्चे को अब्राहम लिंकन बनाती हैं। पाठक की सोई हुई संभावनाएं जगाती हैं। किसी-किसी किताब का संदेश आजीवन व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। 16 वर्षीय बालक आंबेडकर को उनके पिता के मित्र शिक्षक कृष्णा जी अर्जुन केलूस्कर ने *बुद्धचरित* पुस्तक भेंट की थी। ध्यातव्य है डॉ. आंबेडकर ने जीवन की आखिरी किताब *द बुद्धा एंड हिज धम्म* की भूमिका पूरी करके ही अंतिम सांस ली थी। वही बालक आंबेडकर आगे चलकर पुस्तकों के सबसे बड़े संग्रहकर्ता हुए। अंतिम समय में मुंबई के उनके 'राजगृह' में 35 हजार निजी किताबों का अनमोल खजाना था। कहने का तात्पर्य कि अच्छी किताबों का असर भी अच्छा और संदेश स्थायी होता है। बालक की अभिरुचि पहचान कर ही किताबें उपलब्ध कराना उन्हें सही प्रोत्साहन देना होता है।

इस लेखक को वे दिन याद हैं, जब गांव नदरोली में स्वतंत्रता सेनानी यदुनाथ और रघुनाथ शास्त्री गांव की लड़कियों को निःशुल्क पढ़ाते थे। दोनों ही बड़े स्वाध्यायी थे। उन्होंने स्वामी दयानंद का *सत्यार्थ प्रकाश* पढ़वाया था। दसवीं में पढ़ाई के दौरान मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के प्रशिक्षु डॉ. नत्थू लाल ने लिखा था कि अगर तुम दसवीं पास कर लो, तो मैं तुम्हें बहुत अच्छी किताबें दूंगा। बशर्ते, तब तक तुम कोर्स पर ध्यान केंद्रित करो और पाठ्यक्रम से बाहर की किताबें पढ़ने की अपनी इच्छा को तब तक मुल्तवी कर दो। वह दिन आया, जब हम चंदौसी में मिले। उपहार में मिलने वाली चार-पांच किताबों में एक थी, हरिवंश राय बच्चन की *मधुशाला*, जिसे उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में स्वयं कवि के कंठ से सुना था।

यह वाकया 1978 का है, तब से आज तक न जाने कितनी किताबें पढ़ीं-पढ़ाईं, समीक्षाएं कीं, परंतु उन दिनों जो लेखकीय प्रेरणा *मधुशाला* से मिली, वह किसी और से नहीं मिली। ग्यारहवीं में छात्र सभा का अध्यक्ष और बाल कवि था। *मधुशाला* के प्रभाव में लिखी *विद्यालय* कविता पर उसका असर पड़ा। किताब केवल सूचनाएं नहीं देतीं, बल्कि संवेदनशीलता और रागात्मक नजरिया भी देती हैं। किताब हमारा भाषाई संस्कार संवारती हैं। शब्द भंडार में वृद्धि कर उपयुक्त शब्दों से हमारी अभिव्यक्ति और वाणी को प्रभावी बनाती हैं।

-लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर एवं पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष हैं।

क्रूड में तेज गिरावट से बाजार ने लगाई छलांग, सेंसेक्स में 941 अंक का उछाल

आखिरी घंटे में हुई तेज खरीदारी, निफ्टी ने लांघी 24,300 की दीवार

बोनस डेस्क

नई दिल्ली। शेयर बाजार ने बुधवार को वही किया, जिसका निवेशक कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। सुबह की घबराहट दोपहर आते-आते राहत में बदली और आखिरी एक घंटे में बाजार ने तेज छलांग लगा दी। सेंसेक्स 940.73 अंक या 1.22 फीसदी की बढ़त के साथ 77,958.52 पर बंद हुआ। दिन में एक समय यह 1,004.99 अंक उछलकर 78,000 के पार पहुंच गया। निफ्टी 298.15 अंक या 1.24 फीसदी चढ़कर 24,330.95 के स्तर पर पहुंच गया।

इसके साथ ही, निफ्टी ने 24,300 के उस स्तर को पार किया, जो पिछले कुछ सत्रों से बाजार के लिए मजबूत दीवार बना हुआ था। मिडकैप और स्मॉलकैप में भी खरीदारी लौटी, जिससे बाजार की यह तेजी केवल कुछ बड़े शेयरों तक सीमित नहीं रही।

इस तेजी का सबसे बड़ा कारण क्रूड में तेज गिरावट रही। अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद से ब्रेंट क्रूड 12 फीसदी टूटकर 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। बाद में थोड़ा सुधरकर फिर 100 डॉलर के पार पहुंच गया। क्रूड में नरमी को बाजार ने अर्थव्यवस्था और कॉरपोरेट कमाई के लिए सकारात्मक संकेत माना।

5.99 लाख करोड़ निवेशकों की बढ़ी पूंजी

298.15 अंक चढ़कर निफ्टी 24,330.95 के स्तर पर बंद

5,834.90 करोड़ की बिकवाली

- विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,834.9 करोड़ के शेयर बेचे।
- उधर, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,836.8 करोड़ की खरीदारी की।

सेंसेक्स के टॉप-5 गेनर

इंडिगो	6.60%
ट्रेंट	3.91%
एशियन पेंट्स	3.56%
एसबीआई	3.38%
एचडीएफसी बैंक	3.11%

बाजार को एक साथ तीन राहत

रुपये ने भी बाजार का साथ दिया। रुपया करीब 0.7 फीसदी मजबूती के साथ 94.61 के आसपास बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स भी टूटकर 97.79 पर आ गया। यानी बाजार को एक साथ तीन राहत मिली...**तेल सस्ता, रुपया मजबूत और घटता वैश्विक जोखिम।** यही वजह रही कि सुबह की सतर्कता के बाद दूसरे हाफ में तेजी ने जोर पकड़ा। ***सेक्टोरल मोर्चे पर तेजी व्यापक रही। बैंक, ऑटो, मेटल, आईटी और पीएसयू बैंकिंग शेयरों में जोरदार खरीदारी दिखी।***

तेल कंपनियों के शेयर चढ़े

एचपीसीएल	6.89%
बीपीसीएल	5.12%
इंडियन ऑयल	4.22%

पेंट शेयरों में भी रही बढ़त

इंडिगो पेंट्स	3.77%
एशियन पेंट्स	3.56%
शालीमार पेंट्स	2.33%

कर्ज गारंटी से विमानन शेयर 7 फीसदी तक उछले

बाजार की तेजी में एक और बड़ा ट्रिगर सरकार की कर्ज गारंटी योजना रही। सरकार ने ईरान संघर्ष से प्रभावित कारोबारों, खासकर एमएसएमई और विमानन कंपनियों को सहारा देने के लिए 18,100 करोड़ की कर्ज गारंटी योजना को मंजूरी दी। इससे विमानन शेयरों में 7 फीसदी तक की तेजी आई।

*स्पाइसजेट में अपर सर्किट लगा और अंत में बीएसई पर शेयर 4.96 फीसदी बढ़त में बंद हुआ। **इंडिगो में 6.60 फीसदी तेजी रही। बैंक निफ्टी भी एक फीसदी से ज्यादा चढ़ा।***

■ **क्या टिकेगी तेजी...**बाजार विशेषज्ञ वीएलए अंबाला कहती हैं, यह रैली अभी क्रूड और भू-राजनीतिक खबरों पर निर्भर है। तेल फिर उछला या समझौते की उम्मीद कमजोर हुई, तो मुनाफावसूली लौट सकती है।

वैश्विक दबाव के बीच सेवाओं के दम पर रिकॉर्ड निर्यात

आईटी, बिजनेस सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजाइन, रिसर्च और जीसीसी बन रहे भारत के नए डॉलर इंजन

नई दिल्ली। वैश्विक व्यापार पर टैरिफ, युद्ध, महंगे मालभाड़े और कमजोर मांग के दबाव के बावजूद भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में निर्यात के मोर्चे पर नया रिकॉर्ड बनाया। वस्तु और सेवाओं को मिलाकर कुल निर्यात 863.11 अरब डॉलर पहुंच गया, जो 2024-25 के 825.26 अरब डॉलर से 4.59 फीसदी अधिक है। यह तेजी बहुत चमकदार नहीं दिखती, लेकिन वैश्विक सुस्ती के बीच भारत की निर्यात क्षमता का मजबूत संकेत है। इस रिकॉर्ड को ताकत सेवा क्षेत्र ने दी, जिसका निर्यात बीते वित्त वर्ष में 8.71 फीसदी बढ़कर 421.32 अरब डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया। आईटी, बिजनेस सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, इंजीनियरिंग डिजाइन, रिसर्च और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी जीसीसी भारत के नए डॉलर इंजन बन रहे हैं।

उधर, वस्तु निर्यात 2025-26 में सिर्फ 0.93 फीसदी बढ़कर 441.78 अरब डॉलर रहा। यानी वस्तु निर्यात ने दबाव के बीच किसी तरह बढ़त बचाई। ■ बोनस डेस्क

863.11 अरब डॉलर पहुंच गया कुल निर्यात 2025-26 में

421.32 अरब डॉलर के नए शिखर पर पहुंच गया सेवा क्षेत्र का निर्यात

भारत अब सिर्फ सामान बेचने वाला देश नहीं

सेवा निर्यात में यह तेजी बताती है कि भारत अब सिर्फ सामान बेचने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया की कंपनियों को दिमाग, डाटा, तकनीक और प्रबंधन सेवाएं देने वाला केंद्र बन रहा है। कोविड के बाद वैश्विक कंपनियों ने लागत घटाने, आपूर्ति शृंखला फैलाने और डिजिटल कामकाज बढ़ाने पर जोर दिया। भारत को इसका लाभ मिला। हालांकि, रिकॉर्ड निर्यात के भीतर चेतावनी भी छिपी है। भारत का आयात तेज बढ़ रहा है। तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और औद्योगिक कच्चे माल पर निर्भरता व्यापार घाटे को दबाव में रखती है। इसलिए, निर्यात बढ़ने के बावजूद बाहरी खाते की चुनौती खत्म नहीं हुई है।

अब एआई व टैरिफ के मोर्चे पर है परीक्षा

अगला साल आसान नहीं होगा। अमेरिका और यूरोप में संरक्षणवाद बढ़ रहा है। यूरोपीय संघ का कार्बन बॉर्डर टैक्स, अमेरिकी टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाएं भारतीय निर्यातकों की लागत एवं अनुपालन बोझ बढ़ा सकती हैं। इसके अलावा, सबसे बड़ी नई चुनौती एआई है। भारत की सेवा शक्ति जिन कामों यानी कोडिंग, सपोर्ट, प्रोसेस और बैक ऑफिस...उन्हीं में एआई तेजी ला रहा है। खतरा यह नहीं कि सेवा निर्यात खत्म होगा, बल्कि कम मूल्य वाले काम की कीमत घटेगी।

घरेलू मांग से सेवा क्षेत्र मजबूत, वृद्धि पांच माह के शीर्ष पर

नए ऑर्डर और उत्पादन में तेज वृद्धि का असर, मार्च में 14 महीने के निचले स्तर पर आ गया था सूचकांक

नई दिल्ली। घरेलू मांग के दम पर देश के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां अप्रैल में बढ़कर पांच महीने के उच्च स्तर 58.8 पर पहुंच गईं। यह वृद्धि पिछले साल नवंबर के बाद सबसे अधिक है। मार्च में मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक गिरकर 14 महीने के निचले स्तर 57.5 पर आ गया था।

सर्वे में शामिल कंपनियों ने कहा, प्रतिस्पर्धी कीमतें, लॉजिस्टिक्स सेवाओं में उछाल और ई-कॉमर्स की बढ़ती मांग ने कारोबार को मजबूती दी। नए ऑर्डर और उत्पादन बढ़ोतरी में उपभोक्ता सेवाएं सबसे आगे रहीं। इसके

बाद ट्रांसपोर्ट, सूचना और संचार का स्थान रहा। उधर, अप्रैल में महंगाई की रफ्तार कुछ धीमी हुई, फिर भी यह हाल के महीनों के ऊंचे स्तरों पर बनी रही। इससे लागत में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन इसका बोझ पूरी तरह ग्राहकों पर नहीं डाला गया। कीमतों में वृद्धि सीमित रहने से शुल्क आधारित महंगाई तीन महीने के निचले स्तर पर आ गई। कंपनियां अगले 12 महीनों में कारोबार बढ़ने को लेकर आशावादी हैं। रोजगार के मोर्चे पर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। इस साल की पहली तिमाही की शुरुआत में कंपनियों ने अधिक भर्तियां कीं। अस्थायी और जूनियर स्तर के कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई, ताकि काम के बोझ को संभाला जा सके।

एचएसबीसी इंडिया की मुख्य अर्थशास्त्री प्रांजुल भंडारी ने कहा, निर्यात से जुड़े ऑर्डर कुछ कमजोर पड़े। यह संकेत है कि ईरान संकट के चलते मांग विदेशी बाजारों से हटकर घरेलू बाजार की ओर लौट रही है। एजेंसी

न्यूज डायरी

सोना 2,900 रुपये महंगा चांदी भी 1.4% चमकी

नई दिल्ली। अमेरिका-ईरान के बीच समझौते की उम्मीदों और कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से बुधवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 2,900 रुपये या करीब दो फीसदी महंगा होकर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 3,500 रुपये या 1.4 फीसदी बढ़कर 2,54,500 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव पहुंच गई। इसके साथ ही, चांदी में तेजी का सिलसिला लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में जारी रहा। वैश्विक बाजार में सोना 106.15 डॉलर की बढ़त के साथ 4,663.70 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया। एजेंसी

पेटीएम घाटे से उबरी 183 करोड़ का लाभ

नई दिल्ली। पेटीएम ब्रांड का स्वामित्व रखने वाली कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस ने घाटे से उबरते हुए 2025-26 की मार्च तिमाही में 183 करोड़ रुपये का एकीकृत मुनाफा कमाया है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 545 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। **उधर, श्री सीमेंट** का शुद्ध लाभ मार्च तिमाही में करीब 8.5 फीसदी घटकर 525.69 करोड़ रह गया। कंपनी के बोर्ड ने 2025-26 के लिए 70 रुपये प्रति शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। एजेंसी

कच्चे तेल में नरमी से रुपया 69 पैसे मजबूत, डॉलर इंडेक्स लुढ़का

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट के दम पर रुपया एक दिन पहले के रिकॉर्ड निचले स्तर से उबरने में कामयाब रहा और बुधवार को डॉलर के मुकाबले 69 पैसे मजबूत होकर 94.49 पर बंद हुआ।

दरअसल, अमेरिका-ईरान समझौते की उम्मीद से वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड करीब 12 फीसदी टूटकर 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया। भारत अपनी क्रूड जरूरतों का 88 फीसदी हिस्सा आयात करता है। इसलिए, तेल सस्ता होते ही डॉलर की मांग पर दबाव बढ़ा और रुपये को सहारा मिला। वैश्विक बाजारों में

घरेलू बाजार में सुधार और सरकारी बॉन्ड यील्ड में नरमी से भी रुपये को मिला सहारा

भी जोखिम लेने की भूख लौटी। डॉलर इंडेक्स 0.66 फीसदी टूटकर 97.79 पर आ गया। सुरक्षित निवेश के रूप में अमेरिकी डॉलर की मांग घटने, भारतीय बाजार में सुधार और सरकारी बॉन्ड यील्ड में नरमी से भी रुपये को समर्थन मिला। **आगे रुपये की चाल मुख्य रूप से तीन बातों से तय होगी...**कच्चे तेल की दिशा, विदेशी निवेशकों की वापसी और आरबीआई का हस्तक्षेप। ■ बोनस डेस्क

सरकार के पास 604.02 लाख टन गेहूं-चावल का भंडार, बफर मानकों से तीन गुना अधिक

नई दिल्ली। सरकार का गेहूं एवं चावल का भंडार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में एक अप्रैल, 2026 को बढ़कर 604.02 लाख टन पहुंच गया। यह निर्धारित बफर मानक 210.40 लाख टन का करीब तीन गुना है।

आंकड़ों के मुताबिक, चावल का भंडार 386.10 लाख टन रहा, जो 135.80 लाख टन के बफर मानक से काफी अधिक है। गेहूं भंडार 74.60 लाख टन के बफर मानक के मुकाबले 217.92 लाख टन पहुंच गया। अनाज भंडारण के बफर मानक तिमाही आधार पर संशोधित होते हैं। मौजूदा मानक एक अप्रैल से लागू हैं और अगला संशोधन एक जुलाई को होगा। इस बीच, 2026 की रबी फसलों की खरीद प्रक्रिया जारी है। देश में 334.17 लाख हेक्टेयर में बोए गए गेहूं में करीब 97 फीसदी की कटाई हो चुकी है। दलहनों की कटाई भी पूरी हो गई है। रबी सत्र वाले धान की कटाई 59.32 फीसदी तक पहुंच गई है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और तेलंगाना में केंद्रित है। एजेंसी

रबी फसलों के थोक दाम एमएसपी से नीचे

एक अधिकारी ने कहा, एक मई को समाप्त हुए सप्ताह में लगभग सभी प्रमुख फसलें एमएसपी से नीचे कारोबार कर रही थीं। गेहूं का भाव 2,530 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जो 2,585 रुपये के एमएसपी से 2.13 फीसदी कम है। धान की कीमत 3.17 फीसदी गिरकर 2,294 रुपये प्रति क्विंटल पर आ गई। मक्के का भाव 2,400 रुपये के एमएसपी से 23.71 फीसदी घटकर 1,831 रुपये प्रति क्विंटल रहा। अरहर, मूंग, बाजरा और सूरजमुखी के थोक दाम भी एमएसपी से नीचे बने हुए हैं।

ई-कारों की बिक्री 75.14 फीसदी बढ़ी, टाटा मोटर्स ने बेचे सर्वाधिक

नई दिल्ली। देश में इलेक्ट्रिक कारों (यात्री वाहनों) की बिक्री अप्रैल में 75.14 फीसदी बढ़कर 23,506 इकाई पहुंच गई। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लि. 8,543 इकाइयों की बिक्री के साथ शीर्ष पर रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 5,413 ई-कारें बेचीं और वह दूसरे स्थान पर रही। जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर 5,006 इकाइयों के साथ तीसरे स्थान पर रही।

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) के बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, बीते महीने 1,48,740 इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बिके, जो सालाना आधार पर 60.73 अधिक है। टीवीएस मोटर कंपनी इस

फाडा के आंकड़े...इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 60.73 फीसदी का उछाल

सेगमेंट में 37,683 इकाइयों की बिक्री के साथ शीर्ष पर रही। बजाज ऑटो 32,898 इकाइयों के साथ दूसरे और एथर एनर्जी 27,034 इकाइयों के साथ तीसरे स्थान पर रही।

आंकड़ों के मुताबिक, इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री बीते माह 3.3 फीसदी बढ़कर 64,549 इकाई पहुंच गई। इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री एक साल पहले के 902 से बढ़कर 2,245 इकाई पहुंच गई। एजेंसी

अमर उजाला **Job Alert**
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड

अस्पताल सहायक के पदों पर मौके

1200 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 21 मई, 2026
वेतनमान : रुपये 15,500 से लेकर रुपये 49,000 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : esb.mp.gov.in

कोल इंडिया लिमिटेड ■ 660 पद

मैनेजमेंट ट्रेनी के पदों पर आवेदन आमंत्रित
आवेदन की अंतिम तिथि : 11 जून, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : coalindia.in

पीजीआईएमईआर में रिक्तियां ■ 134 पद

सीनियर रेजिडेंट व अन्य पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 11 मई, 2026
आयु-सीमा : अधिकतम उम्र 45 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : pgimer.edu.in

वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून ■ 91 पद

तकनीकी सहायक, वन रक्षक व अन्य पद रिक्त
आवेदन की अंतिम तिथि : 03 जून, 2026
योग्यताएं : दसवीं, बारहवीं व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : fri.icfre.gov.in

भारतीय रिजर्व बैंक ■ 60 पद

ग्रेड-बी ऑफिसर के पदों पर रोजगार के अवसर
आवेदन की अंतिम तिथि : 20 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 21 वर्ष व अधिकतम उम्र 30 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : ibpsreg.ibps.in/rbisbmar26/

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ■ 10 पद

डिप्टी मैनेजर के पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 12 मई, 2026
योग्यताएं : बीई/बीटेक/बीएससी व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : engineersindia.com

योग्य उम्मीदवार करें आवेदन...

अटल बिहारी वाजपेयी-भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, ग्वालियर : इंजीनियर्स के पद रिक्त।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 01 जून, 2026
- iiitm.ac.in

ओएनजीसी ऊर्जा केंद्र : प्रोजेक्ट फेलो/एसोसिएट्स के पदों पर आवेदन आमंत्रित।
- आवेदन की अंतिम तिथि : 25 मई, 2026
- ongcindia.com

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कॅरिअर

हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वही हमें बेहतर बनाती है।

एग्जाम टिप्स : राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, सीयूईटी यूजी परीक्षा

चार दिन बाकी, करते रहें रिवीजन

मुकेश श्रीवास्तव
कॅरिअर सलाहकार

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सीयूईटी यूजी परीक्षा 11 मई, 2026 से होने जा रही है। ऐसे में जिन छात्रों की तैयारी अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, उनके लिए बचे हुए समय का सही और प्रभावी उपयोग करना बेहद आवश्यक है। परीक्षा के नजदीक आते समय तनाव महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन सकारात्मक सोच और नियमित अभ्यास के जरिये इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यह याद रखना जरूरी है कि आपने साल भर जो मेहनत की है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सही रणनीति से की गई परीक्षा की तैयारी आपको सफलता के और करीब ले जाती है, और कम समय में बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।

■ रिकॉल करते रहें

सिर्फ पढ़ने के बजाय अपनी तैयारी को और अधिक सक्रिय बनाएं। किसी भी टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें-जैसे, इससे परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है? फिर बिना देखे जवाब देने की कोशिश करें। इसे 'एक्टिव रिकॉल' कहते हैं, जिससे याददाश्त मजबूत होती है और आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी होती है।

■ गलतियों की नोटबुक बनाएं

एक अलग कॉपी रखें, जिसमें आप अपनी गलतियां लिखते चलें। जब आप मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर हल करते हैं और कोई सवाल गलत हो जाता है, तो उसे उस कॉपी में नोट कर लें। साथ में यह भी लिखें कि इसका सही जवाब क्या था और गलती क्यों हुई। इसके बाद उस कॉपी को रोज थोड़ा समय निकालकर दोबारा पढ़ें। इससे आपको अपनी कमजोरियां साफ समझ में आने लगेंगी और आप उन्हें दोबारा नहीं दोहराएंगे। यह तरीका धीरे-धीरे आपकी सटीकता और स्कोर दोनों बढ़ाने में मदद करता है।

■ ऑडियो रिवीजन

जो टॉपिक्स आपको मुश्किल लगते हैं, उन्हें अपनी आवाज में बोलकर रिकॉर्ड कर लें। फिर उस रिकॉर्डिंग को अपने मोबाइल में सेव कर लें। इसके बाद जब भी आप खाली हों, उसे सुनते रहें। इससे बार-बार पढ़ाई करने की जरूरत नहीं पड़ती और समय का सही उपयोग हो जाता है। साथ ही, सुनने से याददाश्त भी मजबूत होती है और कठिन टॉपिक्स आसानी से समझ में आने लगते हैं।

- *पढ़ने के बाद खुद से सवाल पूछें और बिना देखे जवाब दें।*
- *हर चैप्टर के एक पेज का शॉर्ट रिवीजन नोट बनाएं।*
- *मॉक टेस्ट की गलतियों को अलग कॉपी में लिखें और रोज देखें।*
- *पहले प्रश्न देखें, फिर टॉपिक पढ़ें, ताकि फोकस साफ हो।*

■ अंतिम समय का नियम

सोने से ठीक पहले नया टॉपिक पढ़ने के बजाय दिनभर पढ़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, फॉर्मूले और नोट्स का हल्का-सा रिवीजन करें। इस समय दिमाग शांत होने के कारण दोहराई गई जानकारी लंबे समय तक याद रहती है और बेहतर तरीके से बैठ जाती है। इससे एग्जाम के समय जल्दी रिकॉल करने में भी मदद मिलती है। लगातार ऐसा करने से पढ़ाई का असर बढ़ता है और आत्मविश्वास भी बेहतर होता है।

इंटर्नशिप प्रोग्राम

डीएसएलएसए इंटर्नशिप

- **संस्थान :** दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
- **पात्रताएं :** भारत के किसी भी विधि विश्वविद्यालय/कॉलेज का कानून का छात्र होना चाहिए, तथा अंग्रेजी में लिखित संचार, कानूनी लेखन, बुनियादी कानूनी ज्ञान और वर्ड/एक्सेल/पीपीटी में दक्षता होनी चाहिए।
- **लाभ :** इंटर्नशिप प्रमाणपत्र
- **आवेदन लिंक :** dslsa.org
- **अंतिम तिथि :** 15 मई, 2026

आवेदन आमंत्रित

न्यायिक फेलोशिप-2026

- **पात्रताएं :** प्रारंभिक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट हों, जिनके पास दीवानी या आपराधिक मामलों में पांच-सात वर्ष का अनुभव हो।
- **अवधि :** दो हफ्ते
- **आवेदन लिंक :** tinyurl.com/3we9nk8e
- **अंतिम तिथि :** 01 जून, 2026

एग्जाम अलर्ट

बिहार विधान परिषद डीईओ परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 10 मई, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, गणित तथा मानसिक व तार्किक क्षमता से 400 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि दो घंटे निर्धारित की गई है।
- **यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें** vidhanparishad.bihar.gov.in

एनटीए सीयूईटी यूजी परीक्षा

- **परीक्षा की तिथि :** 11 से 31 मई, 2026
- इस परीक्षा में भाग-1 में भाषा, भाग-2 में विषय-क्षेत्र और भाग-3 में सामान्य अध्ययन से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नपत्र एनसीईआरटी कक्षा बारहवीं के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा।
- **परीक्षा केंद्र की जानकारी प्राप्त करें** tinyurl.com/ytb79st8

खुद को परखें

1. हंतावायरस का संचरण मुख्य रूप से किस प्रजाति द्वारा होता है?
   (a) मच्छर (b) कृंतक
   (c) मक्खी (d) फल चमगादड़
2. भारतीय मानक ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है?
   (a) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
   (b) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   (c) उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
   (d) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
3. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है?
   (a) केरल (b) कर्नाटक
   (c) गुजरात (d) महाराष्ट्र
4. हाल ही में खबरों में रहा मायोन ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
   (a) इंडोनेशिया (b) जापान
   (c) चीन (d) फिलीपींस

उत्तर-1.b, 2.c, 3.d, 4.d

07 मई, 1907

आज का दिन

मुंबई में पहली इलेक्ट्रिक ट्राम कार का संचालन शुरु हुआ था। यह घटना भारत के शहरी परिवहन इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

- **1861 :** नोबेल पुरस्कार विजेता और कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था।
- **1973 :** अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर की आधारशिला रखी गई।
- **2000 :** व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने थे।
- **2001 :** हिंदी सिनेमा जगत के मशहूर गीतकार प्रेम धवन का निधन हुआ था।

व्रत त्योहार

आज : ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी।
कल : ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : प्रातः 10.30 से 12.00 तक।

■ सूर्योदय : 05.39
■ सूर्यास्त : 18.56
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 18 वैशाख मास शक 1948, वैशाख मास 25 प्रविष्टे, 20 जिल्काद हिजरी 1447, प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी 12.21 तक उपरांत सप्तमी, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र 21.19 तक उपरांत श्रवण नक्षत्र, शुभ योग 26.29 तक उपरांत शुक्ल योग, वणिज करण 12.21 तक उपरांत विष्टि (भद्रा) करण, चंद्रमा मकर राशि में दिन-रात।

राशिफल

amarujala.com/astrology
■ पं. विनोद त्यागी

मेष : मनोत्साह बना रहेगा। नौकरी में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें।

वृष : धैर्य बनाए रखें। नौकरी में स्थिति यथावत रहेगी। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। विरोधी परास्त होंगे।

मिथुन : बेरोजगारी से मुक्ति मिल सकती है। आय का स्थायी साधन बन सकता है। मित्र सहयोग मिलेगा।

कर्क : मान-सम्मान बना रहेगा। विरोधी शांत रहेंगे। नौकरी में उन्नति हो सकती है। उदर कष्ट संभव है।

सिंह : भाग्य सहायक रहेगा। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। योजना में सफलता मिलेगी। सेहत नरम रहेगी।

कन्या : मानसिक तनाव बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में व्यस्त रहेंगे। नौकरी में कार्य का दबाव बना रहेगा।

तुला : शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुखद रहेगी। नौकरी में स्थिति अनुकूल रहेगी।

वृश्चिक : नाते-रिश्तों में मनमुटाव हो सकता है। आर्थिक क्षेत्र में सावधानी बरतें। नौकरी में मन नहीं लगेगा।

धनु : प्रभावी व्यक्ति से जान-पहचान बढ़ेगी। नौकरी में उन्नति के संकेत मिल सकते हैं।

मकर : परिश्रम के चलते स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी में उन्नति का अवसर मिल सकता है।

कुंभ : मित्र सहायक रहेंगे। विकास का नया अवसर मिल सकता है। नौकरी में सम्मान बना रहेगा।

मीन : सहृदयता पर नियंत्रण रखें। नौकरी में वर्चस्व बढ़ेगा। व्यवसाय में विस्तार हो सकता है। विरोधी परास्त होंगे।

सुडोकू

					2			
				9			7	
5		9	3	4		6		
		7				4		
4	9	2				5	6	7
		5				3		
		6		5	4	7		1
	3			8				
			9					

1	4	8	7	6	2	9	5	3
6	2	3	5	9	8	1	7	4
5	7	9	3	4	1	6	2	8
3	1	7	6	2	5	4	8	9
4	9	2	8	1	3	5	6	7
8	6	5	4	7	9	3	1	2
9	8	6	2	5	4	7	3	1
7	3	4	1	8	6	2	9	5
2	5	1	9	3	7	8	4	6

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

उत्तर

चिंतन

नई उम्मीदें लेकर आएंगी नई सरकारें

विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद चार बड़े राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल और तमिलनाडु की है। इसकी अपनी वजह है कि चर्चा क्यों है। बंगाल में जहां पहली बार भाजपा तो तमिलनाडु में पहली बार अभिनेता से नेता बने विजय थलापति की तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) सरकार बनाने को तैयार हैं। अब इन नई सरकारों से लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हैं और सरकार पर इन उम्मीदों को पूरा करने का दबाव भी रहेगा। बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी सरकार ने हमेशा केंद्र सरकार के साथ टकराव किया। साथ ही उन बुराइयों और प्रवृत्तियों को भी दूर नहीं किया जो वाम सरकार के समय में प्रचलित थी। इससे लोगों में नाराजगी स्पष्ट तौर पर दिखाई दी और जनता ने दीदी को बंगाल की सत्ता से अलविदा कर दिया। अब ऐसे में लोग नई सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में बदलाव दिखाई देगा और केंद्र की योजनाओं का उन्हें भी लाभ मिलेगा। लोगों की सुनी जाएगी। वहीं, तमिलनाडु में भी एमके स्टालिन सरकार और केंद्र के बीच 36 का आंकड़ा रहा। वे राज्य में भाषा विवाद को बेवजह तूल देकर टकराव मौल लेते रहे। इसके कारण नई शिक्षा नीति को राज्य के स्कूलों में लागू नहीं किया जा सका और छात्र इस लाभ से वंचित रहे। अब लोगों को टीवीके से उम्मीद है कि राज्य के लोगों का कुछ भला होगा और उन्हें सभी योजनाओं के लाभ पारदर्शिता से मिलेंगे, भ्रष्टाचार खत्म होगा। वहीं, टीवीके ने भी केंद्र से सहयोग की बात कही है। इससे लगता है कि वह केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलेंगे और राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। हालांकि उनके सामने विधानसभा चुनाव में किए गए लोकलुभावन वादों को पूरा करने की चुनौती रहेगी। सभी वादे लागू करने में राज्य सरकार के खजाने पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक बोझ पड़ सकता है। केरल में भी कुछ ऐसा ही हाल कांग्रेस का होगा। उसके सामने भी नई शिक्षा नीति को लागू करने की चुनौती होगी। हालांकि राज्य के लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नई सरकार उन्हें सभी योजनाओं का लाभ देगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। जिस तरह का बदलाव इन तीन राज्यों में हुआ है, इससे नई सरकारों पर भी जन आकांक्षाओं को पूरा करने का दबाव रहेगा। इसके बावजूद केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी तो निश्चय ही लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकेगा और बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। असम में भाजपा की वापसी हुई है। यहां भी लोगों को उम्मीद है कि जो योजनाएं और लोगों को राहत देने के उपाय किए गए थे, वे लगातार जारी रहेंगे। इसके अलावा बाढ़मुक्त असम, रोजगार, महिला एवं युवा सशक्तिकरण पर भी सरकार ध्यान देगी। पुडुचेरी में राजग का नेतृत्व करने वाली सरकार पर पर्यटन विकास, कृषि, ऋण माफी और राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा समेत लोगों के विकास की योजनाओं को पूरा किए जाने की उम्मीद होगी। कुल मिलाकर नई सरकारों के सामने जन अपेक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरना सबसे बड़ी चुनौती होगी। जनता बदलाव, पारदर्शिता, विकास और केंद्र-राज्य समन्वय की उम्मीद कर रही है। यदि ये सरकारें राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करें, तो आम लोगों के जीवन में वास्तविक सुधार संभव है। अंततः सफलता उसी सरकार की मानी जाएगी जो विश्वास, विकास और सुशासन के माध्यम से जनता की उम्मीदों को हकीकत में बदल सके।

'परफॉर्मेंस की राजनीति' की जीत

विश्लेषण
डॉ. ओ.पी. त्रिपाठी

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजों में से दो नतीजे बड़े बदलाव के बारे में बताते हैं। एक नतीजा निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का है, जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। दूसरा बड़ा बदलाव तमिलनाडु में देखने को मिला है, जहां महज दो साल पहले गठित राजनीतिक पार्टी ने चुनावी जीत दर्ज की है और विजय हीरो के रूप में उभरे हैं। बंगाल में 1977 में कांग्रेस का दुर्ग ढहा था। वाम मोर्चे की पहली सरकार बनी थी। 2011 में 34 साल लंबी सत्ता को, 'लाल किले' को, ममता बनर्जी ने ध्वस्त किया और एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई। ममता की 15 साल पुरानी सत्ता इस बार ढह गई और भाजपा 'परिवर्तन की प्रतीक' बनकर उभरी है।

चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के नतीजों में से दो नतीजे बड़े बदलाव के बारे में बताते हैं। एक नतीजा निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का है, जहां भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। दूसरा बड़ा बदलाव तमिलनाडु में देखने को मिला है, जहां महज दो साल पहले गठित राजनीतिक पार्टी ने चुनावी जीत दर्ज की है और विजय हीरो के रूप में उभरे हैं। बंगाल में 1977 में कांग्रेस का दुर्ग ढहा था। वाम मोर्चे की पहली सरकार बनी थी। 2011 में 34 साल लंबी सत्ता को, 'लाल किले' को, ममता बनर्जी ने ध्वस्त किया और एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत हुई। ममता की 15 साल पुरानी सत्ता इस बार ढह गई और भाजपा 'परिवर्तन की प्रतीक' बनकर उभरी है।

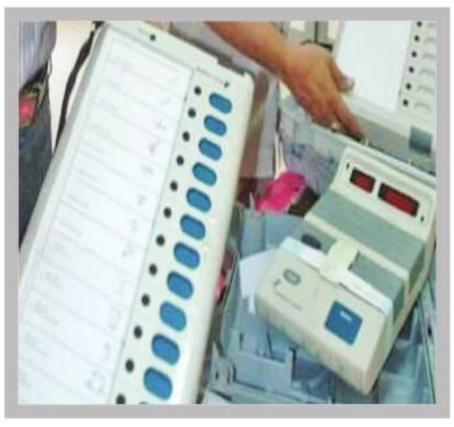

भाजपा ऐसे राज्य में सत्तारूढ़ हो रही है, जहां वह श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 'जनसंघ' के दिनों से प्रयास कर रही थी। बंगाल ने प्रधानमंत्री मोदी की गारंटियों, गृहमंत्री अमित शाह की चुनावी नीतियों तथा सूक्ष्म,माइक्रो स्तर पर काडर की रणनीति को जनादेश दे ही दिया। मतगणना के अंतिम आंकड़ों से साफ है कि पश्चिम बंगाल में जनादेश कितना ऐतिहासिक और प्रचंड है। असम में भी भाजपा की सत्ता बरकरार रही है, क्योंकि लगातार तीसरी बार उसे जनादेश हासिल हो रहा है। तमिलनाडु ने चौंकाया है। वहां सत्तारूढ़ रही द्रमुक के खिलाफ जनादेश दिया गया है और सुपरस्टार विजय की नवजात पार्टी टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। दूसरे स्थान पर सत्तारूढ़ पार्टी डीएमके रही। वहीं अन्नाद्रमुक-भाजपा गठबंधन तीसरे स्थान पर रहा। तमिलनाडु की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर वर्तमान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का हार जाना रहा। जाहिर है, उदयनिधि के सनातन धर्म पर दिए गए विवादित बयानों ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की तरह तमिलनाडु में भी विश्वविद्यालयों से जुड़े दुष्कर्म के मामलों ने सुर्खियां बटोरीं। तमिलनाडु में दो ध्रुवीय द्रविड़ राजनीति सत्ता से बाहर हुई है। छह दशक बाद राज्य में गैर द्रविड़यिन सरकार बनने जा रही है। हालांकि, अभी सत्ता में आने के लिए टीवीके को गठबंधन का सहारा लेना होगा। इस चुनावी नतीजे के साथ ही डीएमके के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है, मुख्य रूप से विजय की पार्टी टीवीके के उभार के कारण। यह स्थिति 1996 के विपरीत है, जब डीएमके को 173 सीटों के साथ भारी जीत मिली थी। डीएमके की उस जीत में रजनीकांत का समर्थन महत्वपूर्ण था, लेकिन आज परिदृश्य पूरी तरह बदल चुका है। चार मई का जनादेश तमिलनाडु के 39 सांसदों के लिए भी एक जनमत संग्रह जैसा है-क्या उन्होंने आठ करोड़ तमिलों के विकास के लिए पर्याप्त काम किया? केरलम में वाम मोर्चे की लगातार 10 साल की सत्ता के बाद इस बार जनता ने उसे भी बदल दिया है और कांग्रेस नेतृत्व के यूडीएफ को जनादेश दिया है। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम वाम दलों के लिये दुःस्वप्न ही साबित हुए हैं, केरलम में उनका आखिरी गढ़ भी हाथ से निकल गया है। हालांकि, केरलम में भाजपा ने तीन व तमिलनाडु में एक सीट जीतकर हिंदी बेल्ट की पार्टी के ठप्पे से मुक्त होने का प्रयास किया है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का नतीजा अपेक्षा के अनुरूप ही रहा। वहां एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया और भाजपा तथा एनआर कांग्रेस के

गठबंधन को जनता का समर्थन मिला। पुडुचेरी में अमित शाह के लगातार दौरे ने भी एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। देश में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल के नतीजों की है। मोदी-शाह की आक्रामक रणनीति के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यकर्ता स्तर पर गहन अभियान चले। फिलहाल, गंगोत्री से गंगासागर तक भाजपा का शासन हो गया है। गंगा के प्रवाह के साथ बहने वाले झारखंड को छोड़ दें तो बाकी राज्य भगवामय हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफलता को 'परफॉर्मेंस की राजनीति' की जीत बताते हुए कहा कि आज बंगाल के भाग्य में एक नया और भयमुक्त अध्याय जुड़ गया है। इन विधानसभा चुनाव परिणामों का निष्कर्ष यह भी है कि अब क्षेत्रीय क्षत्रपों की मुखर आवाज कुंद हो गई है। जहां ममता,स्टालिन व विजयन सत्ता से बाहर हो गए हैं, वहीं शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक का प्रभाव भी फीका हुआ है। वर्तमान विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद देश का 72 फीसदी भूभाग व 78 फीसदी आबादी भाजपा शासित है। अनुमान है कि अब भाजपा 'एक देश, एक चुनाव' के मुद्दे पर मुखर हो सकती है। कयास बंगाल को लेकर भी हैं कि वहां आंदोलनों के अगुवा रहे सुवेंदु अधिकारी को सत्ता की बागडोर सौंपी जाएगी, या भाजपा कोई चौंकाने वाली पहल करती है। बहरहाल, पहले से ही कमजोर विपक्ष को यह परिणाम बड़ा झटका है। कांग्रेस व वाम दलों से किनारा करके चलने की ममता की महत्वाकांक्षी कोशिश का लाभ भाजपा को मिला है। हां, इतना जरूर है कि दक्षिण भारत में पकड़ बनाने के लिए भाजपा को कड़ी मेहनत करनी होगी। इस बार उसे केरल की तीन व तमिलनाडु की एक सीट पर ही संतोष करना पड़ा है। वहीं केरलम में वाम मोर्चे के अंतिम किले का ध्वस्त होना और लगातार टकराव के मूड में रहने वाले स्टालिन की विदाई उसका उत्साह बढ़ाने वाले हैं। बहरहाल, भाजपा को आने वाले समय में पंजाब में कड़ा मुकाबला करना पड़ेगा, जहां आम आदमी पार्टी व कांग्रेस अपनी जमीन मजबूत करने के प्रयासों में लगे हैं। बहरहाल, विगत में राजनीतिक हिंसा का इतिहास रखने वाले पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान उपजी कटुता को नियंत्रित करने के प्रयास बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के करने होंगे। निस्संदेह, लोकतंत्र में हिंसा की कोई भूमिका नहीं स्वीकारी जानी चाहिए। विश्वास करें कि नई सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिशोध को संरक्षण नहीं दिया जाएगा। ममता बनर्जी के लिए यह बहुत बड़ी हार है। अगर वह चौथी बार चुनाव जीततीं, तो प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार होतीं, लेकिन भ्रष्टाचार और आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले ने उनकी छवि कमजोर की। हिंदी भाषी न होने के कारण ममता बनर्जी के लिए आने वाले समय बेहद चुनौती भरे हैं। अपनी हार के लिए वह चुनाव आयोग और एसआइआर को जिम्मेदार ठहरा सकती हैं, पर ऐसे में, कामकाज की उनकी शैली और भ्रष्टाचार पर भी सवाल उठेंगे। यह याद रखना चाहिए कि पहले वह एनडीए में थीं और वाजपेयी सरकार में रेल मंत्री रह चुकी थीं। हालांकि यह मानना कठिन है कि वह फिर से एनडीए के साथ अपने रिश्ते सुधारेंगी। बंगाल में हार के साथ ही 2029 के लोकसभा चुनाव में उनकी लड़ाई कठिन हो गई है। ममता के लिए अपने 39 लोकसभा सांसदों पर नियंत्रण बनाए रखना भी कठिन होगा। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की चूंकि 42 सीटें हैं, लिहाजा यह चुनाव जीतकर भाजपा ने 2029 में अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली है। चार मई के चुनाव परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि डिजिटल क्रांति अपने चरम पर है। अब सोशल मीडिया टेलीविजन के बराबर या उससे भी अधिक प्रभावशाली हो चुका है।

(लेखक चिकित्सक हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

जयंती विशेष

महेन्द्र तिवारी

गीत, ज्ञान और मानवता के कवि रवींद्रनाथ टैगोर

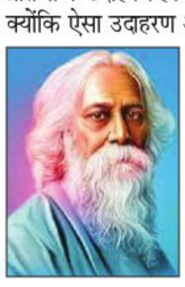

रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था और यह तिथि भारतीय इतिहास और संस्कृति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बंगाली परंपरा में उनकी जयंती वैशाख महीने के 25वें दिन (पचीशे बैसाख) को मनाई जाती है, जो हर वर्ष ग्रेगोरियन कैलेंडर में अलग तिथि पर आती है, परंतु 2026 में यह 7 मई को ही पड़ रही है। यह संयोग केवल तिथियों का मेल नहीं है, बल्कि यह उस सांस्कृतिक निरंतरता का प्रतीक है, जिसमें समय बदलता है पर मूल्य स्थिर रहते हैं। टैगोर का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जो साहित्य, कला और सामाजिक चेतना का केंद्र था, और यही परिवेश उनके व्यक्तित्व के निर्माण में निर्णायक सिद्ध हुआ। रवींद्रनाथ टैगोर को विश्वकवि कहा जाता है और यह उपाधि केवल सम्मान नहीं बल्कि उनकी रचनात्मकता की व्यापकता का प्रमाण है। 1913 में उन्हें उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, जिससे वे इस सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय बने। यह उपलब्धि न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी, बल्कि यह भारतीय साहित्य के वैश्विक स्वीकार का भी क्षण था। गीतांजलि में निहित आध्यात्मिकता, प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और मानवीय भावनाओं की गहराई ने दुनिया भर के पाठकों को प्रभावित किया। उनकी भाषा सरल होते हुए भी गहन थी और उनके विचार सीमाओं से परे जाकर मानवता की एकता की बात करते थे। टैगोर की सबसे विशिष्ट पहचान यह है कि उनकी रचनाएँ दो देशों के राष्ट्रगान बनीं। भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला उनकी ही काव्य प्रतिभा के उदाहरण हैं। यह तथ्य उन्हें विश्व साहित्य में एक अनूठा स्थान देता है, क्योंकि ऐसा उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलता। उनकी रचनाओं में देशभक्ति का

स्वर था, परंतु वह संकीर्ण राष्ट्रवाद से परे था। वे मानवता को किसी एक देश या सीमा में बांधकर नहीं देखते थे, बल्कि उनकी दृष्टि वैश्विक थी। वे मानते थे कि सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो मानवता का सम्मान करे और सभी के लिए समान अवसर और सम्मान की बात करे। संगीत के क्षेत्र में भी टैगोर का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रवींद्र संगीत की परंपरा को विकसित किया जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और लोकधुनों का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। उनके गीतों में भावनाओं की गहराई, प्रकृति के प्रति प्रेम और जीवन के विभिन्न रंगों का चित्रण मिलता है। आज भी उनके गीत बंगाल और पूरे भारत में गाए जाते हैं और उनकी लोकप्रियता समय के साथ और बढ़ी है। उनके द्वारा रचित धुनें केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि वे आत्मा को छूने वाली अनुभूति प्रदान करती हैं। टैगोर का दृष्टिकोण केवल साहित्य और संगीत तक सीमित नहीं था, बल्कि वे एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक भी थे। उन्होंने शांतिनिकेतन की स्थापना इस उद्देश्य से की कि शिक्षा प्रकृति के सान्निध्य में दी जाए और विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने और सीखने का अवसर मिले। बाद में यही संस्थान विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, जो आज भी उनके आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता है। उनका मानना था कि शिक्षा केवल जानकारी प्राप्त करने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के भीतर की संवेदनशीलता, रचनात्मकता और नैतिकता को विकसित करने का साधन है। वे शिक्षा को जीवन से जोड़कर देखते थे और चाहते थे कि विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित न रहें बल्कि प्रकृति और समाज से भी सीखें। उनके विचारों में मानवतावाद की गहरी भावना थी। वे राष्ट्रवाद के अंधानुकरण के विरोधी थे और मानते थे कि यदि राष्ट्रवाद मानवता के विरुद्ध हो जाए तो वह विनाशकारी बन सकता है। उनके लेखन में यह स्पष्ट दिखाई देता है कि वे विश्व शांति, सहिष्णुता और भाईचारे के पक्षधर थे। उन्होंने अपने समय की सामाजिक कुरीतियों, अंधविश्वासों और असमानताओं पर भी तीखा प्रहार किया। उनके उपन्यास, कहानियां और नाटक समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं और पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। वे कवि, लेखक, संगीतकार, चित्रकार और दार्शनिक सभी कुछ थे। टैगोर केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक जीवित प्रेरणा हैं, जिनकी रचनाएं और विचार आज भी हमें बेहतर मनुष्य बनने की ओर प्रेरित करते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सृजन, संवेदना और शिक्षा के माध्यम से हम दुनिया को अधिक सुंदर और मानवीय बना सकते हैं।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

क्षमा करें और भूल जाएं

संकलित
दर्शन

जीवन में हमें कई बार चुनौतियों और निराशाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में हमारा किसी न किसी ऐसी घटना से साक्षात्कार होता है, जो हमें पसंद नहीं होती या जिसके कारण हमें दुख होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने हमारा किसी तरह अनुचित किया हो, शब्दों से हमें भावनात्मक रूप से दुख पहुंचाया हो या शारीरिक कष्ट पहुंचाया हो। परिणाम यह होता है कि हम निराश, दुखी और क्रोधित हो जाते हैं। जब तक हम किसी को क्षमा नहीं करते, तब तक हमारे साथ क्या होता है? हम हमेशा उसी घटना के बारे में सोचते रहते हैं या किसी और से भी उन बातों को दोहराते रहते हैं। कुछ लोग जिनका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता, वे शारीरिक रूप से उस व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं या अपना क्रोध किसी और पर निकालते हैं। ऐसा होने पर हम अपने चारों ओर नकारात्मक वातावरण पैदा कर लेते हैं। अपने मन की शांति खो देते हैं। कुछ क्षणों में घटित हुई घटना के लिए हम अपने जीवन के तमाम घंटे इस बात में लगा देते हैं कि उसका बदला कैसे लें। यदि हम इसके बजाय क्षमा कर दें तो हम इस समय का शांतिपूर्वक सदुपयोग कर सकते हैं। हम अपना ध्यान उस ओर लगाएं, जो आध्यात्मिक रूप से मददगार हो। जैसे कि पिता-परमेश्वर को याद करना, ध्यान-अभ्यास करना, निष्काम सेवा करना और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना। आध्यात्मिक मार्ग पर ध्यान-अभ्यास में सफलता अपने मन को स्थिर करके अंतर में ध्यान टिकाने पर निर्भर है। हमारे ध्यान-अभ्यास में जो सबसे बड़ी बाधा है, वह है ऐसा कुछ होना जो हम नहीं चाहते और जिसे हम भुला नहीं पाते।

भगवान जी आप अपना ध्यान रखना

संकलित
प्रेरणा

एक बच्चा रोज अपने दादा जी को सायंकालीन पूजा करते देखता था। बच्चा भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान को पूर्ण करने की इच्छा रखता था, किन्तु दादा जी की उपस्थिति उसे अवसर नही देती थी।एक दिन दादा जी को शाम को आने में विलंब हुआ, इस अवसर का लाभ लेते हुए बच्चे ने समय पर पूजा प्रारम्भ कर दी। जब दादा जी आये, तो दीवार के पीछे से बच्चे की पूजा देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती एवं अन्य सभी सामग्री का अनुष्ठान में यथाविधि प्रयोग करता है और फिर अपनी प्रार्थना में कहता है। भगवान जी प्रणाम ! आप मेरे दादा जी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटनो के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा-दादी को कुछ हो गया, तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर आगे कहता है, भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा। फिर मेरे पापा और मम्मी को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया, तो घर को चोरों से कौन बचाएगा। लेकिन भगवान यदि आप बुरा न मानो तो एक बात कहू, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया, तो हम सबका क्या होगा। इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादा की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने कभी नहीं की थी। हमें उन परमपिता का हमेशा आभारी होना चाहिए जिन्होनें हमें बिना माँगे सब कुछ दिया है।

अंतर्मन

आज की पाती

विकास के लिए हुआ बंपर मतदान

हाल ही में देश के पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का परिणाम इसलिए अलग सा था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद भाजपा को पहली बार यहां विधानसभा चुनाव में प्रचंड रूप से जीत हासिल हुई। इस जीत ने एक बात तो यह भी साफ कर दी कि मतदाता अब धर्म और जाति को नहीं, बल्कि देश और प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर अपने कीमती मत का प्रयोग करने लगा है। पश्चिम बंगाल में इस बार मुस्लिम वोट भाजपा को कम नहीं मिले होंगे, तभी तो भाजपा को यहां इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लग रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी ने उनका विरोध किया था, जबकि राम तो सभी के हैं। *- प्रतीक अग्रवाल, डोंगरगढ़*

ट्रेंड

एफआरपी स्वीकृत

मोदी सरकार ने गन्ना किसानों के हित में 365 रुपये प्रति क्विंटल का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) स्वीकृत किया है। इससे 5 करोड़ से अधिक गन्ना किसानों को लाभ मिलेगा।
-अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री

जनादेश की भावना

बंगाल में लोकतंत्र को बंदूक की नोक पर रखा जा रहा है और चुनावी नतीजों को मानने से इनकार करना इस वास्तविकता को स्पष्ट कर देता है। ममता ऑफिशियल द्वारा जनादेश की भावना को स्वीकार करने से इनकार करना एक गंभीर प्रश्न उठाता है।
- धर्मेन्द्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री

अंत्योदय गृह योजना

जनता की सरकार ओडिशा के हर क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। अंत्योदय गृह योजना के माध्यम से, हर मजबूत घर के साथ एक सुरक्षित भविष्य का निर्माण हो रहा है। यह सिर्फ एक घर नहीं है; इसके साथ ही विश्वास, आस्था और नई उम्मीद की शुरुआत भी हो रही है।
- मोहन चरण माझी, सीएम, ओडिशा

सरकार का झूठ उजागर

राजस्थान में सत्ताधारी दल के विधायक भी अब सरकार के दावों में छिपे झूठ को उजागर कर रहे हैं। गोगुंदा से भाजपा विधायक प्रताप गमेती का कहना कि "आंगनवाड़ी के लिए तैयार पोषक तत्वों को जानवर भी नहीं खाएंगे," बेहद चिंताजनक है।
- अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

करंट अफेयर

सिंगापुर में भारतीय मूल के कंपनी निदेशक पर जुर्माना

सिंगापुर की एक कंपनी के भारतीय मूल के निदेशक को यहां की एक अदालत ने अक्टूबर 2018 और फरवरी 2024 के बीच एक पोर्श सहित आयातित वाहनों के मूल्य को कम बताने से संबंधित विभिन्न अपराधों के लिए 10 लाख सिंगापुर डॉलर (785,314 अमेरिकी डॉलर) से अधिक का जुर्माना लगाया है और दो महीने की जेल की सजा सुनाई है। कार कंपनी 'कॉनकॉर्डवे' के निदेशक थियांबरावट्टा सुभाष इंद्रजीत ने सीमा शुल्क अधिनियम के तहत नौ आरोपों को स्वीकार किया, जिसमें 34 आयातित वाहनों पर 161,251 सिंगापुर डॉलर से अधिक मूल्य के शुल्क की चोरी करने का आरोप भी शामिल है। सजा सुनाते समय 10 अन्य आरोपों पर भी विचार किया गया जिनमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और जीएसटी बचाने के लिए धोखाधड़ी करने और झूठी जानकारियां देना शामिल हैं। सिंगापुर सीमा शुल्क और भूमि परिवहन प्राधिकरण (एलटीए) ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान में कहा कि 24 अप्रैल को उसे सजा सुनाई गई। सिंगापुर निवासी 59 वर्षीय सुभाष इंद्रजीत को सीमा शुल्क संबंधी अपराधों के संबंध में जुर्माना अदा करने के लिए 25 मई तक का समय दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर उसे 12 महीने और दो सप्ताह की जेल की सजा भुगतनी होगी।

ऑफ बीट

कोआला की नई जीवाश्म प्रजाति का पता चला

वर्ष 2024 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन म्यूजियम को मार्गरेट रिवर की मूनडाइन गुफा से अन्वेषक लिंडसे हैचर द्वारा खोजा गया कोआला की खोपड़ी का एक नमूना दिया गया। इस खोपड़ी में कुछ असामान्य था, जिसे शोधकर्ताओं ने पहचान लिया। इस कोआला की खोपड़ी पर गड्ढेनुमा निशान थे। कोआला ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में लगभग विलुप्त हैं। हालांकि जीवाश्म साक्ष्य बताते हैं कि कोआला कभी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में रहते थे, जिनमें मार्गरेट रिवर से लेकर उत्तर में यानचेप और पूर्व में मदुरा तक के क्षेत्र शामिल हैं। रॉयल सोसाइटी ओपन साइंस में आज प्रकाशित एक नए अध्ययन में शोधकर्ताओं ने बताया कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के ये कोआला आधुनिक कोआला की भटकी हुई आबादी नहीं थे, बल्कि एक अलग प्रजाति थे, जिसके बारे में एक सदी से अधिक समय तक किसी को पता नहीं चला। ज्ञात कोआला से अलग पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कोआला के जीवाश्म पहली बार 1910 में मार्गरेट रिवर के पास मैमथ गुफा में मिले थे। हालांकि लगभग एक सदी तक अधिकतर नमूने केवल अलग-अलग जबड़ों और दांतों तक सीमित रहे।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

पवन खेड़ा बोले- जिन सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर के तहत काटे गए नामों की संख्या से कम, वहां पुनर्मतदान हो, सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले

कांग्रेस का दावा- भाजपा ने पश्चिम बंगाल में धांधली कर करीब 100 सीटें जीतीं

असम चुनाव में हुई धांधली का मुद्दा भी उठाया, कहा- भाजपा ने मतदाता सूची में हेरफेर, एसआईआर और परिसीमन के जरिए पूरी चुनावी प्रक्रिया को कब्जे में लिया

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

कांग्रेस ने भाजपा पर असम और पश्चिम बंगाल में चुनावी धांधली, मतदाता सूची में हेरफेर, एसआईआर तथा परिसीमन के जरिए चुनावी प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप लगाया है। पार्टी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने चुनाव आयोग की मिलीभगत से करीब 100 सीटों पर धांधली कर जीत हासिल की है।

कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए पार्टी के मीडिया और पब्लिसिटी के चेयरमैन पवन खेड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जिन सीटों पर जीत का अंतर एसआईआर के तहत काटे गए मतदाताओं की संख्या से कम है, वहां दोबारा मतदान होना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर मतदाताओं को उनके वोट का अधिकार फिर से देगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि इंडिया गठबंधन लोकतांत्रिक संकट के समय तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है।

उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी धांधली को लेकर तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में स्पष्ट सैद्धांतिक रुख लिया है। उन्होंने बताया कि साजिश के तहत पश्चिम बंगाल में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान चुनावी सूचियों से 91 लाख मतदाताओं के नाम हटा दिए गए, जबकि 27 लाख नागरिकों को किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखने का बुनियादी प्रक्रियात्मक अधिकार भी नहीं दिया गया।

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हो रही हिंसा पर पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा जीत की खुशी नहीं मना रही, बल्कि गुंडागर्दी कर रही है। उन्होंने कहा कि विरोधी दलों के दफ्तर जलाए जा रहे हैं, उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, दुकानें तोड़ी जा रही हैं और डीजे सिस्टम पर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद के अनुरूप आचरण करना चाहिए और हिंसा रोकनी चाहिए। खेड़ा ने कहा कि भाजपा ने मुस्लिम वोटरों को ठुकराया तो मुस्लिम वोटरों ने भाजपा को ठुकरा दिया। ऐसे में जब मुसलमानों ने कांग्रेस जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टी को वोट दिया तो भाजपा को उसमें भी शिकायत होने लगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या बाबा साहेब डॉ भीम राव अंबेडकर का संविधान ऐसी सोच और राजनीतिक संस्कृति की इजाजत देता है? उन्होंने भाजपा पर करारा पलटवार करते हुए कहा कि देशभर में कांग्रेस के 664 विधायकों में से 78 प्रतिशत हिंदू हैं और 12 प्रतिशत मुस्लिम हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आबादी के अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देती आई है, जबकि भाजपा देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं समेत हर वर्ग को कमजोर करना चाहती है।खेड़ा ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को बहुमत नहीं मिलने के बाद चुनावी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश रची गई। उन्होंने याद दिलाया कि राहुल गांधी पहले ही हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक जैसे राज्यों में मतदाता सूची में गड़बड़ी और वोट चोरी के मुद्दे उठा चुके हैं। उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां पांच महीने में 40 लाख नए मतदाता जोड़े गए, जबकि बंगाल और असम में लाखों मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए, जो भाजपा के पारंपरिक मतदाता नहीं माने जाते हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा द्वारा चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में हेरफेर, एसआईआर और परिसीमन के जरिए पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने कब्जे में ले लिया गया है।भाजपा के चुनावी मॉडल पर कटाक्ष करते हुए पवन खेड़ा ने कहा कि जहां-जहां कीचड़ फैलाया गया, वहीं कमल खिला। उन्होंने कहा कि दक्षिण के राज्यों जैसे तमिलनाडु और केरल में यह कीचड़ नहीं फैल पाया, इसलिए वहां भाजपा सफल नहीं हुई।

खबर संक्षेप

पवन खेड़ा ने हिमंत सरमा को 'दोस्त' कहा

नई दिल्ली। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा और हिमंत बिस्वा सरमा के बीच हाल में हुआ विवाद सुर्खियों में रहा है।

लेकिन, सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद पवन खेड़ा जब पहली बार कांग्रेस के आधिकारिक प्रेस कांफ्रेंस में आए तो उनके सुर ही बदले हुए लग रहे थे। बिना नाम लिए असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को अपना 'दोस्त' भी बताने की कोशिश की। पवन खेड़ा ने उन आरोपों पर भी सफाई देने की कोशिश की है कि असम में कांग्रेस के जो 19 उम्मीदवार जीते हैं, उनमें 18 मुसलमान ही क्यों हैं।

महिला पुलिस कमिश्नर ने मनचलों को पकड़ा

अमरावती। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मल्काजगिरि पुलिस कमिश्नर बी. सुमति ने देर रात

करीब 2 बजे अकेले बस स्टॉप पर खड़ी रहीं और मनचलों को जाल में फंसाया। इस दौरान करीब 40 लोगों को हिरासत में लिया गया। दिलसुखनगर बस स्टॉप के आसपास हॉस्टल क्लस्टर होने के चलते रात में महिला यात्री अक्सर नशे में धुत लोगों का शिकार बनती थीं। सुमति ने देर रात से सुबह 3 बजे तक वे सामान्य महिला यात्री बनकर बस स्टॉप पर खड़ी रहीं और उनको अश्लील बातें कहने वाले 40 मनचलों को पकड़ा।

इमारत में आग से बच्ची समेत 3 की मौत

भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में बुधवार तड़के एक रिहायशी इमारत में भीषण आग

लगने से एक बच्ची समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और करीब 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के अनुसार, आग सुबह करीब 4 बजे लक्ष्मीसागर इलाके स्थित बसंती विला अपार्टमेंट की ग्राउंड फ्लोर पर लगी। देखते ही देखते आग और धुआं पूरे भवन में फैल गया।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू

9 मई को भाजपा का भव्य समारोह, ब्रिगेड ग्राउंड में होगा आयोजन, दो दर्जन मंत्री भी लेंगे शपथ

एजेंसी ⏭ कोलकाता

पीएम सहित भाजपा के सभी सीएम होंगे शामिल

8 मई की शाम को विधायक दल की बैठक होगी

कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में जोर-शोर से आयोजन की तैयारियां हो रहीं

पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शुरू होगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, शपथ समारोह में प्रधानमंत्री, एनडीए व भाजपा के सभी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे।

दो दर्जन मंत्री भी शपथ लेंगे। शपथग्रहण समारोह बंगाली पंचांग के बैसाख महीने के 25वें दिन आयोजित किया जाएगा जिसे पूरे राज्य में रवींद्र जयंती के रूप में मनाया जाता है, जो रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती है। इससे कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रतीकात्मकता की झलक नजर आएगी।

राजनीतिक हलकों में इस तारीख के चयन को भाजपा द्वारा बंगाल की सांस्कृतिक परिकल्पना में अपने ऐतिहासिक उदय को स्थापित करने और तृणमूल कांग्रेस द्वारा इसे बंगाल की भाषाई एवं बौद्धिक लोकाचार से अलग 'बाहरी लोगों की पार्टी' बताए जाने का मुकाबला करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल की जनता ने पीएम मोदी और गृहमंत्री शाह पर भरोसा जताया:बिप्लब

भाजपा की जीत के बाद बंगाल से दिल्ली पहुंचे बिप्लब देब का हरियाणा और दिल्ली के कार्यकताओं ने किया अभिनंदन

हरिभूमि ब्यूरो, नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में भाजपा को पहली बड़ी जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव सह प्रभारी एवं सांसद व त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दिल्ली पहुंचकर नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें इन

परिणामों पर कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता भी प्रधानमंत्री पर विश्वास करती है और भाजपा की यह जीत इसी विश्वास का परिणाम है।भाजपा नेता बिप्लब देब ने कहा कि साल 2021 में भी भाजपा सरकार बनने की स्थिति थी, लेकिन कोविड काल का बहाना बनाकर लोगों को वोट देने से टीएमसी सरकार द्वारा रोका गया। इस बार परिस्थितियां अलग रहीं और जनता ने खुलकर अपना फैसला दिया। पूरे देश की तरह पश्चिम बंगाल की जनता ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह पर विश्वास जताया और बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। उन्होंने चुनाव आयोग की सराहना और धन्यवाद करते हुए कहा कि उनकी वजह से रिकॉर्ड मतदान संभव हो पाया और जनता की वास्तविक राय सामने आई। बिप्लब देब ने केंद्र और राज्य में एक जैसी सरकार का दावा करते हुए कहा कि करीब 50 वर्षों बाद केंद्र और बंगाल में एक ही विचारधारा की सरकार बनी है, जो राज्य के विकास के लिए बड़ा अवसर है। बंगाल के विकास पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में अपार संभावनाएं हैं और इसे एक शक्तिशाली राज्य बनाना जरूरी है। बंगाल की क्षमता पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकती है। देब के बयान से साफ है कि भाजपा इस जीत को जनता के भरोसे और मजबूत लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिणाम मान रही है, और अब बीजेपी का फोकस बंगाल के विकास पर रहेगा।

टीएमसी जैसा व्यवहार ना करें, सयंम रखें भाजपा कार्यकर्ता: सुकांत मजूमदार

हरिभूमि ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने टीएमसी कार्यालयों पर कथित हमलों के बीच भाजपा कार्यकर्ताओं से संयम रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि भाजपा को अपना चरित्र बनाए रखना चाहिए और रावण बनने से बचना चाहिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणामों के बाद राजनीतिक माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि पुलिस इन मामलों में कार्रवाई करेगी। उन्होंने दोहराया कि भाजपा को अपने सिद्धांतों पर अडिग रहना चाहिए। मजूमदार ने कहा कि वे भगवान राम के अनुयायी हैं। उन्हें रावण की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। भाजपा को भाजपा ही रहना होगा। सुकांत मजूमदार ने साफ कहा कि भाजपा को अपनी राजनीतिक पहचान बनाए रखनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में हिंसा का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। मजूमदार ने कहा कि लोगों ने टीएमसी को अस्वीकार कर दिया है, इसलिए भाजपा को उनके जैसा आचरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्वीकार किया कि स्थानीय लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ लगातार अत्याचार हुए हैं। हालांकि, उन्होंने कार्यकर्ताओं से धैर्य रखने का आग्रह किया। हाल ही में पश्चिम बंगाल के आसनसोल और हावड़ा में तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, इन घटनाओं में फर्नीचर, पोस्टर और झंडे तक नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा कूचबिहार में भी राजनीतिक टकराव की स्थिति देखने को मिली, जहां दोनों दलों के समर्थकों के बीच तनाव बढ़ा। बंगाल चुनाव परिणामों के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन के साथ ही राजनीतिक संघर्ष तेज हो गया है। टीएमसी और भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में तनाव की स्थिति बनी हुई है।

बंगाल में हिंसा की घटनाओं पर केंद्रीय मंत्री सुकांत ने दी भाजपा कार्यकर्ताओं को नसीहत

तमिलनाडु में कांग्रेस के समर्थन से बनेगी टीवीके सरकार, डीएमके ने इंडी अलायंस से नाता तोड़ा

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

हरिभूमि फॉलोअप

कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने तमिलनाडु प्रदेश कांग्रेस कमेटी की मांग पर मुहर लगा दिया। कांग्रेस, टीवीके गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में बनेगी। कांग्रेस के टीवीके के साथ जाने के फैसले से नाराज डीएमके ने विपक्षी गठबंधन से खुद को अलग कर लिया। दशकों पुराना डीएमके का साथ कांग्रेस से छूटा तो सुबाई सियासत में कांग्रेस को नया नेवला साथी टीवीके नेता विजय के रूप में मिला।

डीएमके नेता एमके स्टालिन नहीं चाहते थे कि कांग्रेस टीवीके को पनपने का मौका दे। उन्हें इस बात का इल्म है कि बतौर फिल्मी सुपरस्टार विजय की प्रसिद्धि जिस तरह से उन्हें महज तीन साल में सीएम की कुर्सी तक पहुंचाने में सफलता दिलाई है उसी तरह अगर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का साथ टीवीके को मिला तो डीएमके का भविष्य खतरे में पड़ सकता है!

मगर कांग्रेस नेतृत्व ने तमिलनाडु में साथी बदलने का निर्णय करते हुए विजय के साथ जाने का फैसला किया। कांग्रेस विधायक दल के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने टीवीके के साथ जाने का फैसला किया। जिस पर शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली में मुहर लगा दिया। इस फैसले के पहले जबरदस्त रस्साकसी कांग्रेस के भीतर मची। एक वर्ग चाहता था डीएमके के साथ रहा जाए जबकि दूसरा धड़ा, बदलते राजनीतिक परिदृश्य में टीवीके के साथ जाने की पैरवी कर रहा था।

पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने हरिभूमि को बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और पी. चिदंबरम जैसे नेता टीवीके के साथ जाने के फैसले के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाए पुराने साथी डीएमके को पहले विश्वास में लेना चाहिए। मगर, बड़े नेताओं के किंतु - परंतु की धराशाई करने में राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले डेटा विश्लेषक प्रवीण चक्रवर्ती, के सी वेणुगोपाल और तमिलनाडु के सभी वरिष्ठ नेताओं ने सफलता पाई। सभी ने एक सुर में टीवीके के साथ जाने का फैसला तुरंत लेने की जरूरत पर बल दिया। और फैसला हो गया। इससे पहले टीवीके की ओर से खुद विजय और उनके पिता ने कांग्रेस नेतृत्व से समर्थन का आग्रह किया था। सरकार के आकार प्रकार और मंत्रिमंडल में सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने के बाद विजय बतौर मुख्यमंत्री तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में नई इबारत लिखेंगे।

राज्यपाल से मिले विजय, सरकार बनाने का दावा

तमिलनाडु विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद तमिलगा वेत्री कड़गम (टीवीके) के प्रमुख विजय ने आज लोकभवन में जाकर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। लेकिन लोकभवन के सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल विजय के बहुमत वाले दावे से संतुष्ट नहीं है। इसी बीच 16वीं तमिलनाडु विधानसभा को 5 मई 2026 से भंग करने का निर्णय लिया गया। एआईएडीएमके ने टीवीके को समर्थन से इनकार किया है।

सांसद सैलजा ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर उठाए सवाल

हरियाणा में स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार का बोलबाला, बुनियादी सुविधाएं नदारद: सैलजा

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार स्थानीय स्तर पर पूरी तरह विफल साबित हुई है। स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। शहरों को गंदगी का डिब्बा बनाकर छोड़ दिया गया है। सैलजा ने कहा कि धारूहेड़ा के लोग लंबे समय से परेशान और दुखी हैं। आखिर धारूहेड़ा ने ऐसा कौन-सा दोष किया है कि पड़ोसी क्षेत्रों की गंदगी यहां डाली जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, केंद्र और स्थानीय स्तर पर भाजपा की सरकार होने के बावजूद धारूहेड़ा की जनता के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। लोगों को हर स्तर पर ठगा गया है। सांसद ने विश्वास जताया कि निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष पद की उम्मीदवार को जनता प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएगी। भाजपा शासन में जो स्थानीय विकास कार्य पूरी तरह ठप हो गए हैं, उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में मिलकर तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार स्थानीय निकायों की समस्याओं के समाधान में पूरी तरह असफल रही है। शहरों में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है।

चुनाव प्रक्रिया को डिजिटली ऐसे मजबूत किया चुनाव आयोग ने, 'ईसीआइनेट' ऐप लॉन्च के बाद सुपरहिट हो रहा है साबित

हरिभूमि ब्यूरो ⏭ नई दिल्ली

चुनाव आयोग द्वारा विकसित अत्याधुनिक आईटी प्लेटफॉर्म ईसीआइनेट ने इस साल के विधानसभा चुनावों और उपचुनावों में पारदर्शिता, गति और सुरक्षा के नए मानक स्थापित किए हैं। आयोग के आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया गया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने चुनावी प्रक्रिया को अधिक सुगम, सुरक्षित और प्रभावी बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाई। जनवरी 2026 में आधिकारिक लॉन्च के बाद से ईसीआइनेट ऐप को जनता और प्रशासनिक तंत्र से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अब तक इस ऐप को 10 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। इससे पहले इसका बीटा संस्करण नवंबर 2025 में बिहार चुनावों में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। चुनाव के दौरान इस ईसीआइनेट की उपयोगिता स्पष्ट रूप से देखने को मिली। मतदान दिवस (9, 23 और 29 अप्रैल) पर

इस प्लेटफॉर्म पर कुल 98.3 करोड़ से अधिक हिट दर्ज किए गए। वहीं, 4 मई 2026 को मतगणना के दिन यह आंकड़ा औसतन 3 करोड़ हिट प्रति मिनट तक पहुंच गया, जो इसकी व्यापक उपयोगिता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी ईसीआइनेट ने मजबूत प्रदर्शन किया। मतगणना के दिन देश और विदेश से आए 68 लाख से अधिक साइबर हमलों को सफलतापूर्वक विफल किया गया। ये हमले चुनाव परिणाम पोर्टल सहित विभिन्न महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म्स को निशाना बना रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए इस बार पहली बार क्यूआर कोड आधारित फोटो पहचान पत्र प्रणाली लागू की गई।

इसके तहत देशभर के मतगणना केंद्रों पर 3.2 लाख से अधिक क्यूआर कोड जारी किए गए, जिससे केवल अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिल सका और किसी भी प्रकार की अनधिकृत गतिविधि पर प्रभावी रोक लगी। चुनाव आयोग के इस डिजिटल प्रयास ने न केवल चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और तेज बनाया, बल्कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में ईसीआइनेट जैसे प्लेटफॉर्म भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाएंगे।

आम जनता की दूर हुई आशंका

पेट्रोल-डीजल और घरेलू एलपीजी की कीमतों में नहीं होगी बढ़ोतरी

एजेंसी ⏭ नई दिल्ली

पेट्रोल-डीजल को लेकर राहत बड़ी खबर सामने आई है। घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया है और न ही पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी के संबंध में, घरेलू इस्तेमाल वाले कुकिंग एलपीजी सिलिंडरों री कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हालिया संशोधन केवल कमर्शियल एलपीजी सिलिंडरों पर लागू होता है। इसके अलावा फ्यूल स्टेशनों पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है।

100% एलपीजी आपूर्ति के प्रयास जारी: सुजाता शर्मा

सुजाता शर्मा ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण हमारे आयात पर असर पड़ा है, चाहे वह एलपीजी हो, कच्चा तेल हो या प्राकृतिक गैस। हालांकि, भारत सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को खाना पकाने के लिए एलपीजी की 100 प्रतिशत घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। साथ ही, कमर्शियल उपयोगकर्ताओं को भी 70 प्रतिशत तक आपूर्ति करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

विश्व में एलएनजी की कीमतें बढ़ी

आपूर्ति बाधाओं के कारण वैश्विक स्तर पर एलएनजी की कीमतें तीन साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। अप्रैल 2026 में स्पॉट एलएनजी की कीमतें 17 से 18 डॉलर प्रति एमएमबीटीयू तक बढ़ गई हैं, जो पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले 10 से 11 डॉलर के स्तर पर थीं। बीच में कीमतों ने 22 डॉलर का स्तर भी छुआ था। इस मूल्य वृद्धि और आपूर्ति में कमी का सीधा असर भारत की गैस खपत पर पड़ा है।

पीएम मोदी 'आर्ट ऑफ लिविंग' के 45वें स्थापना दिवस समारोह को करेंगे संबोधित

182 देशों के प्रतिभागी आध्यात्मिक आंदोलन के साक्षी बनेंगे

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

- कई गोलमेज चर्चा और शिखर सम्मलेन का आयोजन होगा
- 13 मई को गुरुदेव रविशंकर के उद्बोधन का सीधा प्रसारण भी

पीएम मोदी और गुरुदेव रविशंकर फाइल फोटो

पीएम नरेंद्र मोदी 'आर्ट ऑफ लिविंग' की स्थापना के 45 वर्ष पूर्ण होने और इसके संस्थापक, गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर 10 मई को 'आर्ट ऑफ लिविंग' के अंतरराष्ट्रीय केंद्र, बेंगलुरु में आयोजित समारोह को संबोधित करेंगे। मानवीय एवं आध्यात्मिक आंदोलन के साढ़े चार दशक पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस वैश्विक समागम में 182 से अधिक देशों के प्रतिभागी प्रत्यक्ष और ऑनलाइन माध्यम से सम्मिलित होंगे। यह आयोजन समाज के हर वर्ग राजनेताओं, सिविल सेवकों, किसानों, इंजीनियरों, गृहिणियों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को एक मंच पर लाएगा, जो गुरुदेव के दूरदर्शी नेतृत्व और संगठन के वैश्विक प्रभाव का एक अनूठा उत्सव होगा।

'ध्यान मंदिर' कक्ष का उद्घाटन करेंगे पीएम

पीएम नरेंद्र मोदी परिसर में नव-निर्मित 'ध्यान मंदिर' एक विशेष ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही, वे मानसिक स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, प्रकृति संरक्षण और सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित राष्ट्रव्यापी सेवा पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। बता दें, वर्ष 1981 में गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर द्वारा स्थापित 'आर्ट ऑफ लिविंग' आज एक वैश्विक, स्वयंसेवक-आधारित मानवीय और शैक्षिक संगठन बन चुका है। 182 देशों में सक्रिय यह संस्था 'सुदर्शन क्रिया' जैसी परिवर्तनकारी श्वास तकनीकों और सतत विकास के क्षेत्र में अपनी अग्रणी ठोस पहलों के माध्यम से अब तक 100 करोड़ से अधिक जीवन को स्पर्श कर चुकी है।

सांस्कृतिक महोत्सव का होगा आयोजन

इस अवसर पर 182 देशों की विविध संस्कृतियों को प्रस्तुत करते हुए संगीत, नृत्य और कलात्मक अभिव्यक्तियों से सुसज्जित सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। नागरिक समाज में नैतिकता पर केंद्रित वैश्विक नेतृत्व संवाद और शिखर सम्मेलन का भी आयोजन होगा। 13 मई को गुरुदेव श्री श्री रवि शंकर के मार्गदर्शन में 'विश्व शांति हेतु वैश्विक ध्यान' सभी के लिए निःशुल्क और विश्वभर में सीधा प्रसारित किया जाएगा। भारत के 450 से अधिक जिलों में कार्यरत अनसुने दैनिक नायकों को सम्मानित किया जाएगा। 25-26 मई को 'बंदी कल्याण और नीतिगत सुधार' पर विशेष गोलमेज चर्चा होगी

बिम्सटेक देशों के युवाओं का सम्मेलन

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित 'बिम्सटेक युवा नेतृत्व आदान-प्रदान', जिसमें सभी सात बिम्सटेक देशों के युवा नेता 'आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर' में केंद्रित नेतृत्व प्रशिक्षण (लीडरशिप इमर्शन) हेतु एकत्र होंगे।

संपादकीय जागरण

गुरुवार, 7 मई, 2026 : ज्येष्ठ कृष्ण - 5 वि. 2083

दृढ़ता ही विजय का आधार बनती है

राहत भरी खबर

यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए राहत की बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के आसार बढ़ गए हैं। इसका संकेत इससे मिलता है कि जहां दोनों देश एक 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आपरेशन एपिक फ्यूरी नामक अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने के साथ होर्मुज समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन फ्रीडम को भी रोकने की घोषणा की। आपरेशन फ्रीडम के बाद भी जहाजों का आवागमन सुगम तो नहीं हो पाया था, लेकिन शायद ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ने ईरान के नेतृत्व को अपना रवैया नरम करने को बाध्य किया। जो भी हो, जब तक दोनों पक्षों के बीच वास्तव में समझौता नहीं हो जाता, तब तक न तो पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की आशा की जा सकती है और न ही पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित कर रहे ऊर्जा संकट से मुक्ति की। ध्यान रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता नाकाम हो गई थी और दूसरे दौर की वार्ता हो ही नहीं पाई थी। इसके बाद दोनों देश एक-दूसरे को धमकाने में जुट गए थे।

विश्व अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति को कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि दोनों के बीच समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की खबर आते ही तेल के दाम गिर गए और शेयर बाजारों में भी सकारात्मक असर दिखा। यदि किसी कारण दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होती तो टकराव की आशंकाएं उभरने में देर नहीं लगेगी। ऐसा न हो, इसके लिए जहां अमेरिका को सब कुछ अपने मन मुताबिक होने की अपेक्षा का परित्याग करना होगा, वहीं ईरान को भी अपना यह हठ छोड़ना होगा कि परमाणु मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता और होर्मुज पर उसका अधिकार होना चाहिए। ईरान कुछ भी कहे, उसे न तो परमाणु हथियार बनाने की अनुमति दी जा सकती है और न ही इसकी कि वह होर्मुज को अपनी निजी जागीर माने। यदि ईरान चैन से रहने के साथ औरों को भी चैन से रहने देना चाहता है तो उसे इजरायल के लिए खतरा बने हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी गुटों को सहयोग-समर्थन देने से पीछे हटना होगा। उसे इस्लामी जगत का अगुआ बनने की मानसिकता भी छोड़नी होगी, क्योंकि खाड़ी देश पश्चिम एशिया में उसके दबदबे को कभी स्वीकार नहीं करने वाले। ईरान आज जिस स्थिति में है और विशेष रूप से जिस प्रकार यह जानना कठिन है कि वहां वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में है, तब तक न तो अमेरिका उससे समझौते के लिए बहुत आशान्वित हो सकता है और न ही विश्व। वैसे अंततः किसी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। अच्छा होता कि अमेरिका इसे समय रहते समझता और ईरान से वार्ता का क्रम तोड़कर उस पर हमला करने से बचता।

चिंता की बात

दिल्ली में किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराधों की संख्या देश के अन्य बड़े शहरों की तुलना में काफी अधिक है, जो गंभीर चिंता का विषय है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में दिल्ली में नाबालिगों द्वारा अपराध के 23 सौ से अधिक मामले सामने आए हैं, जबकि चेन्नई और बेंगलुरु जैसे महानगरों में ये मामले पांच सौ से भी कम हैं। यही नहीं, दिल्ली में विगत तीन वर्षों में भी ये संख्या 22 सौ से अधिक बनी हुई है, जो दर्शाता है कि स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। इसमें दो राय नहीं कि अपराध को रोकने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन अभिभावक, समाज और सरकार भी अपने दायित्व से पीछे नहीं हट सकती। अपराध में लिप्त 2700 किशोर ऐसे पाए गए जो अभिभावकों के साथ रहते थे।

किशोरों को शिक्षा और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके

स्पष्ट है कि अभिभावकों ने यदि अपने बच्चों पर ध्यान दिया होता तो इन किशोरों को अपराध की गर्त में जाने से रोका जा सकता था। दिल्ली सरकार को ऐसे क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए, जहां अपराध में लिप्त किशोर सबसे ज्यादा हैं। इन क्षेत्रों में किशोरों को शिक्षा और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि उनका ध्यान अपराध से हटाया जा सके और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाया जा सके।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या क्षेत्रीय दलों की राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है?

आज का सवाल

क्या कांग्रेस का द्रमुक से किनारा करना राजनीतिक अवसरवाद है?

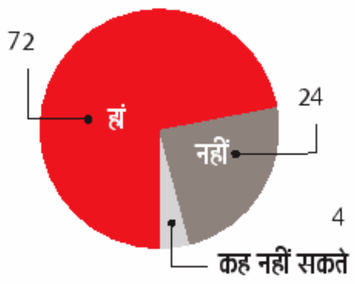

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

सामरिक तैयारी को देनी होगी और धार

हर्ष वी. पंत

आपरेशन सिंदूर ऐसा पड़ाव बनकर उभरा था, जहां मंशा, क्षमता और रणनीतिक पहलू स्पष्टता के साथ एक दूसरे के साथ ताल मिलाते दिखे थे

अवधेश राजपूत

भारत की पाकिस्तान नीति में आपरेशन सिंदूर एक निर्णायक पड़ाव के रूप में सामने आया था। एक सीमित अवधि में चले इस सैन्य अभियान के परिणाम बहुत व्यापक निहितार्थों वाले रहे। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के जवाब में इस अभियान के दौरान पाकिस्तान के सुदूरवर्ती स्थलों पर संचालित आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त करने का काम किया गया। आतंकी ढांचे पर नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया न तो नितांत भावनात्मक रही और न ही विशुद्ध प्रतीकात्मक। यह एक नपी-तुली सुनियोजित सामरिक कार्रवाई थी, जिसने प्रतिरोध के नए पैमाने को परिभाषित करने का काम किया। भारत की ओर से ऐसा करारा जवाब दिया गया और ऐसे-ऐसे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिनके बारे में पाकिस्तान ने शायद सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान की मनुहार के बाद भारत ने चार दिन बाद भले ही संघर्ष विराम पर सहमति जताई हो, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि अभियान केवल थमा है, समाप्त नहीं हुआ। आपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न केवल अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बल्कि वह दृढ़ता भी दिखाई कि उस पर हुए हमलों का किसी भी कीमत पर ऐसा जवाब दिया जाएगा, जिसे दुश्मन लंबे अर्से तक याद रखे। राजनीतिक नेतृत्व की स्पष्टता के साथ सैन्य बलों ने अपने शौर्य का अप्रतिम परिचय दिया।

हर सफलता अपने साथ कुछ सबक लेकर आती है और इस पैमाने पर आपरेशन सिंदूर भी अपवाद नहीं रहा। इसमें पाकिस्तान की परमाणु हेकड़ी की हवा पूरी तरह निकल गई। हालांकि तनाव भड़कने से जुड़े पहलू अभी भी कायम हैं, लेकिन भारत के स्पष्टता भरे रुख ने एक रेखा अवश्य खींच दी है। आपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच अद्भुत समन्वय का साक्षी भी बना। विशेष रूप से अरब सागर में नौसेना की तत्परता से तैनाती से जुड़ा पहलू बहुत सराहनीय रहा। इसके बावजूद यह भी स्वीकार करना होगा कि तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य को बेहतर बनाने की दिशा में अभी और प्रयास करने होंगे। खासतौर से रीयल टाइम में एकीकृत परिचालन को लेकर।

आपरेशन सिंदूर ने लक्ष्य को चिह्नित कर सटीक प्रहार की क्षमताओं के साथ दूर से ही दुश्मन को सबक सिखाने में सुरक्षा बलों की भूमिका को और पुख्ता किया। मिसाइल, ड्रोन और बियोंड-विजुअल रेंज वाले संघर्ष ने भारत के जोखिम घटाते हुए हमलों के अधिकतम प्रभाव को सुनिश्चित किया। हालांकि इस दौरान हवाई रक्षा प्रतिरोध, ड्रोन रोधी क्षमताओं, खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं के अलावा संचार संबंधी लचीलेपन के स्तर पर मौजूद कुछ कमजोरियां भी उजागर हुईं। नीति-नियंताओं के लिए इसका स्पष्ट संदेश है कि प्रणालीगत पूर्ण एकीकरण के अभाव में केवल अपनी सुविधा के साथ विशिष्ट तकनीकों को अपनाने की अपनी सीमाएं भी होती हैं। वैसे तो इस सैन्य संघर्ष में भारत ने निर्णायक प्रभुत्व के साथ सफलता हासिल की, लेकिन शुरुआती स्तर पर लगे कुछ झटकों ने सैन्य क्षमताओं में विद्यमान कुछ असंतुलन की ओर भी संकेत किया। आवश्यक स्वदेशी क्षमताओं का अभाव, लंबी दूरी तक प्रहार करने वाली प्रणालियों की सीमाएं और इलेक्ट्रानिक युद्ध के मोर्चे पर जो कमजोरियां दिखीं, उन्हें तत्काल प्रभाव से दूर कर स्वयं को सशक्त करना होगा।

आपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत ने आतंकवाद से निपटने को लेकर अपना दृष्टिकोण और स्पष्ट किया। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवादी तत्वों और उन्हें संरक्षण देने वाले देशों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा और उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। इस अभियान से संबंधित तकनीकी आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस क्रम में ड्रोन, लायटरिंग म्यूनिशंस यानी घातक ड्रोन और अत्याधुनिक हवाई रक्षा कवच का व्यापक उपयोग न केवल भारत के अपने अनुभवों पर आधारित रहा, बल्कि उसने समकालीन वैश्विक संघर्षों के रुझानों से लिए गए सबक का लाभ भी उठाया। इसका ही परिणाम है कि भारत ने रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता के प्रयासों को तेज कर दिया है। आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिले चीनी खुफिया एवं सैन्य सामग्री सहयोग-समर्थन को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस जटिलता ने दो मोर्चों पर संभावित संघर्ष को लेकर भारत की तैयारी को और पुख्ता बनाने की आवश्यकता को कहीं अधिक गहराई से रेखांकित किया है।

हमें अपनी मंशा और क्षमताओं दोनों को और धार देनी होगी और यह बात केवल घोषणाओं तक सिमटकर न रह जाए, बल्कि आवश्यकता पर तत्परता से उपयोग योग्य भी बने। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जैसी पहल बहुत अच्छी रही है, लेकिन इस ढांचे के अंतर्गत सशस्त्र बलों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाना होगा। यह सही है कि समन्वय में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन नियोजन, कमान ढांचे और संसाधनों के आवंटन में एकीकरण के अभाव और असंतुलन की कुछ स्थिति बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती मंशा को मूर्त रूप देने की होगी। जैसे सैन्य बलों की संस्थागत संस्कृतियों में सामंजस्य बैठाना, सेना के विभिन्न अंगों में लचीलापन बढ़ाना और सामरिक तैयारियों की दिशा में एकीकृत ढांचा तैयार करना। यदि रणनीतिक बदलाव को स्थायी बनाना है, तो इस क्रम में तकनीक के आधुनिकीकरण के साथ-साथ इन संगठनात्मक सुधारों पर भी ध्यान देना ही होगा।

भारत के सामरिक परिदृश्य में आपरेशन सिंदूर एक ऐसा पड़ाव बनकर उभरा, जहां मंशा, क्षमता और रणनीतिक पहलू पूरी स्पष्टता के साथ एक दूसरे के साथ ताल मिलाते दिखे। इसने दर्शाया कि यह दबाव में आने वाला पुराना भारत नहीं, बल्कि दुश्मन पर दबाव बनाने वाला भारत है, जहां तकनीकी श्रेष्ठता का लाभ उठाकर संघर्ष का दायरा बढ़ाए बिना ही अपने विकल्पों में वृद्धि करने में बड़ी सफलता मिली। उस संघर्ष में मिली सफलता को कायम रखने के लिए आवश्यक होगा कि ऐसा राजनीतिक संकल्प लिया जाए जो दिखावटी सुधारों के बजाय संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दे। यदि ऐसा न हुआ तो आपरेशन सिंदूर से उपजी संभावनाएं एक गंवाए हुए अवसर का प्रतीक बनकर ही रह जाएंगी।

(लेखक सामरिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

आत्ममंथन के बजाय आरोपों का सहारा

पीयूष पांडे

लोकतंत्र में सवाल उठाना आवश्यक है, लेकिन हर चुनावी हार को साजिश बताना एक खतरनाक प्रवृत्ति है

वास्तविकता से मुंह मोड़ने की नाकाम कोशिश ● प्रेट्र

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए का पूरा विमर्श पश्चिम बंगाल के इर्द-गिर्द सिमटता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित किया। ममता ने यहां तक कहा कि वे हार को 'साजिश' का परिणाम मानती हैं। उल्लेखनीय है कि 2014 के बाद से हुए कई चुनावों में विपक्षी दलों ने अपनी हार के कारणों का ठोस आत्ममंथन करने के बजाय आरोपों की राह अधिक चुनी है। 2014 में भाजपा की बड़ी जीत के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा जोर-शोर से उठा, जो हर चुनावी हार के बाद समय-समय पर सामने आता रहा है। हालांकि 2017 में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 'ईवीएम चैलेंज' में कोई भी दल मशीनों में छेड़छाड़ का दावा साबित नहीं कर पाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वीवीपैट प्रणाली को और व्यापक रूप से लागू किया गया, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते ही रहते हैं।

बंगाल में बात ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों से भी आगे निकल गई है। अब विपक्षी दलों का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने पहले गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआइआर के तहत लाखों मतदाताओं के वोट काटे और फिर चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों ने भाजपा के इशारे पर काम करते हुए चुनावी गड़बड़ी की। यदि चुनाव प्रक्रिया इतनी व्यापक रूप से प्रभावित की जा सकती थी, तो अन्य राज्यों तमिलनाडु या केरलम में अलग-अलग नतीजे कैसे आए? केरलम में तो कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है।

विपक्ष इस तथ्य को नकार देता है कि बंगाल में भाजपा की उपस्थिति कोई नई नहीं है। पहले जनसंघ और बाद में भाजपा वहां पैर जमाने की कोशिश सदैव करती रही। 2016 के विधानसभा चुनाव में उसे 10 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे, जो 2021 में बढ़कर 37.97 प्रतिशत हुए और अब 45.85 प्रतिशत। तृणमूल कांग्रेस के वोट 2021 के 48.02 प्रतिशत से घटकर 2024 में 40.80 प्रतिशत पर आ गए। 15 साल की एंटी इनकंबेंसी, भ्रष्टाचार के आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध हिंदू ध्रुवीकरण, महिलाओं की सुरक्षा और कांग्रेस, वाम दलों का तृणमूल के खिलाफ होना ममता की हार की वजहों में रहे।

चुनावी धांधली का आरोप नया नहीं है। तमाम प्रयासों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह दोषमुक्त कभी नहीं रही। दिलचस्प है कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को 9 फरवरी 1952 को एक पत्र लिखा था, 'मुझे समय-समय पर चुनावों के संचालन के तरीके के बारे में विभिन्न शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।...आज सुबह मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में शिकायत मिली कि कई स्थानों पर मतदान पेटियों को बदल दिया गया या उनके साथ छेड़छाड़ की गई।' बाद के वर्षों में बिहार, तमिलनाडु, जैसे कई राज्यों में भी चुनावी गड़बड़ियां होती रहीं। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त बूथ लूट और हिंसा रोकने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहली बार कई चरणों में चुनाव कराए। राज्य में बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई। उस वक्त लालू यादव खुलकर टीएन शेषन के खिलाफ बोलते थे। बंगाल में चुनावी हिंसा की अति हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त बंगाल में चुनावी हिंसा में सात मौतें और करीब 2,652 लोग घायल हुए। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान तो 300 से ज्यादा हिंसक घटनाओं में 58 मौतें हुईं। इन हालात में केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने अगर मतदाताओं को भयमुक्त होकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया तो इसे गलत कैसे कहा जा सकता है? क्या ये भी एक वजह नहीं है कि बंगाल में मतदान के पहले चरण में 93.19 और दूसरे चरण में 91.66 प्रतिशत वोट पड़े? इसमें कोई शक नहीं कि एसआइआर का क्रियान्यवन और बेहतर होना चाहिए था, पर विपक्षी दलों की एसआइआर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश सिर्फ एक नैरेटिव बनाने का ही दांव है, जिसका उन्हें लाभ कम और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान अधिक है। बिहार में भी यही कोशिश हुई थी, जहां एसआइआर के बाद 65 लाख लोगों के नाम कटे थे, पर नाम जोड़ने के लिए औपचारिक आवेदन सैकड़ों में भी नहीं हुए।

संभव है कि बंगाल में एसआइआर के चलते कुछ लोग मतदान से वंचित हुए होंगे, पर विपक्ष वास्तव में एसआइआर के मुद्दे पर चिंतित था, तो उसे बयानबाजी से आगे बढ़ना चाहिए था। यदि वह पांच-सात हजार प्रभावित लोगों को ही आगे कर देता, तो मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ जाता, पर केवल बयानबाजी होती रही। तथ्य यह भी है कि एसआइआर के तहत जहां अधिक नाम कटे, वहां भाजपा के साथ टीएमसी ने भी जीत हासिल की है। लोकतंत्र में सवाल उठाना आवश्यक है, किंतु हर चुनावी हार को साजिश बताना खतरनाक प्रवृत्ति है। इससे न केवल संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ता है, बल्कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भी भटकता है। विपक्षी दलों के लिए जरूरी है कि वे जमीनी मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती और वैकल्पिक नीति का एजेंडा बनाएं। ईवीएम में गड़बड़ी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत जैसे आरोप जनता के गले नहीं उतरते।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मन की दिशा बदलेगी दशा

मन यदि नियंत्रण में हो तो वह मनुष्य को नर से नारायण और भटक जाए तो नर से नराधम बना देता है। गुरु नानक देव जी ने कष्टों से मुक्ति का एक ही उपाय बताया 'मन जीते, जग जीत।' कबीरदास जी ने 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत' का संदेश दिया। वस्तुतः, हमारा मन उस जलाशय की भांति है, जिसका स्थिर जल हवा के प्रभाव से लहरों में परिवर्तित होकर शीघ्र गतिमान हो जाता है। मन क्षण-क्षण कहीं न कहीं दौड़ता रहता है। मन यदि बुरे विचारों में निमग्न है तो स्वभावतः उस बुराई की अगणित प्रेरणा, योजना मस्तिष्क के सामने आती चली जाएंगी और मन क्रमशः उनके लिए प्रशिक्षित होता चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने यथार्थ ही कहा है कि एक प्रखर नियंत्रित और शांत मन संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक है।

सांसारिक विषय-भोग मन को और चंचल बनाते हैं। इसलिए मन को आत्मा के स्वाभाविक गुण शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता आदि गुणों का रसास्वादन कराना होगा। हृदय में प्रेम भावना का विकास कर दोषों का शमन करना होगा। दोषों का शमन होते ही अवरोधों के टूट जाने से हृदय में ईश्वर का वास होगा। आज हम तन से नहीं मन से बीमार हैं। मन में संकल्प-विकल्प आते, मन की बीमारी तन में चली जाती है। इसलिए जरूरी है मन का संशोधन करें। जब मन निर्मल होता है तो हमारा तन भी निर्मल हो जाता है और जीवन भी निर्मल हो जाता है। कोई प्यादा मर्यादा में ही रहेगा, बशर्ते शासक अनुशासन में हो। शासक हमारा मन और प्यादा हमारी इंद्रियां। जब मन कमजोर होता है तो स्थिति समस्या होती है, जब मन संतुलित होता है तो स्थिति चुनौती होती है। वहीं, जब मन मजबूत होता है तो वही स्थिति अवसर बन जाती है। अगर हमारे भीतर की आत्म-शक्ति, इच्छा-शक्ति बहुत मजबूत है तो बाहर का बुरे से बुरा प्रभाव भी हमें विचलित नहीं कर सकेगा। मन की दिशा ही हमारी दशा बदलने में सक्षम है।

डा. निर्मल जैन

पाठकनामा

pathaknama@nda.jagran.com

बेनकाब हुआ फर्जी सेक्युलरिज्म

'फिर खुली फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ स्वयं ममता बनर्जी की हताशा भरी पराजय के कारणों की पड़ताल करते हुए ठीक ही कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिमपरस्ती की कीमत चुकानी पड़ी। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हिंदू समुदाय को जातियों के खेमे में बंटा मानकर मुसलमानों को एकमुश्त वोटबैंक के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। भाजपा की रीति-नीति से इतर स्वयं को सेक्युलर साबित करने के लिए ये मुस्लिम वोटबैंक को आकर्षित करने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते। बंगाल की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहने के लिए ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय देकर मुस्लिमपरस्ती का सुविधाजनक कार्ड खेला, जो कालांतर में भाजपा की सधी चुनावी रणनीति के आगे फुस्स साबित हुआ। भाजपा ने ममता शासन की अराजकता और मुस्लिम तुष्टीकरण से आजिज आ चुके हिंदुओं में टीएमसी की सत्ता उखाड़ फेंकने का जो विश्वास भरा मंत्र फूंका, वह उनके मन में गहराई तक उतर गया। अबकी बार भाजपा की चाकचौबंद चुनावी रणनीति, चुनाव आयोग के सख्त रवैये और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने बंगाल की डरी-सहमी आम जनता को निर्भीकता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए न केवल प्रोत्साहित किया, अपितु मतदान के बाद भी उनमें सुरक्षा का भरोसा पैदा किया। बंगाल के एकजुट हिंदुओं ने राजनीति की उस अवधारणा को ध्वस्त कर दिया कि हिंदू वोट कभी एकजुट नहीं हो सकता। हिंदुओं के ध्रुवीकरण से बंगाल का मजबूत किला ढह जाने से मुस्लिम तुष्टीकरण की विकृत राजनीति करने वाले दल सकते में हैं। उनका फर्जी सेक्युलरिज्म बेनकाब हो गया। अब हिंदू जनभावना की उपेक्षा करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना घाटे का सौदा होगा।

pandeyvp1960@gmail.com

बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा

बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद व्यापक तौर पर हिंसा देखने को मिली थी। इस वर्ष के चुनाव में भी हिंसा देखने को मिल रही है। ऐसे में कानून व्यवस्था स्थापित करना बंगाल में एक बहुत बड़ी चुनौती है, बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है। ऐसे में पक्ष और विपक्ष में हिंसा देखने को मिल सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार को इस मामले में नजर रखना चाहिए कि बंगाल की जनता और संपत्ति का किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचे। शांति और व्यवस्था बनाए बनी रहे इसके लिए यह भी जरूरी है नई सरकार बनने तक अर्धसैनिक बलों की तैनाती बनी रहे। बंगाल में चुनाव के बाद होने वाले हिंसा को रोकना हमेशा से चुनौती रही है। बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद हिंसा होना साफ बताता है कि कुछ असामाजिक तत्व पूरी शांति व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।

विजय किशोर तिवारी, नई दिल्ली

नए भारत का स्वर्णिम अध्याय

वर्ष 2014 भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है, जब नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री की कमान संभाली। उस समय भारत दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और जीडीपी लगभग 1.86 ट्रिलियन डालर थी। एक दशक के भीतर भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है, बल्कि वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। प्रति व्यक्ति आय का लगभग दोगुना हो जाना इस बात का प्रमाण है कि विकास का लाभ समाज के व्यापक वर्ग तक पहुंचा है। अर्थव्यवस्था में आई यह तेजी एक व्यापक परिवर्तन का संकेत है। 2026 तक भारत की जीडीपी चार ट्रिलियन डालर के पार पहुंचने का अनुमान है और 7.4 से 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर इसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बनाए हुए है। यह उपलब्धि सरकार की नीतियों, आर्थिक सुधारों और मजबूत नेतृत्व का परिणाम है। इस परिवर्तन में अमित शाह की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने संगठन को मजबूत करते हुए भाजपा को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। मोदी और शाह की जोड़ी ने राजनीति को केवल सत्ता तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया। बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में जो बदलाव आया है, वह अभूतपूर्व है। सड़कों का विस्तार, हाईवे का निर्माण, रेलवे का आधुनिकीकरण और हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि ने देश को एक नए युग में प्रवेश कराया है।

कांतिलाल मांडोत नई दिल्ली

पोस्ट

विधानसभा चुनावों का सार यह भी रहा कि असम से लेकर बंगाल और तमिलनाडु तक वंशवादी राजनीति के विरुद्ध भारी मतदान हुआ है। तहसीन पूनावाला@tehseenp

कांग्रेस नेता तमिलनाडु में हार का ठीकरा द्रमुक पर फोड़ रहे हैं। जब दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था तो हार अकेले द्रमुक की कैसे हुई? द्रमुक ने कांग्रेस के सबसे बुरे वक्त में उसका साथ दिया और अब कांग्रेस ही द्रमुक से किनारा कर रही है

मालिनी पार्थसारथी@MaliniP

सुबह राहुल गांधी ने आह्वान किया कि विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एकजुटता दिखाएं। शाम होते-होते उनकी पार्टी ने तमिलनाडु में अपने पुराने सहयोगी दल को छोड़कर नई पार्टी का दामन थाम लिया। संकेत उपाध्याय@sanket

अमेरिका ने आपरेशन एपिक फ्यूरी के समापन की घोषणा की है। स्पष्ट राजनीतिक एवं सामरिक लक्ष्य के बिना छेड़ी गई जंग की परिणति ऐसी ही होती है। दुनिया भारत से सीखे कि किसी युद्ध में उतरकर (1971, कारगिल और आपरेशन सिंदूर), अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर उसे अपनी शर्तों पर कैसे समाप्त करते हैं। केजेएस ढिल्लों@TinyDhillon

जनपथ

इस्तीफा देंगी नहीं करें साफ इंकार,
अपने हाथों स्वयं की इज्जत रहीं उतार।
इज्जत रहीं उतार गई हाथों से सत्ता,
नहीं रहा है छूट किंतु कुर्सी का हत्था।
दीदी होकर फेल चाहतीं मिले वजीफा,
बच्चों सी जिद ठान न देतीं वे इस्तीफा!

-ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120- 4615800, E- mail:delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 292

कागजी मास्टर प्लान यानी अव्यवस्थित एनसीआर

किसी भी महानगर के लिए 'मास्टर प्लान' वह नींव है, जिसपर बेहतर जन-जीवन का भविष्य टिका होता है। यह संसाधनों के समान वितरण, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन स्तर का वादा होता है. लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बीते पांच साल से बगैर मास्टर प्लान के है। इतना ही नहीं, यहां पर क्रियान्वयन की बिगड़ी व्यवस्था के कारण पूर्व के मास्टर प्लान पर भी ठीक से काम नहीं हो पाया है। दिल्ली का मौजूदा मास्टर प्लान वर्ष 2041 तक की स्थितियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, लेकिन यह अभी केंद्र सरकार के पास लंबित है। सवाल यह उठता है कि जब पूर्व में भी मास्टर प्लान बनाए गए और उनके अनुरूप काम किया जाना था तो दिल्ली आज भी प्रदूषण, जलभराव और अनियोजित विकास के जाल में क्यों फंसी है। उचित क्रियान्वयन का अभाव ही है कि दिल्ली का लगभग 65% हिस्सा अनियोजित तरीके से बसा है। मास्टर प्लान की सबसे बड़ी जरूरत जनसंख्या के बोझ को सहने की क्षमता विकसित करना है। यहां का 100 वर्ष पुराना ड्रेनेज सिस्टम हर साल सिर्फ खबरों तक सीमित रह जाता है, उसके सुधार के प्रयासों को कोई गति मिलती नहीं दिखती। बहुत हद तक एनसीआर के शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के बीच भी समन्वय की भारी कमी हमेशा उभरकर सामने आती है। आखिर सरकार, प्रशासन के स्तर पर देश की राजधानी समेत पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को इस दृष्टि से क्यों नहीं देखा जा रहा। दिल्ली समेत एनसीआर में मास्टर प्लान के अनुरूप नियोजित विकास न हो पाने के पीछे कहां है लापरवाही और कौन है जिम्मेदार? साथ ही दिल्ली समेत एनसीआर में मास्टर प्लान के अनुरूप उचित ढंग से काम कर योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए क्या करने होंगे ठोस उपाय। इसी की पड़ताल हमारा आज का मुद्दा है:

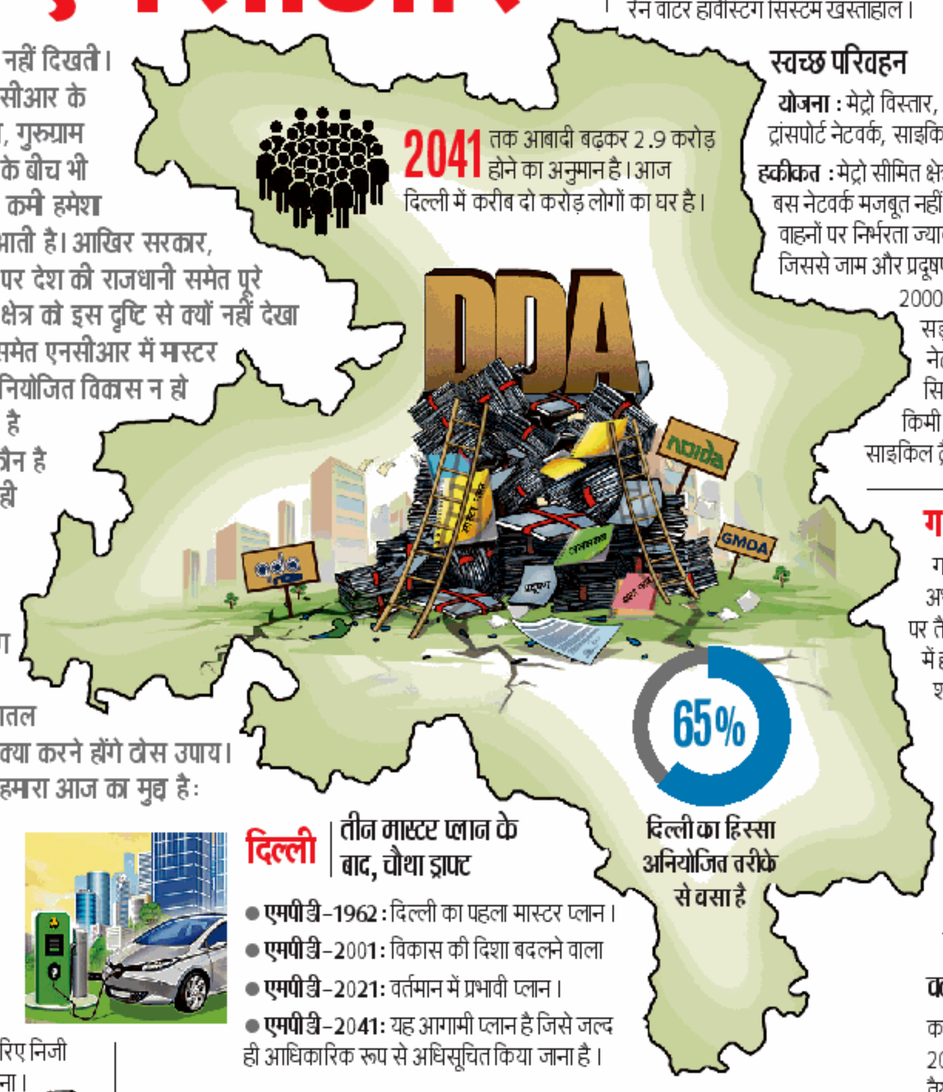

पिछला मास्टर प्लान (एमपीडी-2021)

7 फरवरी 2007 को अधिसूचित किया गया था और 20 साल (वर्ष 2021 तक) की जरूरतों और अनुमानित आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हालांकि नए प्लान (2041) के आने तक इसी के प्रविधानों के तहत काम हो रहा।

वर्तमान मास्टर प्लान (एमपीडी-2021): तय मानक बनाम वास्तविकता :

मास्टर प्लान में जो लक्ष्य रखे गए और जो धरातल पर उतरे, उनमें एक बड़ा अंतर साफ देखा जा सकता है:-

हरित और जल संरक्षण-एकीकरण

क्या तय है : दिल्ली के कुल क्षेत्रफल का लगभग 15-20 प्रतिशत हिस्सा 'ग्रीन कवर' और 'रीजनल रिज' के रूप में संरक्षित रखना। यमुना के किनारे को 'रिवरफ्रंट' के रूप में विकसित करना और जल निकायों का पुनरुद्धार।

वास्तविकता : सकारात्मक पक्ष यह है कि दिल्ली का ग्रीन कवर बढ़ा। लेकिन नकारात्मक पहलू यह है कि यमुना रिवरफ्रंट आज भी अतिक्रमण और गंदगी की मार झेल रहा। जल निकायों में से कई केवल कागजों पर जीवित हैं, असलियत में वहां कंक्रीट का कब्जा।

प्रदूषण नियंत्रण: स्वच्छ परिवहन

क्या तय है : 'पब्लिक ट्रांसपोर्ट' को प्राथमिकता देना, साइकिल ट्रैक बनाना और 'ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (टीओडी) के जरिए निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना।

वास्तविकता : दिल्ली मेट्रो का तो विस्तार हुआ। पर, अब तक 'लास्ट माइल कनेक्टिविटी' और साइकिल ट्रैक की योजना बुरी तरह विफल रही। परिवहन के साधन बढ़ने के बावजूद दिल्ली आज भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है क्योंकि सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम नहीं हुआ।

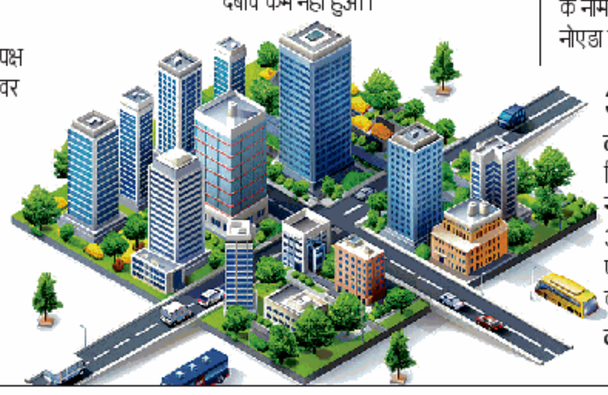

आधारभूत ढांचा

क्या तय है : बढ़ती आबादी के लिए नए 'अर्बन एक्सटेंशन' (जैसे नरेला, द्वारका, रोहिणी) बनाना और वहां बुनियादी सुविधाएं जैसे पानी, सीवर और बिजली उपलब्ध कराना।

वास्तविकता : रोहिणी और द्वारका जैसे उप-शहर बसे तो सही। पर, नरेला जैसे इलाके आज भी कनेक्टिविटी और बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण पिछड़े हैं। मास्टर प्लान ने आबादी का जो अनुमान लगाया था, असल आबादी उससे कहीं ज्यादा बढ़ गई, जिससे मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी दबाव।

विरासत और संस्कृति

क्या तय है : 'हेरिटेज जोन' और 'हेरिटेज बिल्डिंग्स' की पहचान कर उन्हें संरक्षित करना। पुरानी दिल्ली (शाहजहांनाबाद) का पुनरुद्धार और वहां के व्यापारिक चरित्र को बनाए रखते हुए आधुनिकीकरण करना।

वास्तविकता : चांदनी चौक के सुंदरीकरण की कोशिशें हुईं, बाकी पुरानी दिल्ली और महरौली जैसे ऐतिहासिक क्षेत्रों में संरक्षण केवल प्रतीकात्मक बनकर रह गया। ऐतिहासिक धरोहरों के आसपास अवैध निर्माण और जनसंख्या का घनत्व मास्टर प्लान के संरक्षण के नियमों का खुला उल्लंघन करता है।

दिल्ली | तीन मास्टर प्लान के बाद, चौथा ड्राफ्ट

- **एमपीडी-1962:** दिल्ली का पहला मास्टर प्लान।
- **एमपीडी-2001:** विकास की दिशा बदलने वाला
- **एमपीडी-2021:** वर्तमान में प्रभावी प्लान।
- **एमपीडी-2041:** यह आगामी प्लान है जिसे जल्द ही आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाना है।

आर्थिक विकास : स्वच्छ अर्थव्यवस्था

क्या तय है : दिल्ली को 'सर्विस हब' के रूप में विकसित करना। गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को शहर से बाहर शिफ्ट करना और हाई-टेक उद्योग (आइटी, जैव प्रौद्योगिकी) को बढ़ावा देना।

वास्तविकता : औद्योगिक क्षेत्रों की शिफ्टिंग होने तक सीमित रह गया। रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे छोटे उद्योगों पर नहीं हो पा रहा नियंत्रण। 'स्वच्छ अर्थव्यवस्था' के नाम पर आइटी हब बनाने का सपना गुरुग्राम और नोएडा की तुलना में दिल्ली में धीमा रहा।

जिले की वर्तमान व मास्टर प्लान की अनुमानित आबादी

जिला	वर्तमान में	2031 तक
गुरुग्राम	27 लाख	42.5 लाख
फरीदाबाद	30 लाख	38 लाख
गाजियाबाद	24 लाख	55 लाख
नोएडा	15 लाख	25 लाख
ग्रेटर नोएडा	22 लाख	35 लाख (2041 लाख)

गुरुग्राम | वर्तमान विकास मास्टर प्लान 2031 के आधार पर

हरित और जल संरक्षण

योजना : हरित पट्टियां, अरावली संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल निकायों का पुनर्जीवन।

जमीनी स्थिति : तेजी से कंक्रीट विस्तार के कारण हरित क्षेत्र घटे। सौ से ज्यादा तालाब खत्म। रेन वाटर हार्वेस्टिंग नियम मौजूद, पर अनुपालन सीमित। 450 रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम खस्ताहाल।

स्वच्छ परिवहन

योजना : मेट्रो विस्तार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, साइकिल ट्रैक।

हकीकत : मेट्रो सीमित क्षेत्रों तक। बस नेटवर्क मजबूत नहीं। निजी वाहनों पर निर्भरता ज्यादा, जिससे जाम और प्रदूषण बढ़ा। 2000 किमी सड़क नेटवर्क में सिर्फ 100 किमी का साइकिल ट्रैक।

प्रदूषण नियंत्रण

योजना : औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

स्थिति: वायु गुणवत्ता लगातार खराब श्रेणी में। निर्माण गतिविधियों और वाहनों का बड़ा योगदान। कचरा प्रबंधन में सुधार के हुए मामूली प्रयास, पर पूर्ण नियंत्रण नहीं।

आर्थिक विकास (स्वच्छ अर्थव्यवस्था)

योजना: आइटी, कारपोरेट व सेवा क्षेत्र को बढ़ावा, प्रदूषण मुक्त उद्योग।

हकीकत: गुरुग्राम देश का प्रमुख कारपोरेट हब बना, लेकिन स्वच्छ अर्थव्यवस्था का लक्ष्य आंशिक। छोटे उद्योगों और निर्माण गतिविधियों से पर्यावरण दबाव बना।

आधारभूत ढांचा

योजना: सड़क, सीवर, ड्रेनेज, जल आपूर्ति का मजबूत नेटवर्क।

जमीनी स्थिति: कई क्षेत्रों में आधुनिक आधारभूत ढांचा लेकिन वर्षा में जलभराव, सीवर ओवरफ्लो और ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या। मास्टर प्लान और वास्तविक विकास में अंतर साफ।

विरासत और संस्कृति

योजना: ऐतिहासिक स्थलों और स्थानीय संस्कृति का संरक्षण।

हकीकत: तेजी से शहरीकरण के चलते पारंपरिक पहचान कमजोर। विरासत संरक्षण पर सीमित ध्यान। एक भी सांस्कृतिक केंद्र की सुविधा नहीं।

फरीदाबाद

वर्तमान में मास्टर प्लान 2031 लागू है, यह आगामी 10 साल को ध्यान में रखकर बनाया गया है :

वर्तमान मास्टर प्लान में क्या तय है और उसकी वास्तविकता क्या है :

- **हरित और जल संरक्षण-एकीकरण :** 5314 जमीन आरक्षित की गई, फिलहाल जमीन अधिग्रहण करने की कागजी प्रक्रिया चल रही है।
- **प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ परिवहन :** इसी साल 200 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। 50 सीएनजी बस चल रही हैं। बड़े पार्क व 20 मीटर चौड़ी ग्रीनबेल्ट विकसित की जाएंगी।
- **आर्थिक विकास, स्वच्छ अर्थव्यवस्था :** इसके लिए 448 एकड़ में स्पेशल जोन होंगे।
- **आधारभूत ढांचा :** 26 हजार 328 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है, जहां सेक्टर काटे जाने हैं।
- **विरासत और संस्कृति :** मास्टर प्लान 2031 में ऐतिहासिक खजानों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्मारकों और विरासत स्थलों को संरक्षित करना प्राथमिकता।

गाजियाबाद

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से अभी तक तीन मास्टर प्लान आधिकारिक तौर पर तैयार या लागू किए जा चुके हैं, जिसमें से हाल में ही काफी प्रयासों के बाद मास्टर प्लान 2031 शासन से स्वीकृत हुआ।

पिछले मास्टर प्लान

- **मास्टर प्लान 2001 (पुराना) :** यह शहर के शुरुआती सुनियोजित विकास के लिए बना था।
- **मास्टर प्लान 2021 (पूर्व) :** इसमें शहर की आबादी के अनुसार विकास का खाका तैयार किया गया।

वर्तमान मास्टर प्लान की स्थिति :

करीब सात साल के इंतजार के बाद अगस्त 2025 में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार मास्टर प्लान 2031 को यूपी सरकार ने मंजूरी दी। यह मास्टर प्लान जीआइएस आधारित है। इसे आठ की जगह 15 जोन में विकसित किया जा रहा है। इसमें गाजियाबाद, लोनी, और मोदीनगर, मुरादनगर को शामिल कर 33,543 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी), मेट्रो, नमो भारत कारिडोर पर आवासीय-व्यावसायिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मिश्रित भू उपयोग आवासीय क्षेत्रों में धड़ल्ले से चल रही व्यावसायिक गतिविधियां मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ा रही हैं। राजनगर या कविनगर जैसे नियोजित क्षेत्रों में भी अब अवैध रूप से दफ्तर और दुकानें खुल गई हैं।

मास्टर प्लान कागजी नक्शा नहीं बल्कि एक जीवंत दस्तावेज बने

बलविंद्र कुमार
पूर्व उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)

राष्ट्रीय राजधानी दुनिया के सबसे गतिशील शहरी केंद्रों में से एक है। आज दिल्ली में करीब दो करोड़ लोगों का घर है। अनुमान है कि 2041 तक यह संख्या बढ़कर 2.9 करोड़ हो जाएगी। इतनी बड़ी आबादी के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा तैयार करना न केवल एक प्रशासनिक आवश्यकता है, बल्कि एक अस्तित्वगत जरूरत भी है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा तैयार 'मास्टर प्लान 2041' (एमपीडी- 2041) इसी दिशा में एक महत्वाकांक्षी खाका है, लेकिन इसे धरातल पर उतारने के लिए अभी भी कई ठोस उपायों और विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है।

एमपीडी 2041 को 2021 में सार्वजनिक समीक्षा के लिए जारी किया गया था। नागरिकों और हितधारकों से 33,000 से अधिक सुझाव प्राप्त हुए। यह हमारे शहर के नियोजित विकास इतिहास में चौथा मास्टर प्लान है, जो 1962, 2001 और 2021 की योजनाओं के बाद आया है। कागज पर, यह हमारे शहर का अब तक का सबसे व्यापक खाका है। लेकिन फिर भी, इतने साल बीत जाने के बावजूद, हम अभी भी इसकी औपचारिक मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अभी तक अपनी अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने फरवरी 2023 में अपनी मंजूरी दे दी थी। लेकिन केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा है कि यह "विचाराधीन" है और मसौदे को अंतिम रूप देने में "कुछ कठिनाइयां" आई हैं। इस बीच, हमारा शहर लगातार बढ़ता जा रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन योजना अभी भी अटकी हुई है। एक आदर्श मास्टर प्लान केवल कागजी नक्शा नहीं, बल्कि एक जीवंत दस्तावेज होना चाहिए। एमपीडी-2041 का विजन दिल्ली को रहने योग्य, टिकाऊ और जीवंत बनाना है। इसमें आवास, परिवहन, हरित क्षेत्र, अर्थव्यवस्था और डिजिटल बुनियादी ढांचे का समावेश है। प्रभावी मास्टर प्लान में 'ट्रांजिट-ओरिएंटेड डेवलपमेंट' (टीओडी) पर जोर होना चाहिए, जहां मेट्रो स्टेशनों के आसपास घनी आबादी और मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा दिया जाए ताकि निजी वाहनों पर निर्भरता कम हो। धरातल पर योजनाओं को लाने के लिए ठोस उपाय योजनाओं को केवल घोषित करना पर्याप्त नहीं है, उन्हें लागू करने के लिए निम्न प्रमुख कदम उठाने होंगे :

सिंगल विंडो क्लीयरेंस और एकीकृत शासन : दिल्ली की सबसे बड़ी समस्या बहु-एजेंसी शासन है। डीडीए, एमसीडी, एनडीएमसी और राज्य सरकार के बीच क्षेत्राधिकार के विवाद अक्सर विकास की गति रोक देते हैं। एक एकीकृत निगरानी तंत्र की आवश्यकता है जो सभी एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करे।

लैंड पूलिंग पालिसी का सरलीकरण : आवास संकट को दूर करने के लिए लैंड पूलिंग एक क्रांतिकारी कदम है। इसमें निजी जमींदारों को योजनाबद्ध विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसके लिए नियमों को सरल बनाना और हितधारकों का भरोसा जीतना अनिवार्य है।

पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता : दिल्ली का वायु प्रदूषण और यमुना की बदहाली एक आपात स्थिति है। मास्टर प्लान में अरावली रिज के संरक्षण और यमुना के बाढ़ क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान होने चाहिए। साथ ही, कचरा प्रबंधन और सौर ऊर्जा के लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना होगा।

पुरानी विसंगतियों को दूर करने का मार्ग : दिल्ली की 30 से 40 प्रतिशत आबादी अनधिकृत कालोनियों या झुग्गी-झोपड़ियों में रहती है। यह पिछले मास्टर प्लानों की सबसे बड़ी विफलता रही है। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए 'इन-सीटू' (जहां झुग्गी, वहीं मकान) पुनर्वास और पुराने नियोजित क्षेत्रों के पुनरुद्धार पर ध्यान देना होगा। पुरानी हो चुकी बुनियादी सुविधाओं को आधुनिक मानकों के अनुरूप अपग्रेड करना अब अनिवार्य है।

मेरा मानना है कि दिल्ली और एनसीआर के पास अब और प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। एमपीडी-2041 को केंद्र सरकार द्वारा जल्द अधिसूचित किया जाना चाहिए। हर साल की देरी का मतलब है- अधिक अनियंत्रित निर्माण, अधिक प्रदूषण और बुनियादी ढांचे पर बढ़ता दबाव। दिल्ली के 2.9 करोड़ भविष्य के नागरिकों के लिए एक ऐसा शहर बनाने का समय आ गया है जो न केवल प्राचीन विरासत को संजोए रखे, बल्कि आधुनिकता की कसौटी पर भी खरा उतरे। ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक सक्रियता ही दिल्ली को एक वैश्विक 'स्मार्ट और सस्टेनेबल' सिटी बना सकती है।

जैसा संजीव गुप्ता को बातचीत में बताया।

बार-बार बिल्डिंग कोड बदलने से फेल हो रही व्यवस्था

प्रो केके यादव
पूर्व चीफ टाउन प्लानर, हरियाणा

दिल्ली सहित एनसीआर में नियोजित शहरी विकास का सपना लंबे समय से अधूरा ही नजर आता है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बिल्डिंग कोड और बायलाज में लगातार किए जा रहे संशोधन मास्टर प्लान की मूल अवधारणा को बार-बार प्रभावित कर रहे हैं। जब भी भवन निर्माण नियमों में बदलाव होता है, तो उसी अनुपात में आबादी का घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन उस बढ़ती आबादी के अनुरूप आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें, सीवर, जलापूर्ति और सार्वजनिक सेवाएं विकसित नहीं हो पाते। नतीजन शहरों पर दबाव बढ़ता जाता है और मास्टर प्लान केवल कागजों तक सीमित होकर रह जाता है। आवश्यक है कि शहर की वास्तविक क्षमता और मौजूदा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही आबादी का निर्धारण किया जाए, ताकि नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं संतुलित तरीके से मिल सकें। एनसीआर में नियोजित विकास के पिछड़ने के पीछे नीतिगत और संरचनात्मक खामियां भी जिम्मेदार रही हैं। मास्टर प्लान तैयार करते समय कंट्रोल एरिया को तो शामिल कर लिया गया, लेकिन वास्तविक शहरी निकाय क्षेत्रों को बाहर कर दिया गया, जबकि विकास का केंद्र वही क्षेत्र थे। इससे योजना और जमीन की वास्तविक स्थिति के बीच असंतुलन पैदा हुआ। इसके अलावा, व्यापक और विज्ञानी शहरी विकास के लिए जरूरी कांप्रिहेंसिव टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट को भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया, जबकि महाराष्ट्र, पंजाब जैसे राज्यों में यह कानून सफलतापूर्वक लागू है।

भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी इस गतिरोध का एक अहम कारण रही है। सरकारों ने बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण तो किया, लेकिन किसानों और स्थानीय हितधारकों को योजना प्रक्रिया में शामिल नहीं किया। इससे न केवल असंतोष बढ़ा, बल्कि योजनाओं के क्रियान्वयन में भी बाधाएं आईं। यदि स्थानीय लोगों को सहभागी बनाया जाता, तो विकास अधिक संतुलित और व्यावहारिक हो सकता था। जनभागीदारी नहीं होने के कारण मास्टर प्लान सफल नहीं हो सके। अवैध निर्माण ने भी मास्टर प्लान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बिना स्वीकृति के खड़ी की गईं इमारतें न केवल शहरी सुंदरता को बिगाड़ती हैं, बल्कि बुनियादी ढांचे पर अतिरिक्त बोझ भी डालती हैं। प्रशासनिक उदासीनता और कमजोर निगरानी तंत्र के चलते यह समस्या लगातार बढ़ती गई। अगर गुरुग्राम की बात करें तो पुराने शहर से लेकर नए गुरुग्राम में अवैध निर्माण इतने हो गए कि सड़कें और ग्रीन बेल्ट ही खत्म हो गईं। कई फीट चौड़ी सड़कें संकरी हो चुकी हैं। नतीनजन, ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण की समस्या है। दिल्ली सहित एनसीआर के लिए प्रस्तावित आठ रीजनल सेंटरों का विकास भी समय पर नहीं हो सका, जिसका सीधा असर राजधानी और आसपास के शहरों पर पड़ा। यदि ये सेंटर विकसित होते, तो आबादी और शहरों का विकेंद्रीकरण संभव होता। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स की प्राथमिकताओं और निर्णयों के चलते सौ से अधिक कारपोरेशन का विकेंद्रीकरण नहीं हो पाया, जिससे दिल्ली और गुरुग्राम जैसे शहरों पर दबाव और बढ़ गया। पर्यावरणीय पहलुओं की अनदेखी भी शहरी संकट को गहरा कर रही है। अरावली क्षेत्र को मास्टर प्लान में समुचित रूप से शामिल नहीं किया गया, जिसके कारण गुरुग्राम में जलभराव की समस्या गंभीर होती जा रही है। मानसून के दौरान शहर का डूब जाना इसी का परिणाम है। पुराने जलस्रोत और बांध समाप्त हो गए, जबकि ग्रीन और ब्लू स्पेस के विकास पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया। गुरुग्राम में सौ से ज्यादा पुराने तालाब शहरी विकास के साथ ही खत्म हो गए। चारों तरफ कंक्रीट है और शहर आबादी के बोझ को झेल रहा है। सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा तक नहीं है। मास्टर प्लान के अनुसार अगर तेजी से काम होते तस्वीर ही कुछ अलग होती।

स्पष्ट है कि दिल्ली सहित एनसीआर में नियोजित विकास के लिए केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें स्थिर नीति, सख्त क्रियान्वयन और स्थानीय सहभागिता के साथ लागू करना भी जरूरी है। जब तक नीतिगत निरंतरता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित नहीं होगी, तब तक मास्टर प्लान वास्तविक विकास का माध्यम नहीं बन पाएंगे।

-जैसा बातचीत में संदीप रतन को बताया।

स्मार्ट विजन चश्मे : आवाज से दिखा रहे नेत्र दिव्यांगों को राह, कर रहे सतर्क भी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: एआइ आधारित स्मार्ट विजन चश्मा नेत्र दिव्यांगों के लिए नई उम्मीद बन कर आया है। जिनकी आंखें नहीं हैं या दृष्यता बुरी तरह प्रभावित है, यह उन्हें आवाज से दुनिया दिखा रहा है। एआइ, कैमरा और रियल टाइम आडियो गाइडेंस से इसने उनके लिए चलने-फिरने के साथ पढ़ना और समझना आसान कर दिया है। कैमरा व एआइ की मदद से चश्मा सामने के दृश्य की पहचान कर उसे तुरंत आडियो में बदल देता है- जैसे 'सामने सीढ़ी है', 'दरवाजा बाईं ओर है' या 'कोई व्यक्ति पास खड़ा है।' इसमें टेक्स्ट पढ़कर सुनाने, चेहरा और वस्तु पहचानने, रास्ता बताने और आपात स्थिति में मदद मांगने की भी व्यवस्था है। यह चश्मा नेत्र दिव्यांगों के लिए 'देखने' का नया तरीका बन गया है।

स्मार्ट विजन चश्मे दो तरह की तकनीक पर काम करते हैं। कुछ

स्मार्ट विजन चश्मा ●

स्मार्ट विजन चश्मों में इयरबड से और कुछ में चश्मे की डंडी में कान के पीछे की हड्डी में हल्के कंपन (ध्वनि तरंगों) से मस्तिष्क तक आवाज पहुंचाने की तकनीक होती है। दूसरी तकनीक में कान के पर्दे को बाईपास कर दिया जाता है। इससे कान खुले रहते हैं और रियल टाइम में आसपास की आवाज भी सुनाई देती रहती है।

एम्स चिकित्सकों के अनुसार, यह तकनीक न केवल दैनिक जीवन को सरल बनाती है, बल्कि शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के नए अवसर भी खोलती है। एक चश्मे की कीमत करीब 35 हजार बताई गई है। एम्स आरपी सेंटर की प्रमुख प्रो. राधिका टंडन के अनुसार एआइ आधारित यह तकनीक लोगों की दूसरों पर निर्भरता कम कर आत्मनिर्भर बनाती है।

40 नेत्र दिव्यांग छात्रों-शिक्षकों को स्मार्ट विजन चश्मे बांटे : दिल्ली एम्स के डा. आरपी सेंटर में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में नेत्र दिव्यांग छात्रों-शिक्षकों को निश्शुल्क स्मार्ट विजन चश्मे वितरित किए गए। एम्स ने यह पहल रोटरी जिला 3012, एसएचजी और विजन एड के सहयोग से की। सेंटर के वरिष्ठ विशेषज्ञ प्रो. प्रवीण वशिष्ठ ने बताया कि एम्स ऐसे कार्यक्रम लगातार चला रहा है। प्रो. तनुज दादा ने इसे कार्यात्मक दृष्टि सुधारने में महत्वपूर्ण बताया, जबकि रोटरी जिला 3012 की गवर्नर डा. अमिता मोहिंद्रु ने इसे तकनीक और सामुदायिक सहयोग का प्रभावी उदाहरण बताया।

बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर की हत्या, खुद दी पुलिस को सूचना

जागरण संवाददाता, पलवल: शहर थाना अंतर्गत मुख्य बाजार में बड़े भाई ने छोटे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। दोनों स्वर्ण कारीगर थे। चौंकाने वाली बात यह है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपित खुद शहर थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। शहर थाना पुलिस ने मामले में आरोपित को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है।

मृतक का फ़ाइल फोटो ● स्वजन

राजस्थान के पाली के रहने वाले सुरेश और उसका छोटा भाई विक्रम दरबार कुंआ के समीप दूसरी मंजिल पर किराए के कमरे में रहते थे। दोनों करीब एक साल से यहां काम कर रहे थे। बुधवार सुबह करीब चार बजे किसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच कहासुनी हो गई। इसका शोर आसपास रह रहे लोगों को सुनाई दिया। इसके बाद सुरेश ने आपा खो दिया और चाकू से हमला कर अपने 19 वर्षीय छोटे भाई विक्रम की हत्या कर दी। वारदात के बाद सुरेश ने आसपास के लोगों को भी बताया कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी है। इसके बाद, वह खुद शहर थाने पहुंचा और पुलिस को मामले की सूचना दी। घटना की सूचना पाकर शहर थाना प्रभारी प्रकाशचंद अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और आरोपित को हिरासत में ले लिया।

थाना प्रभारी प्रकाशचंद के अनुसार, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो सका है कि आरोपित ने इतनी बड़ी वारदात को किस वजह से अंजाम दिया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। स्थानीय निवासियों के अनुसार, घटना के बाद आरोपित बिना किसी डर के काफी देर तक बाजार में घूमता रहा। इस वारदात के बाद बाजार में भय का माहौल है।

पीरागढ़ी तिहरे हत्याकांड में चार्जशीट दाखिल, धनवर्षा का झांसा देकर पिलाया गया था जहर

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : बाहरी जिला पुलिस ने पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास कार में मिले तीन शवों के मामले में अदालत में करीब 300 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की है। इसमें उल्लेख किया गया है कि तिहरा हत्याकांड सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दिया गया था। घटना 8 फरवरी को सामने आई थी, जब पीरागढ़ी फ्लाईओवर की सर्विस लेन में खड़ी एक कार में तीन लोग रणधीर (76), शिव नरेश (42) और लक्ष्मी (40) के शव मिले थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

8 फरवरी को सामने आया था मामला, पीरागढ़ी फ्लाईओवर के पास कार में मिले थे महिला समेत तीन लोगों के शव

पुलिस अधिकारी के अनुसार चार्जशीट में बताया गया है कि जांच के दौरान काल डिटेल रिकार्ड, डिजिटल साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के विश्लेषण से आरोपित कमरुद्दीन की भूमिका पता चली। महिला समेत तीनों लोग आर्थिक लाभ के लालच में कमरुद्दीन के संपर्क में आए थे और घटना वाले दिन लोनी से लौटते समय वह उनके साथ कार में मौजूद था। रास्ते में आरोपित ने शराब, कोल्ड ड्रिंक और खाने की वस्तुओं में जहर मिलाकर उन्हें पिलाया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद वह नकदी और अन्य सामान लेकर फरार हो गया था।

घटनास्थल से बरामद बोतलें, गिलास, कार मैट, मोबाइल फोन और अन्य वस्तुओं की फोरेंसिक जांच में जहर के अंश मिले हैं। एक सीसीटीवी फुटेज में उसे बैग के साथ कार से उतरते हुए भी देखा गया, जिसे चार्जशीट में अहम साक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है। चार्जशीट में आरोपित को आदतन अपराधी बताया गया है और उसके खिलाफ पूर्व में दर्ज मामलों का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपित अब तक आठ हत्याओं में शामिल रहा है, जिनमें दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मामले शामिल हैं। वर्ष 2014 में राजस्थान के धौलपुर जिले और वर्ष 2025 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दर्ज मामलों का जिक्र भी चार्जशीट में किया गया है।

चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि आरोपित लोगों को धनवर्षा का लालच देकर अपने संपर्क में लाता था और जिन्न के नाम पर डर पैदा कर विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाता था। इस प्रक्रिया में महिलाओं का मानसिक रूप से दुरुपयोग और शोषण किए जाने के आरोपों का भी उल्लेख किया गया है। पुलिस अब ऐसे संभावित पीड़ितों की पहचान करने में जुटी है।

दैनिक जागरण

दृढ़ता ही विजय का आधार बनती है

राहत भरी खबर

यह केवल पश्चिम एशिया ही नहीं, पूरे विश्व के लिए राहत की बात है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के आसार बढ़ गए हैं। इसका संकेत इससे मिलता है कि जहां दोनों देश एक 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव पर विचार-विमर्श कर रहे हैं, वहीं अमेरिका ने ईरान के खिलाफ आपरेशन एपिक फ्यूरी नामक अपने सैन्य अभियान को समाप्त करने के साथ होर्मुज समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन फ्रीडम को भी रोकने की घोषणा की। आपरेशन फ्रीडम के बाद भी जहाजों का आवागमन सुगम तो नहीं हो पाया था, लेकिन शायद ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ने ईरान के नेतृत्व को अपना रवैया नरम करने को बाध्य किया। जो भी हो, जब तक दोनों पक्षों के बीच वास्तव में समझौता नहीं हो जाता, तब तक न तो पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की आशा की जा सकती है और न ही पूरी दुनिया को बुरी तरह प्रभावित कर रहे ऊर्जा संकट से मुक्ति की। ध्यान रहे कि अमेरिका और ईरान के बीच पहले दौर की शांति वार्ता नाकाम हो गई थी और दूसरे दौर की वार्ता हो ही नहीं पाई थी। इसके बाद दोनों देश एक-दूसरे को धमकाने में जुट गए थे।

विश्व अमेरिका और ईरान के बीच स्थायी शांति की कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, इसका पता इससे चलता है कि दोनों के बीच समझौते की दिशा में आगे बढ़ने की खबर आते ही तेल के दाम गिर गए और शेयर बाजारों में भी सकारात्मक असर दिखा। यदि किसी कारण दोनों देशों के बीच होने वाली वार्ता में ठोस प्रगति नहीं होती तो टकराव की आशंकाएं उभरने में देर नहीं लगेगी। ऐसा न हो, इसके लिए जहां अमेरिका को सब कुछ अपने मन मुताबिक होने की अपेक्षा का परित्याग करना होगा, वहीं ईरान को भी अपना यह हठ छोड़ना होगा कि परमाणु मसले पर कोई समझौता नहीं हो सकता और होर्मुज पर उसका अधिकार होना चाहिए। ईरान कुछ भी कहे, उसे न तो परमाणु हथियार बनाने की अनुमति दी जा सकती है और न ही इसकी कि वह होर्मुज को अपनी निजी जागीर माने। यदि ईरान चैन से रहने के साथ औरों को भी चैन से रहने देना चाहता है तो उसे इजरायल के लिए खतरा बने हमास, हिजबुल्ला जैसे आतंकी गुटों को सहयोग-समर्थन देने से पीछे हटना होगा। उसे इस्लामी जगत का अगुआ बनने की मानसिकता भी छोड़नी होगी, क्योंकि खाड़ी देश पश्चिम एशिया में उसके दबदबे को कभी स्वीकार नहीं करने वाले। ईरान आज जिस स्थिति में है और विशेष रूप से जिस प्रकार यह जानना कठिन है कि वहां वास्तविक नेतृत्व किसके हाथ में है, तब तक न तो अमेरिका उससे समझौते के लिए बहुत आशान्वित हो सकता है और न ही विश्व। वैसे अंततः किसी बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। अच्छा होता कि अमेरिका इसे समय रहते समझता और ईरान से वार्ता का क्रम तोड़कर उस पर हमला करने से बचता।

जनभावनाओं का सम्मान

उत्तर प्रदेश में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था समाप्त करने के निर्णय से उन उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, जो बिल भुगतान करने के बाद भी असुविधा झेल रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हस्तक्षेप से अब प्रदेश में 83 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं के प्रीपेड स्मार्ट मीटर पुरानी व्यवस्था के अनुरूप ही चलेंगे। उपभोक्ताओं के समवेत विरोध के कारण यह निर्णय किया गया। बदलाव की इस पूरी प्रक्रिया में उपभोक्ताओं की संतुष्टि का विभाग या कार्यदायी एजेंसी ने ध्यान नहीं रखा, अन्यथा फैसले को इतनी जल्दी वापस लेने की स्थिति नहीं बनती। विभागीय मंत्री को इस बात की जांच करानी चाहिए कि आखिर नई व्यवस्था की खामी को दूर किए बिना योजना लागू ही कैसे हो गई? प्रीपेड मीटर को लेकर उपजा आवेश किसी एक दिन की खोज का परिणाम नहीं है। पुराने मीटर में बदलाव के साथ ही शुरू हुई व्यावहारिक असुविधा से लोग तंग आ गए थे। स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कराए जाने के बाद भी घंटों बिजली का कनेक्शन स्वतः न जुड़ना, बिल की अन्य विसंगतियों से लोग परेशान थे। बिजली बिल भरने से जी चुराने वालों पर सख्ती होनी ही चाहिए। यहां तो असुविधा उन्हें हो रही थी, जो उपभोग की वास्तविक कीमत चुका रहे थे। निश्चय ही यदि समय से उपभोक्ताओं की असुविधा का समाधान किया गया होता, तो यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करती।

> प्रीपेड स्मार्ट मीटर की व्यवस्था लागू करने से पहले ही विभाग को उपभोक्ता संतुष्टि का परीक्षण करा लेना चाहिए था

सामरिक तैयारी को देनी होगी और धार

हर्ष वी. पंत

आपरेशन सिंदूर ऐसा पड़ाव बनकर उभरा था, जहां मंशा, क्षमता और रणनीतिक पहलू स्पष्टता के साथ एक दूसरे के साथ ताल मिलाते दिखे थे

अवधेश राजपूत

भारत की पाकिस्तान नीति में आपरेशन सिंदूर एक निर्णायक पड़ाव के रूप में सामने आया था। एक सीमित अवधि में चले इस सैन्य अभियान के परिणाम बहुत व्यापक निहितार्थों वाले रहे। पहलगाम में हुए नृशंस आतंकी हमले के जवाब में इस अभियान के दौरान पाकिस्तान के सुदूरवर्ती स्थलों पर संचालित आतंकी ठिकानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त करने का काम किया गया। आतंकी ढांचे पर नई दिल्ली की यह प्रतिक्रिया न तो नितांत भावनात्मक रही और न ही विशुद्ध प्रतीकात्मक। यह एक नपी-तुली सुनियोजित सामरिक कार्रवाई थी, जिसने प्रतिरोध के नए पैमाने को परिभाषित करने का काम किया। भारत की ओर से ऐसा करारा जवाब दिया गया और ऐसे-ऐसे पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, जिनके बारे में पाकिस्तान ने शायद सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान की मनुहार के बाद भारत ने चार दिन बाद भले ही संघर्ष विराम पर सहमति जताई हो, लेकिन यह भी स्पष्ट कर दिया कि अभियान केवल थमा है, समाप्त नहीं हुआ। आपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने न केवल अपनी मारक क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बल्कि वह दृढ़ता भी दिखाई कि उस पर हुए हमलों का किसी भी कीमत पर ऐसा जवाब दिया जाएगा, जिसे दुश्मन लंबे अर्से तक याद रखे। राजनीतिक नेतृत्व की स्पष्टता के साथ सैन्य बलों ने अपने शौर्य का अप्रतिम परिचय दिया।

हर सफलता अपने साथ कुछ सबक लेकर आती है और इस पैमाने पर आपरेशन सिंदूर भी अपवाद नहीं रहा। इसमें पाकिस्तान की परमाणु हेकड़ी की हवा पूरी तरह निकल गई। हालांकि तनाव भड़कने से जुड़े पहलू अभी भी कायम हैं, लेकिन भारत के स्पष्टता भरे रुख ने एक रेखा अवश्य खींच दी है। आपरेशन सिंदूर तीनों सेनाओं के बीच अद्भुत समन्वय का साक्षी भी बना। विशेष रूप से अरब सागर में नौसेना की तत्परता से तैनाती से जुड़ा पहलू बहुत सराहनीय रहा। इसके बावजूद यह भी स्वीकार करना होगा कि तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य को बेहतर बनाने की दिशा में अभी और प्रयास करने होंगे। खासतौर से रीयल टाइम में परिचालन को लेकर।

आपरेशन सिंदूर ने लक्ष्य को चिह्नित कर सटीक प्रहार की क्षमताओं के साथ दूर से ही दुश्मन को सबक सिखाने में सुरक्षा बलों की भूमिका को और पुख्ता किया। मिसाइल, ड्रोन और बियोंड-विजुअल रेंज वाले संघर्ष ने भारत के जोखिम घटाते हुए हमलों के अधिकतम प्रभाव को सुनिश्चित किया। हालांकि इस दौरान हवाई रक्षा प्रतिरोध, ड्रोन रोधी क्षमताओं, खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही क्षमताओं के अलावा संचार संबंधी लचीलेपन के स्तर पर मौजूद कुछ कमजोरियां भी उजागर हुईं। नीति-नियंताओं के लिए इसका स्पष्ट संदेश है कि प्रणालीगत पूर्ण एकीकरण के अभाव में केवल अपनी सुविधा के साथ विशिष्ट तकनीकों को अपनाने की अपनी सीमाएं भी होती हैं। वैसे तो इस सैन्य संघर्ष में भारत ने निर्णायक प्रभुत्व के साथ सफलता हासिल की, लेकिन शुरुआती स्तर पर लगे कुछ झटकों ने सैन्य क्षमताओं में विद्यमान कुछ असंतुलन की ओर भी संकेत किया। आवश्यक स्क्वाड्रन क्षमताओं का अभाव, लंबी दूरी तक प्रहार करने वाली प्रणालियों की सीमाएं और इलेक्ट्रानिक युद्ध के मोर्चे पर जो कमजोरियां दिखीं, उन्हें तत्काल दूर कर स्वयं को सशक्त करना होगा।

आपरेशन सिंदूर के साथ ही भारत ने आतंकवाद से निपटने को लेकर अपना दृष्टिकोण और स्पष्ट किया। भारत ने स्पष्ट कर दिया था कि आतंकवादी तत्वों और उन्हें संरक्षण देने वाले देशों के बीच कोई अंतर नहीं किया जाएगा और उन्हें इसकी कीमत भी चुकानी होगी। इस अभियान से संबंधित तकनीकी आयाम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस क्रम में ड्रोन, लायटरिंग म्यूनिशंस यानी घातक ड्रोन और अत्याधुनिक हवाई रक्षा कवच का व्यापक उपयोग न केवल भारत के अपने अनुभवों पर आधारित रहा, बल्कि उसने समकालीन वैश्विक संघर्षों के रुझानों से लिए गए सबक का लाभ भी उठाया। इसका ही परिणाम है कि भारत ने रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भरता के प्रयासों को तेज कर दिया है। आपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिले चीनी खुफिया एवं सैन्य सामग्री सहयोग-समर्थन को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस जटिलता ने दो मोर्चों पर संभावित संघर्ष को लेकर भारत की तैयारी को और पुख्ता बनाने की आवश्यकता को कहीं अधिक गहराई से रेखांकित किया है।

हमें अपनी मंशा और क्षमताओं दोनों को और धार देनी होगी और यह बात केवल घोषणाओं तक सिमटकर न रह जाए, बल्कि आवश्यकता पर तत्परता से उपयोग योग्य भी बने। चीफ आफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जैसी पहल बहुत अच्छी रही है, लेकिन इस ढांचे के अंतर्गत सशस्त्र बलों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाना होगा। यह सही है कि समन्वय में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन नियोजन, कमान ढांचे और संसाधनों के आवंटन में एकीकरण के अभाव और असंतुलन की कुछ स्थिति बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती मंशा को मूर्त रूप देने की होगी। जैसे सैन्य बलों की संस्थागत संस्कृतियों में सामंजस्य बैठाना, सेना के विभिन्न अंगों में लचीलापन बढ़ाना और सामरिक तैयारियों की दिशा में एकीकृत ढांचा तैयार करना। यदि रणनीतिक बदलाव को स्थायी बनाना है, तो तकनीक के आधुनिकीकरण के साथ संगठनात्मक सुधारों पर भी ध्यान देना ही होगा।

भारत के सामरिक परिदृश्य में आपरेशन सिंदूर एक ऐसा पड़ाव बनकर उभरा, जहां मंशा, क्षमता और रणनीतिक पहलू पूरी स्पष्टता के साथ एक दूसरे के साथ ताल मिलाते दिखे। इसने दर्शाया कि यह दबाव में आने वाला पुराना भारत नहीं, बल्कि दुश्मन पर दबाव बनाने वाला भारत है, जहां तकनीकी श्रेष्ठता का लाभ उठाकर संघर्ष का दायरा बढ़ाए बिना ही अपने विकल्पों में वृद्धि करने में बड़ी सफलता मिली। उस संघर्ष में मिली सफलता को कायम रखने के लिए आवश्यक होगा कि ऐसा राजनीतिक संकल्प लिया जाए जो दिखावटी सुधारों के बजाय संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दे। यदि ऐसा न हुआ तो आपरेशन सिंदूर से उपजी संभावनाएं एक गंवाए हुए अवसर का प्रतीक बनकर ही रह जाएंगी।

(लेखक सामरिक विश्लेषक हैं)
response@jagran.com

आत्ममंथन के बजाय आरोपों का सहारा

पीयूष पांडे

लोकतंत्र में सवाल उठाना आवश्यक हैं, लेकिन हर चुनावी हार को साजिश बताना एक खतरनाक प्रवृत्ति हैं

वास्तविकता से मुंह मोड़ने की नाकाम कोशिश। प्रेट्र

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों के बीच विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआइए का पूरा विमर्श पश्चिम बंगाल के इर्द-गिर्द सिमटता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी और राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर नतीजों को प्रभावित किया। ममता ने यहां तक कहा कि वे हार को 'साजिश' का परिणाम मानती हैं। उल्लेखनीय है कि 2014 के बाद से हुए कई चुनावों में विपक्षी दलों ने अपनी हार के कारणों का ठोस आत्ममंथन करने के बजाय आरोपों की राह अधिक चुनी है। 2014 में भाजपा की बड़ी जीत के बाद ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा जोर-शोर से उठा, जो हर चुनावी हार के बाद समय-समय पर सामने आता रहा है। हालांकि 2017 में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित 'ईवीएम चैलेंज' में कोई भी दल मशीनों में छेड़छाड़ का दावा साबित नहीं कर पाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर वीवीपैट प्रणाली को व्यापकता से लागू किया गया, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगते ही रहते हैं।

बंगाल में बात ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों से भी आगे निकल गई है। अब विपक्षी दलों का आरोप है कि निर्वाचन आयोग ने पहले गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी एसआइआर के तहत लाखों मतदाताओं के वोट काटे और फिर चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों ने भाजपा के इशारे पर काम करते हुए चुनावी गड़बड़ी की। यदि चुनाव प्रक्रिया इतनी व्यापक रूप से प्रभावित की जा सकती थी, तो अन्य राज्यों तमिलनाडु या केरलम में अलग-अलग नतीजे कैसे आए? केरलम में तो कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली है।

विपक्ष इस तथ्य को नकार देता है कि बंगाल में भाजपा की उपस्थिति कोई नई नहीं है। पहले जनसंघ और बाद में भाजपा वहां पैर जमाने की कोशिश सदैव करती रही। 2016 के विधानसभा चुनाव में उसे 10 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे, जो 2021 में बढ़कर 37.97 प्रतिशत हुए और अब 45.85 प्रतिशत। तृणमूल कांग्रेस के वोट 2021 के 48.02 प्रतिशत से घटकर 2024 में 40.80 प्रतिशत पर आ गए। 15 साल की एंटी इनकंबेंसी, भ्रष्टाचार के आरोप, मुस्लिम तुष्टीकरण के विरुद्ध हिंदू ध्रुवीकरण, महिलाओं की सुरक्षा और कांग्रेस, वाम दलों का तृणमूल के खिलाफ होना ममता की हार की वजहों में रहे।

चुनावी धांधली का आरोप नया नहीं है। तमाम प्रयासों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह दोषमुक्त कभी नहीं रही। दिलचस्प है कि 1952 में जब पहला चुनाव हुआ था, तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को 9 फरवरी 1952 को एक पत्र लिखा था, 'मुझे समय-समय पर चुनावों के संचालन के तरीके के बारे में विभिन्न शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।...आज सुबह मुझे उत्तर प्रदेश के बारे में शिकायत मिली कि कई स्थानों पर मतदान पेटियों को बदल दिया गया या उनके साथ छेड़छाड़ की गई।' बाद के वर्षों में बिहार, तमिलनाडु, जैसे कई राज्यों में भी चुनावी गड़बड़ियां होती रहीं। 1995 में बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त बूथ लूट और हिंसा रोकने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ने पहली बार कई चरणों में चुनाव कराए। राज्य में बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई। उस वक्त लालू यादव खुलकर टीएन शेषन के खिलाफ बोलते थे। बंगाल में चुनावी हिंसा की अति हो गई थी। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त बंगाल में चुनावी हिंसा में सात मौतें और करीब 2,652 लोग घायल हुए। 2021 के विधानसभा चुनाव के दौरान तो 300 से ज्यादा हिंसक घटनाओं में 58 मौतें हुईं। इन हालात में केंद्रीय बलों की मौजूदगी ने अगर मतदाताओं को भयमुक्त होकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया तो इसे गलत कैसे कहा जा सकता है? क्या ये भी एक वजह नहीं है कि बंगाल में मतदान के पहले चरण में 93.19 और दूसरे चरण में 91.66 प्रतिशत वोट पड़े? इसमें कोई शक नहीं कि एसआइआर का क्रियान्वयन और बेहतर होना चाहिए था, पर विपक्षी दलों की एसआइआर पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश सिर्फ एक नैरेटिव बनाने का ही दांव है, जिसका उन्हें लाभ कम और लोकतांत्रिक ढांचे को नुकसान अधिक है।

संभव है कि बंगाल में एसआइआर के चलते कुछ लोग मतदान से वंचित हुए होंगे, पर विपक्ष वास्तव में एसआइआर के मुद्दे पर चिंतित था, तो उसे बयानबाजी से आगे बढ़ना चाहिए था। यदि वह पांच-सात हजार प्रभावित लोगों को ही आगे कर देता, तो मुद्दा राजनीति के केंद्र में आ जाता, पर केवल बयानबाजी होती रही। एसआइआर के तहत जहां अधिक नाम कटे, वहां भाजपा के साथ टीएमसी ने भी जीत हासिल की है। लोकतंत्र में सवाल उठाना आवश्यक है, किंतु हर हार को साजिश बताना खतरनाक है। इससे संस्थाओं पर अविश्वास बढ़ता है, बल्कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भी भटकता है। विपक्षी दलों के लिए जरूरी है कि वे जमीनी मुद्दों, संगठनात्मक मजबूती और वैकल्पिक नीति का एजेंडा बनाएं। ईवीएम में गड़बड़ी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत जैसे आरोप जनता के गले नहीं उतरते।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

मन की दिशा बदलेगी दशा

मन यदि नियंत्रण में हो तो वह मनुष्य को नर से नारायण और भटक जाए तो नर से नराधम बना देता है। गुरु नानक देव जी ने कष्टों से मुक्ति का एक ही उपाय बताया 'मन जीते, जग जीत।' कबीरदास जी ने 'मन के हारे हार है, मन के जीते जीत' का संदेश दिया। वस्तुतः, हमारा मन उस जलाशय की भांति है, जिसका स्थिर जल हवा के प्रभाव से लहरों में परिवर्तित होकर शीघ्र गतिमान हो जाता है। मन क्षण-क्षण कहीं न कहीं दौड़ता रहता है। मन यदि बुरे विचारों में निमग्न है तो स्वभावतः उस बुराई की अगणित प्रेरणा, योजना मस्तिष्क के सामने आती चली जाएंगी और मन क्रमशः उनके लिए प्रशिक्षित होता चला जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने यथार्थ ही कहा है कि एक प्रखर नियंत्रित और शांत मन संसार का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिसके सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक है।

सांसारिक विषय-भोग मन को और चंचल बनाते हैं। इसलिए मन को आत्मा के स्वाभाविक गुण शील, क्षमा, संतोष, विवेक और नम्रता आदि गुणों का रसास्वादन कराना होगा। हृदय में प्रेम भावना का विकास कर दोषों का शमन करना होगा। दोषों का शमन होते ही अवरोधों के टूट जाने से हृदय में ईश्वर का वास होगा। आज हम तन से नहीं मन से बीमार हैं। मन में संकल्प-विकल्प आते, मन की बीमारी तन में चली जाती है। इसलिए जरूरी है मन का संशोधन करें। जब मन निर्मल होता है तो हमारा तन भी निर्मल हो जाता है और जीवन भी निर्मल हो जाता है। कोई प्यादा मर्यादा में ही रहेगा, बशर्ते शासक अनुशासन में हो। शासक हमारा मन और प्यादा हमारी इंद्रियां। जब मन कमजोर होता है तो स्थिति समस्या होती है, जब मन संतुलित होता है तो स्थिति चुनौती होती है। अगर हमारे भीतर की आत्म-शक्ति, इच्छा-शक्ति मजबूत है तो बाहर का बुरा प्रभाव भी हमें विचलित नहीं कर सकेगा।

डा. निर्मल जैन

व्यर्थ बहने वाले पानी का हो सदुपयोग

रेणु जैन

छोटे-छोटे एवं व्यावहारिक प्रयासों से रोजाना करोड़ों लीटर व्यर्थ बहने वाले पानी का सदुपयोग किया जा सकता हैं

भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में जल संकट एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, खासकर गर्मियों के मौसम में। एक ओर जहां कई शहरों और गांवों में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हर दिन करोड़ों लीटर पानी अनजाने में व्यर्थ बह जाता है। ऐसे समय में दुनिया के कुछ देशों द्वारा अपनाई गई जल संरक्षण प्रभावी तकनीकें हमारे लिए प्रेरणा बन सकती हैं। जापान इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

जापान में पानी बचाने के लिए एक अनोखी और बेहद व्यावहारिक व्यवस्था अपनाई गई है। वहां कई घरों और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे सिंक लगाए जा रहे हैं, जिनमें हाथ धोने का पानी सीधे शौचालय के फ्लश टैंक में जमा हो जाता है। यानी जब कोई व्यक्ति हाथ धोता है, तो वही पानी फ्लश के लिए उपयोग में लाया जाता है। इस प्रणाली से साफ पानी की दोबारा उपयोगिता सुनिश्चित होती है और अनावश्यक बर्बादी को रोका जा सकता है।

भारत में जल प्रबंधन की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। घरों में, कार्यालयों में और सार्वजनिक स्थानों पर पानी का अत्यधिक दुरुपयोग होता है। खुले नल, लीक होती पाइपलाइनें, वाहन धोने में जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल, ये सभी समस्याएं आम हैं। परिणामस्वरूप, लोगों को पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की मांग भी बढ़ जाती है, लेकिन पर्याप्त प्रबंधन के अभाव में आपूर्ति कम पड़ जाती है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में लोग कई किमी दूर से पानी लाते हैं।

ऐसे हालात में जापान जैसे देशों से सीख लेना बेहद जरूरी है। यदि भारत में भी घरों और सार्वजनिक स्थानों पर पानी के पुनः उपयोग की तकनीकों को अपनाया जाए, तो काफी हद तक जल संकट को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वाशबेसिन के पानी को फ्लश में उपयोग करने की व्यवस्था, वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) और ग्रे वाटर रीसाइक्लिंग जैसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके अलावा, लोगों में जल संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

सरकार की भूमिका भी इस दिशा में अहम है। नीतियों और योजनाओं के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नए भवनों में जल पुनर्चक्रण प्रणाली को अनिवार्य किया जा सकता है। साथ ही, पुराने भवनों में भी ऐसी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा सकता है। जल संकट केवल सरकार या किसी एक संस्था की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। जापान की तरह छोटे-छोटे कदम उठाकर हम भी जल संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जल है तो जीवन है- इस सच्चाई को समझते हुए हमें हर बूंद की कीमत पहचाननी होगी।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

बेनकाब हुआ फर्जी सेक्युलरिज्म

'फिर खुली फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ स्वयं ममता बनर्जी की हताशा भरी पराजय के कारणों की पड़ताल करते हुए ठीक ही कहा है कि बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिमपरस्ती की कीमत चुकानी पड़ी। सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हिंदू समुदाय को जातियों के खेमे में बंटा मानकर मुसलमानों को एकमुश्त वोटबैंक के रूप में देखने के आदी हो चुके हैं। भाजपा की रीति-नीति से इतर स्वयं को सेक्युलर साबित करने के लिए ये मुस्लिम वोटबैंक को आकर्षित करने का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहते। बंगाल की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहने के लिए ममता बनर्जी ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रश्रय देकर मुस्लिमपरस्ती का सुविधाजनक कार्ड खेला, जो कालांतर में भाजपा की सधी चुनावी रणनीति के आगे फुस्स साबित हुआ। भाजपा ने ममता शासन की अराजकता और मुस्लिम तुष्टीकरण से आजिज आ चुके हिंदुओं में टीएमसी की सत्ता उखाड़ फेंकने का जो विश्वास भरा मंत्र फूंका, वह उनके मन में गहराई तक उतर गया। अबकी बार भाजपा की चाकचौबंद चुनावी रणनीति, चुनाव आयोग के सख्त रवैये और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने बंगाल की डरी-सहमी आम जनता को निर्भीकता से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए न केवल प्रोत्साहित किया, अपितु मतदान के बाद भी उनमें सुरक्षा का भरोसा पैदा किया। बंगाल के एकजुट हिंदुओं ने राजनीति की उस अवधारणा को ध्वस्त कर दिया कि हिंदू वोट कभी एकजुट नहीं हो सकता। हिंदुओं के ध्रुवीकरण से बंगाल का मजबूत किला ढह जाने से मुस्लिम तुष्टीकरण की विकृत राजनीति करने वाले दल सकते में हैं। उनका फर्जी सेक्युलरिज्म बेनकाब हो गया। अब हिंदू जनभावना की उपेक्षा करके मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना घाटे का सौदा होगा।

pandeywp1960@gmail.com

लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि

बुधवार को प्रकाशित अग्रलेख "ममता का हठ" पढ़ा। बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के उपरांत भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा न देने का निर्णय राजनीतिक हठधर्मिता है। भारतीय लोकतंत्र में यह पहला उदाहरण है, जब कोई मुख्यमंत्री चुनाव हारने के उपरांत अपने पद से इस्तीफा देने से इनकार कर रहा है। इस प्रसंग में ममता बनर्जी का रुख राजनीतिक परिपक्वता पर प्रश्न खड़े करता है। यदि जनादेश स्पष्ट रूप से सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है, तो उसे विनम्रता से स्वीकार करना लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है। ममता बनर्जी अपने समर्थकों को संदेश देने का प्रयास कर रही है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और वे उनका सहानुभूति प्राप्त करना चाहती हैं। जबकि उन्हें समझना चाहिए कि आज का मतदाता जागरूक हो चुका है। जिस मतदाता ने उन्हें बंगाल की सत्ता सौंपी थी, आज उसी ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया है। लोकतंत्र में जनादेश सर्वोपरि है और नेताओं को उसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, यही स्वस्थ राजनीति की पहचान है।

हिमांशु शेखर केसपा, गयाजी

सेक्युलरिज्म के संवैधानिक अर्थ

फिर खुली फर्जी सेक्युलरिज्म की पोल- शीर्षक से बुधवार को प्रकाशित संपादकीय लेख समकालीन भारतीय राजनीति के एक अत्यंत संवेदनशील और बहुचर्चित विषय पर गंभीर विमर्श प्रस्तुत करता है। इस लेख में उठाया गया यह बिंदु कि ''सेक्युलरिज्म'' का प्रयोग कई बार एक राजनीतिक औजार के रूप में किया जाता रहा है, निस्संदेह विचारणीय है। परंतु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि क्या हम 'सेक्युलरिज्म' के मूल संवैधानिक अर्थ समानता, निष्पक्षता और धार्मिक निरपेक्षता से भटक नहीं गए हैं? इस बहस का निष्कर्ष आलोचना तक सीमित न रहकर समाधान की दिशा में भी बढ़ना चाहिए।

बिमलेश कुमार सिंह चौहान, लखनऊ

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:

दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशनलि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

आशुतोष दीक्षित बने पोर्शे इंडिया के ब्रांड निदेशक

नई दिल्ली: स्कोडा आटो फाक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने मंगलवार को आशुतोष दीक्षित को भारत में पोर्शे ब्रांड का निदेशक नियुक्त किए जाने का एलान किया। कंपनी ने कहा कि दीक्षित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। वह मनोलिटो वूजिकिक की जगह लेंगे, जिन्होंने ग्रुप के बाहर नए अवसर तलाशने का फैसला किया है। दीक्षित के पास वाहन उद्योग में 28 साल से अधिक का अनुभव है। इसमें से लगभग दो दशक उन्होंने फाक्सवैगन समूह के साथ बिताए हैं। (प्रेट्र)

पश्चिम एशिया में लंबा खिंचने वाला संघर्ष, समुद्री आपूर्ति में बाधाएं और ऊंची ऊर्जा कीमतें भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं और देश की जीडीपी वृद्धि दर को 6.5 प्रतिशत से नीचे ला सकती हैं।
– राजीव मेमानी, प्रेसिडेंट, सीआइआइ

संसेक्स	77,958.52	▲ 940.73
निफ्टी	24,330.95	▲ 298.15
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 1,55,400	▲ ₹ 2,900
चांदी प्रति किलो ग्राम	₹ 2,54,500	▲ ₹ 3,500
डालर	₹ 94.49	▼ ₹ 0.69
क्रूड प्रति बैरल	$ 101.1	

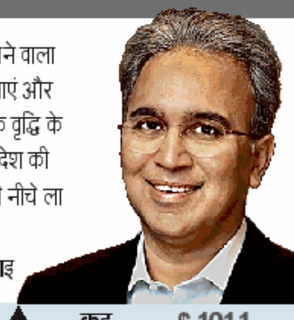

एक नजर में

सोना 2,900 तो चांदी 3,500 रुपये बढ़ी

नई दिल्ली: बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोना 2,900 रुपये बढ़कर 1,55,400 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मंगलवार को इस पीली धातु का मूल्य 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम था। चांदी भी लगातार तीसरे कारोबारी दिन बढ़ी और यह 3,500 रुपये चढ़कर 2,54,500 रुपये प्रति किलो हो गई। एलकेपी सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई खत्म होने की खबरों पर बाजार ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी, जिससे सोने में तेजी दिखाई दी। (प्रेट्र)

बफर से तीन गुना ज्यादा है गेहूं-चावल का स्टाक

नई दिल्ली: एक अप्रैल तक भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में गेहूं और चावल का स्टाक बढ़कर 604.02 लाख टन हो गया। यह स्टाक 210.40 लाख टन के जरूरी बफर स्टाक से लगभग तीन गुना ज्यादा है। एक अप्रैल तक चावल का स्टाक 386.10 लाख टन था, जो 135.80 लाख टन के बफर मानक से काफी ज्याद है जबकि गेहूं का स्टाक 74.60 लाख टन के मुकाबले 217.92 लाख टन था। बफर मानक हर तीन महीने में बदले जाते हैं। मौजूदा आंकड़े एक अप्रैल से लागू होते हैं। अगले बदलाव एक जुलाई को होगा। (प्रेट्र)

एलएंडटी को जेएसडब्ल्यू स्टील से मिला बड़ा ठेका

नई दिल्ली: लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) को जेएसडब्ल्यू स्टील से 10,000 से 15,000 करोड़ रुपये के बीच का 'बड़ा' ठेका मिला है। जेएसडब्ल्यू 2031 तक अपनी कच्चे इस्पात प्रसंस्करण क्षमता को 3.5 करोड़ टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर पांच करोड़ टन प्रति वर्ष से अधिक करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। इसके अनुरूप, एलएंडटी को बेल्लारी और पारादीप स्थित जेएसडब्ल्यू के संयंत्रों में ब्लास्ट फर्नेस तथा स्टील मेल्ट शाप सहित महत्वपूर्ण प्रक्रिया सुविधाओं की इंजीनियरिंग, खरीद एवं स्थापना का काम सौंपा गया है। (प्रेट्र)

अमेरिका–ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल

संसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट

मुंबई, प्रेट्र: अमेरिका-ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत में प्रगति के दावे के बाद कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट से बुधवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। अंतिम घंटे में जोरदार खरीदारी से बीएसई के 30 शेयरों वाला संसेक्स 940.73 अंक यानी 1.22 प्रतिशत की छलांग के साथ 77,958.52 अंक पर पहुंच गया।

कारोबार के दौरान एक समय यह 1,004.99 अंक यानी 1.30 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78,022.78 अंक पर पहुंच गया था। वहीं, नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी 298.15 अंक यानी 1.24 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,330.95 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों के सकारात्मक रुख ने भी स्थानीय बाजार को समर्थन दिया। ग्लोबल आयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड आठ प्रतिशत गिरकर 101.1 डालर प्रति बैरल पर आ गया। संसेक्स की 30 कंपनियों में इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) सबसे ज्यादा फायदे में रही। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और पश्चिम एशिया संकट से प्रभावित विमानन कंपनियों के लिए क्रेडिट लाइन की कंपनियों के शेयर में 6.6 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई। ट्रेंट 3.91 प्रतिशत, एशियन पेंट्स 3.56 प्रतिशत, स्टेट बैंक आफ इंडिया 3.38 प्रतिशत, एचडीएफसी बैंक 3.11 प्रतिशत और इटरनल 2.98 प्रतिशत बढ़ा।

रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा 1.8 प्रतिशत गिरा। लार्सन एंड टूब्रो, पावर ग्रिड और एनटीपीसी भी पिछड़ने वालों में शामिल थे। संसेक्स मंगलवार को 251.61 अंक यानी 0.33 प्रतिशत की गिरावट के साथ 77,017.79 अंक पर बंद हुआ था, जबकि निफ्टी 86.50 अंक यानी 0.36 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,032.80 अंक पर रहा था। एशियाई बाजार की बात करें तो दक्षिण कोरिया का बेंचमार्क कास्पी, शंघाई एसएसई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स बढ़त के साथ बंद हुए। कास्पी छह प्रतिशत से ज्यादा चढ़ा।

940.73 पर बंद हुआ बीएसई का बेंचमार्क सूचकांक

298.15 अंक बढ़कर 24,330.95 पर बंद हुआ निफ्टी

निवेशकों की पूंजी छह लाख करोड़ रुपये बढ़ी

शेयर बाजार में तेजी से निवेशकों की पूंजी 5.99 लाख करोड़ रुपये बढ़ गई। इससे बीएसई की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) 5,99,107.83 करोड़ रुपये बढ़कर 4,72,80,559.98 करोड़ रुपये (4,970 अरब डालर) हो गया।

सेक्टरवार तेजी (प्रतिशत में)	
टेलिकम्युनिकेशन	2.94
सर्विसेज	2.89
पीएसयू बैंक	2.81
रियल्टी	2.76
बैंकेक्स	2.64
प्राइवेट बैंक इंडेक्स	2.51

शांति वार्ता को लेकर नई उम्मीद और ऊर्जा कीमतों में कमी ने बाजार की तेजी में उत्प्रेरक का काम किया। कारोबार के पहले हिस्से में बिकवाली का दबाव रहा जबकि दूसरे हिस्से में तेज खरीदारी हुई, जिससे सारे नुकसान लाभ में बदल गए और यह हरे निशान पर बंद हुआ। – **पोनमुडी आर**, सीईओ, एनरिच मनी

रुपया 69 पैसे चढ़कर 94.49 प्रति डालर पर

अमेरिका-ईरान में संभावित समझौते के संकेत के बाद क्रूड की कीमत 100 डालर प्रति बैरल के करीब पहुंचने से रुपया बुधवार को मजबूत हुआ और 69 पैसे चढ़कर 94.49 प्रति डालर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि रुपये पर पड़ रहे भारी दबाव को देखते हुए आरबीआइ मुद्रा को समर्थन देने के लिए सक्रिय रूप से एक 'अप्रत्यक्ष' रणनीति भी अपना रहा है। विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, डालर के मुकाबले 95 पर खुला। कारोबार के दौरान यह टूटकर 95.18 प्रति डालर के निचले स्तर पर पहुंच गया। अंततः यह 94.49 पर बंद हुआ जो पिछले बंद भाव से 69 पैसे की बढ़त है। रुपया मंगलवार को डालर के मुकाबले 95.18 पर बंद हुआ था।

सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर अप्रैल में पांच महीने के उच्च स्तर पर

नए आर्डर और उत्पादन में तेज वृद्धि से सेवा क्षेत्र को मिली मजबूती, पश्चिम एशिया में युद्ध ने विस्तार की गति प्रभावित की

नई दिल्ली, प्रेट्र: नए आर्डर और उत्पादन में तेज वृद्धि के चलते देश के सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर अप्रैल में बढ़कर पांच महीने के उच्च स्तर 58.8 पर पहुंच गई। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया सेवा पीएमआइ कारोबारी गतिविधि सूचकांक मार्च के 57.5 से बढ़कर अप्रैल में 58.8 हो गया जो पिछले नवंबर के बाद विस्तार की सबसे मजबूत दर को दर्शाता है।

सर्वे में शामिल प्रतिभागियों के अनुसार, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, ई-कामर्स और विशेष रूप से स्थानांतरण (रिलोकेशन) तथा लाजिस्टिक्स सेवाओं की मजबूत मांग ने बिक्री वृद्धि को बढ़ावा दिया। हालांकि, इस दौरान भारतीय सेवाओं की अंतरराष्ट्रीय मांग कमजोर पड़ी। कंपनियों ने संकेत दिया कि पश्चिम एशिया में युद्ध और कमजोर पर्यटन ने विस्तार की गति को प्रभावित किया। सेवा कंपनियों ने अपने परिचालन खर्चों में एक बार फिर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। अप्रैल में मुद्रास्फीति की दर में कमी आने के बावजूद, यह नवंबर 2024 के बाद से उच्चतम स्तरों में से एक बनी रही।

कंपनियों ने खाद्य पदार्थ, गैस तथा श्रम लागत और गैस की कमी का इसकी वजह बताया। इस बीच, एचएसबीसी इंडिया समग्र पीएमआइ उत्पादन सूचकांक 57.0 से बढ़कर 58.2 हो गया जो ऐतिहासिक रूप से मजबूत विस्तार दर का संकेत देता है।

मुद्रा लेनदेन से जुड़े संस्थानों के लिए नए मानक जारी

- अब 'मनी चेंजरों' के लिए नहीं जारी किए जाएंगे नए लाइसेंस
- नए लाइसेंस के लिए आवेदन तीन श्रेणियों में किया जा सकेगा

मुंबई, प्रेट्र: आरबीआइ ने विदेशी मुद्रा लेनदेन से जुड़े संस्थानों के लिए संशोधित मानक जारी करते हुए कहा है कि अब 'मनी चेंजरों' के लिए नए लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन विनियमन, 2026' के तहत यह बदलाव किया है।

आरबीआइ ने बुधवार को कहा कि नए ढांचे के तहत विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए सभी संस्थाओं को उसकी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही विदेशी मुद्रा की खरीद-बिक्री के लिए अधिकृत डीलरों की श्रेणियों और नियमों को भी संशोधित किया गया है। नए नियमों के तहत, नए लाइसेंस के लिए आवेदन तीन श्रेणियों में किया जा सकेगा। बैंकों को अधिकृत डीलर श्रेणी-1 के तहत आवेदन करना होगा। एनबीएफसी, पूरी तरह मनी चेंजर का काम करने वाले या दो वर्षों से काम कर रहे एवं दो वित्त वर्षों में औसतन 50 करोड़ रुपये का वार्षिक विदेशी मुद्रा कारोबार करने वाले संस्थान अधिकृत डीलर श्रेणी-2 के तहत आवेदन कर सकेंगे। वहीं, विदेशी मुद्रा से जुड़े नवाचार आधारित उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने वाली कुछ अन्य संस्थाओं को अधिकृत डीलर श्रेणी-3 में रखा गया है। आरबीआइ ने स्पष्ट किया कि पूरी तरह मनी चेंजर के रूप में काम करने का लाइसेंस पाने के लिए आवेदन पर विचार नहीं होगा।

बिजनेस से जुड़ी खबरों और अपडेट के लिए स्कैन करें या विजिट करें jagran.com

वस्तुओं, सेवाओं का निर्यात बीते वित्त वर्ष में 863 अरब डालर रहा

नई दिल्ली, प्रेट्र: वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद देश का वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात बीते वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 4.6 प्रतिशत बढ़कर 863.11 अरब डालर के अब तक के उच्चस्तर पर पहुंच गया है। 2024-25 में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात 825.26 अरब डॉलर रहा था। पिछले वित्त वर्ष में वस्तुओं का निर्यात 0.93 प्रतिशत बढ़कर 441.78 अरब डालर रहा, जो 2024-25 में 437.70 अरब डालर था।

बुधवार को वाणिज्य मंत्रालय ने निर्यात से जुड़े संशोधित आंकड़े जारी किए। एक अधिकारी ने कहा, 'वैश्विक अनिश्चितताओं और वस्तुओं के व्यापार में चुनौतियों के बावजूद भारत के वस्तु निर्यात में बढ़ोतरी हुई और इसने कुल निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान दिया।' हालांकि, सेवाओं के निर्यात क्षेत्र का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा।

ऊर्जा संकट से 6.6% रह जाएगी भारत की वृद्धि

- एसएंडपी ग्लोबल ने जीडीपी वृद्धि में इस गिरावट के लिए ऊर्जा आपूर्ति की समस्या को बताया प्रमुख कारण
- ऊर्जा संकट का असर सिर्फ तेल-गैस तक सीमित नहीं, माल ढुलाई और बीमा प्रीमियम भी महंगा हुआ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : एसएंडपी ग्लोबल ने कहा है कि अगर पश्चिम एशिया संकट जारी रहता है तो वर्ष 2026-27 में भारत की आर्थिक विकास दर घटकर 6.6 प्रतिशत रह सकती है। इससे पहले रेटिंग एजेंसी ने 7.1 प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया था। विकास दर में इस गिरावट के लिए ऊर्जा आपूर्ति की समस्या को प्रमुख कारण बताया गया है। साथ ही इसने भारत सरकार से यह भी कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित देश बनने के लक्ष्य के लिए ऊर्जा आपूर्ति की चुनौती का समाधान करना होगा।

पश्चिम एशिया संघर्ष से जो ऊर्जा संकट पैदा हुआ है उसका असर सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं है, बल्कि माल ढुलाई लागत, बीमा प्रीमियम, सप्लाई चेन और उर्वरक क्षेत्र तक फैल गया है। भारत की पश्चिम एशिया पर भारी निर्भरता इन जोखिमों को और बढ़ा रही है। इस क्षेत्र से भारत 45 से 50 प्रतिशत कच्चा तेल आयात करता है। इसके अलावा गैस, उर्वरक और कई औद्योगिक कच्चे माल की आपूर्ति भी मुख्य रूप से यहीं से होती है। पश्चिम एशिया भारत के कुल माल आयात का 22% और निर्यात का 13% हिस्सा रखता है।

तीन प्रमुख क्षेत्रों में प्राथमिकताएं तय करने की सलाह

विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एसएंडपी ग्लोबल ने भारत सरकार को तीन प्रमुख क्षेत्रों में तत्काल नीतिगत प्राथमिकताएं तय करने की सलाह दी है। रिपोर्ट के अनुसार, ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत को भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे ऊर्जा आपूर्ति को लेकर जारी अनिश्चितता के खतरे को कम किया जा सके। खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में घरेलू उर्वरक सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है, क्योंकि भारत विश्व में उर्वरक उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन मांग आपूर्ति से तेजी से आगे निकल रही है। आर्थिक सुधारों के तहत निरंतर संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता है ताकि व्यापार सुगम हो और भारत प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य बने।

'महत्वपूर्ण सूचकांक' निर्धारण के लिए सेबी ने पेश की गाइडलाइन

नई दिल्ली, प्रेट्र: सेबी ने महत्वपूर्ण सूचकांक के निर्धारण के मामले में मंगलवार को एक नई गाइडलाइन पेश की। इसके तहत किसी भी सूचकांक को उस समय 'महत्वपूर्ण सूचकांक' माना जाएगा, जब उसे ट्रैक करने वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं का दैनिक एयूएम पिछले छह महीनों में लगातार 20,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा हो।

बाजार नियामक ने स्पष्ट किया कि एक बार किसी सूचकांक को 'महत्वपूर्ण' श्रेणी में शामिल कर दिया गया तो वह इसमें बना रहेगा, जब तक कि उसका एयूएम लगातार तीन वर्षों तक निर्धारित सीमा से नीचे नहीं चला जाता। सेबी ने कहा कि सूचीबद्ध प्रतिभूतियों पर आधारित सूचकांक को तब 'महत्वपूर्ण सूचकांक' माना जाएगा जब वह म्यूचुअल फंड योजनाओं में छह महीने की अवधि में तय एयूएम मानदंड को पूरा करता है।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

हथियारों के प्रदर्शन में जदयू विधायक समेत नौ पर केस

गोपालगंज : बिहार में एक वीडियो प्रसारित होने के बाद बाहुबली जदयू विधायक अनंत सिंह समेत नौ के खिलाफ प्राथमिकी की गई है। मामला गोपालगंज जिले के सेमराव गांव में आयोजित उपनयन संस्कार के दौरान कार्यक्रम में हथियारों के खुलेआम प्रदर्शन व अश्लील नृत्य का है। मीरगंज थाने में पुलिस ने केस के साथ ही वीडियो की जांच भी शुरू कर दी है। (जासं)

फर्जी जाति के आधार पर नौकरी की तो नहीं मिलेगी पेंशन : कोर्ट

बिलासपुर: हाई कोर्ट ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए नौकरी करने वालों को स्पष्ट चेतावनी दी है। जस्टिस बीडी गुरु की अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि यह साबित होता है कि किसी कर्मचारी ने फर्जीवाड़े के जरिए नौकरी की है, तो उसे सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। हाल ही में हाई कोर्ट ने एक सेवानिवृत्त डिप्टी डायरेक्टर की याचिका को खारिज कर दिया। (नईदुनिया प्रतिनिधि)

भारतीय पर्यटक घर बैठे आनलाइन जमा करेंगे भंसार

पश्चिम चंपारण : भारतीय पर्यटकों को अब नेपाल की सीमा पर जाकर कस्टम कार्यालय में अपनी गाड़ी का भंसार (कस्टम ड्यूटी) जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। नेपाल सरकार ने भारतीय पर्यटकों की गाड़ी का शुल्क जमा करने के लिए आनलाइन सेवा शुरू कर दी है। त्रिवेणी भंसार कार्यालय के प्रभारी तुलसी राम चौधरी ने यह जानकारी दी है। (जासं)

तीन महीने में 2.1 करोड़ लोगों ने नया आधार एप डाउनलोड किया

नई दिल्ली: सरकार ने बताया कि नया आधार एप लोगों की ओर से तेजी से अपनाया जा रहा है। तीन महीने में यह 2.1 करोड़ ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। आइटी मंत्रालय ने कहा कि लोग एप का उपयोग सेवाओं का लाभ उठाने को कर रहे हैं, जिससे मोबाइल नंबर व पता को अपडेट करना आसान हो गया। (आइएएनएस)

उप्र एटीएस ने पाकिस्तान समर्थित दो और आतंकियों को बाराबंकी व कुशीनगर से पकड़ा

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने इंटरनेट मीडिया के जरिये संचालित एक बड़े आतंकी माड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए बाराबंकी और कुशीनगर से दो संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। आतंकियों की पहचान कुशीनगर निवासी 20 वर्षीय कृष्णा मिश्रा और बाराबंकी निवासी 23 वर्षीय दानियाल अशरफ के रूप में हुई है। एटीएस ने पांच मई को गोरखपुर से कृष्णा और छह मई को बाराबंकी से दानियाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों के खिलाफ एटीएस थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। एटीएस के अनुसार, दानियाल अशरफ के पास से एक देशी पिस्टल (9 एमएम), चार जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है। वहीं, कृष्णा मिश्रा के कब्जे से एक तमंचा (.315 बोर), दो जिंदा कारतूस और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। दोनों पाकिस्तान खुफिया एजेंसी आइएसआइ के इशारे पर काम कर रहे गैंगस्टर नेटवर्क के संपर्क में थे और संवेदनशील ठिकानों पर हमले की साजिश रच रहे थे।

एटीएस ने 23 अप्रैल को नोएडा से दो संदिग्ध आतंकी तुषार चौहान और समीर खान को गिरफ्तार किया था। दोनों से पाकिस्तानी गैंगस्टरों के लिए काम करने वाले कई युवकों की जानकारी मिली थी। आरोपितों ने बताया था पाकिस्तानी गैंगस्टर उत्तर प्रदेश में इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम के जरिये स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं। इसी इनपुट के आधार पर दोनों संदिग्ध आतंकियों को बाराबंकी व कुशीनगर से गिरफ्तार किया गया है। एटीएस के अनुसार, दोनों आरोपित इंस्टाग्राम समेत विभिन्न इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिये पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी, आबिद जट और हम्माद के संपर्क में आए। पाकिस्तानी गैंगस्टर ने इन्हें संवेदनशील स्थानों पर ग्रेनेड से हमले का लक्ष्य दिया था। एटीएस की टीम इस बात की भी जांच कर रही है कि इन गैंगस्टरों के तार हाल ही में पंजाब में हुए विस्फोट से जुड़े हैं या नहीं।

माड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही

एटीएस अधिकारियों का कहना है कि इस माड्यूल से जुड़े अन्य लोगों की पहचान कर गहन जांच की जा रही है, ताकि किसी भी संभावित आतंकी घटना को समय रहते रोका जा सके। एटीएस की टीम तुषार और समीर को नोएडा लेकर गई थी। वहां पर कई ठिकानों की छानबीन करने के बाद इन्हें बुधवार को जेल भेज दिया गया।

इरडा के डिजिटल पोर्टल से मिलेगी राहत, नहीं देना पड़ेगा कमीशन

प्रथम पृष्ठ से आगे

भारतीय बीमा और विकास प्राधिकरण (इरडा) के सूत्रों का कहना है कि उपभोक्ताओं की समस्याओं को हल करने के लिए इस वर्ष बीमा सुगम डिजिटल मार्केट प्लेस लांच किया जाएगा। इसकी तैयारी पिछले दो-तीन वर्षों से चल रही है।

इस डिजिटल प्लेटफार्म की शुरुआत मोटर इंश्योरेंस से होगी और कुछ महीनों बाद हेल्थ इंश्योरेंस को भी इसमें शामिल किया जाएगा। डिजिटल खरीदारी से एजेंट को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जिससे इंश्योरेंस की कीमत कम होगी। अभी इंश्योरेंस की खरीदारी के दौरान और हर साल दिए जाने वाले प्रीमियम में एजेंट का कमीशन भी शामिल होता है। इस कारण उपभोक्ताओं का प्रीमियम ज्यादा होता था, लेकिन कमीशन न लेने से इसमें कमी आएगी।

35 शिफ्ट में होगी सीयूईटी यूजी प्रवेश परीक्षा, 15.68 लाख विद्यार्थी हैं पंजीकृत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

- 11 से 31 मई तक चलेगी परीक्षा, छात्रों के लिए री-एलोकेशन विंडो खुली

कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी यूजी) 2026 इस बार आयोजकों के प्रबंधन की बड़ी परीक्षा होने वाली है। इस परीक्षा के लिए 15.68 लाख अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है, जो 12,906 विषय संयोजन को चुनेंगे। परीक्षा 35 शिफ्ट में 11 से 31 मई के बीच आयोजित की जाएगी, ताकि हर छात्र को उसके चुने गए विषयों के अनुसार स्लाट मिल सके।

इस बार सीयूईटी का स्वरूप पूरी तरह बहु-विषय आधारित हो गया है। एक छात्र अधिकतम पांच विषय चुन सकता है, जिस कारण परीक्षा को लचीला तो बनाया ही गया है, वहीं हर विषय के लिए अलग-अलग टेस्ट कराने की भी जरूरत पड़ रही है। सबसे बड़ी चुनौती विषय संयोजनों की है। 12,906 यूनिक काम्बिनेशन के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) को ऐसा टाइमटेबल तैयार करना पड़ा, जिसमें किसी भी छात्र के दो विषय एक ही शिफ्ट में न आएं। इसके लिए तकनीकी सिस्टम का सहारा लिया गया। केंद्रों का आवंटन भी इस बार परीक्षा का अहम पहलू बनकर उभरा है। एनटीए के अनुसार 79 प्रतिशत छात्रों को उनकी पहली पसंद का शहर मिला, जबकि 96.6 प्रतिशत को उनके चुने गए शहरों में से ही एक केंद्र दिया गया है। हालांकि, करीब 3.4 प्रतिशत अभ्यर्थियों को दूसरे शहरों में जाना पड़ा है। इसके पीछे सीमित केंद्र, अधिक भीड़ और विषय व शिफ्ट का टकराव होना जैसे कारण रहे हैं। एनटीए ने री-एलोकेशन विंडो शुरू की है, ताकि जिन छात्रों को मनचाहा शहर नहीं मिला है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उपलब्ध सीटों के आधार पर केंद्र बदल सकते हैं।

यूपी में 'एक जिला एक व्यंजन' की सूची में मांसाहारी स्वाद शामिल नहीं

राज्य ब्यूरो, जागरण • लखनऊ

- एमएसएमई मंत्री ने कहा, अभी और व्यंजनों को किया जाना है शामिल
- यूपी के कई जिलों के मांसाहारी व्यंजनों की भी है अलग पहचान

उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 'एक जिला एक व्यंजन' (ओडीओसी) योजना की सूची में मांसाहारी व्यंजनों को फिलहाल शामिल नहीं किया जा रहा है। एमएसएमई मंत्री राकेश सचान का कहना है कि पहले चरण में जिला स्तरीय समिति द्वारा चयनित व्यंजनों को ही शामिल किया गया है। बाद में अन्य व्यंजनों को शामिल किया जाएगा।

एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर बीती 24 जनवरी को शुरू की गई एक जिला एक व्यंजन योजना की सूची में मांसाहारी व्यंजनों को शामिल न किए जाने को लेकर बहस छिड़ गई है। प्रदेश की खानपान संस्कृति में खास पहचान रखने वाले लखनऊ के गलावटी कबाब, अवधी बिरयानी और नहारी जैसे विश्वप्रसिद्ध व्यंजन सूची से बाहर हैं। इसी तरह रामपुर के मटन कोरमा और सीक कबाब, बरेली का मटन पकवान भी शामिल नहीं है। इस बाबत कुजीन सोसायटी आफ इंडिया के अध्यक्ष और फूड हिस्टोरियन पुष्पेश पंत ने इस पहल को अधूरा करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम चयनात्मक प्रतीत होता है। मांसाहारी व्यंजनों की अनदेखी उचित नहीं है। दूसरी ओर, सूची में प्रदेश के कई शाकाहारी और मिठाई आधारित व्यंजनों को प्रमुखता दी गई है। आगरा का पेठा और दालमोठ, मथुरा का पेड़ा व खुरचन, अयोध्या की कचौड़ी, मेरठ की रेवड़ी-गजक, बाराणसी की ठंडाई, लस्सी और बनारसी पान, जौनपुर की इमरती, मऊ का लिट्टी-चोखा जैसे व्यंजन सूची में शामिल हैं।

भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट रात्रि में आवाजाही पर रोक

जासं, जयपुर : भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में तीन किलोमीटर क्षेत्र में रात्रि के समय आवाजाही पर रोक लगाई गई है। अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़, घड़साना, रायसिंहनगर, पदमपुर और श्रीकरणपुर उपखंडों से लगती सीमा से तीन किलोमीटर क्षेत्र में शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक किसी भी व्यक्ति का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।

जिला कलक्टर अमित यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। किसानों को खेती के लिए बीएसएफ के बार्डर पोस्ट अधिकारियों अथवा सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर खेत तक जाने की अनुमति दी जा सकेगी। सूत्रों के अनुसार भीषण गर्मी और धूलभरी हवाओं के बीच पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए यह आदेश जारी किए गए हैं।

खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

- कोर्ट ने सुनाया है फैसला-खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की शक्ति राज्यों के पास

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार द्वारा क्यूरेटिव पिटीशन लंबित होने की बात कहे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति से संबंधित याचिकाओं पर 20 मई को विचार करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जुलाई, 2024 के नौ न्यायाधीशों की पीठ के उस फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध करने वाली याचिकाओं को सितंबर 2024 में खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी शक्ति राज्यों के पास है।

नौ जजों की पीठ ने 8:1 के बहुमत से दिए गए फैसले में कहा था कि संसद के पास संविधान की सूची 1 की प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने की विधायी क्षमता नहीं है। पुनर्विचार याचिकाएं खारिज होने के बाद केंद्र ने शीर्ष अदालत में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की थी। सालिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बुधवार को जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की पीठ से मामले को स्थगित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा दायर क्यूरेटिव पिटीशन लंबित है। इस मामले में पेश हुए कुछ वकीलों ने मेहता की दलील का समर्थन किया और कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला आने के बाद ही अन्य अपीलों पर सुनवाई की जानी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट। फाइल

होशियारपुर में आठ वर्षीय बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोचकर मार डाला

जागरण संवाददाता, होशियारपुर : पंजाब के होशियारपुर के गांव खर्ल खुर्द में बुधवार को आठ साल की बच्ची को आवारा कुत्तों ने नोचकर मार डाला। मृतक बच्ची की पहचान सलोनी के रूप में हुई।

मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले प्यारे लाल ने बताया कि उनकी बेटी सलोनी तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। सुबह करीब 8:30 बजे वह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। इस दौरान वह शौच के लिए खेत में चली गई। जब वह काफी समय तक घर नहीं लौटी तो वह उसे तलाश करते हुए खेत की तरफ गए। जब वह कुछ दूरी पर पहुंचे तो सलोनी खून से लथपथ हालत में खेत में गिरी हुई थी और आवारा कुत्ते उसे नोच रहे थे। उन्होंने कुत्तों को भगाया और बच्ची को उठाकर घर लाए। इसके बाद वह सलोनी को सरकारी अस्पताल टांडा में लेकर पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।